



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2013/फाल्गुन 9, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013/PHALGUNA 9, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण., आस्ट्रेलिया, रूस और थाइलैंड के मूल के या वहाँ से निर्यातित “रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले कार्बन ब्लैक” के आयातों के बारे में मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) पाटनरोधी जांच।

सं. 15/41/2010-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि :

1. यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण., आस्ट्रेलिया, रूस और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित “रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले कार्बन ब्लैक” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/21/2008-डी जी ए डी के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। केन्द्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 6/2010-सी.शु. के तहत लगाया गया था।

2. यतः मैं 0 आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसो. (ए टी एम ए), जिसे आगे आवेदक कहा गया है, ने संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं की ओर से मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक ने नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया और यह दावा किया कि मूल जांच के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान भारी परिवर्तन हुआ है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की आगे जरूरत नहीं रह गई है।

ख जांच की शुरूआत

3. अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 23 में यह अपेक्षा की गई है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ खुद की पहल पर अथवा ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उचित अवधि बीत जाने पर किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें परिवर्तन किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए आगे इसकी जरूरत नहीं है।

4. आवेदक द्वारा ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए और लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बताते हुए परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 15/41/2010-डी जी ए डी के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित 24 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/21/2008-डी जी ए डी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की संबद्ध मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की और केन्द्र सरकार ने 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 6/2010-सी. शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।

ग. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- प्राधिकारी ने 30 अगस्त, 2011 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों एवं घरेलू उत्पादकों को भेजी। ज्ञात हितबद्ध

पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर करें और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समयावधि में संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को उत्तर देने की सलाह दें।

- ii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात आयातकों, घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई गई थी।
- iii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत संबंधी सार्वजनिक सूचना की प्रति संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

आस्ट्रेलिया में कार्बन ब्लैक के उत्पादक/निर्यातक

1. मै. कॉन्टीरेंटल कार्बन आस्ट्रेलिया पीटीवाई लि.

सर जोसेप बैंड ड्राइव

कुरनैल एनएसडब्ल्यू 2231, आस्ट्रेलिया

फोन: 9668 9177

2. कैबोट आस्ट्रेलिया पीटीवाई लि.,

पो.बॉ. 829, टर्की,

विक्टोरिया 3228,

आस्ट्रेलिया

चीन जन.गण. में कार्बन ब्लैक के उत्पादक / निर्यातक

1. हेबैईजिंग कन्ट्री जिनयुआन रबड़ कैमिकल कं. लि. शेघली रोड गुआंगशा डिस्ट्रिक 31-1-101, हैंगसुई सिटी हेबैई प्रोविन्स, चीन.जन.गण.
2. हेबैई योंगहुई कैमिकल इंडस्ट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि., नं. 199, जिनहुआ रोड, शिजियाजहुआंग, हेबैई, चीन.जन.गण.-311101
3. लाइवू ताइशा कार्बन ब्लैक कंपनी लि., गाओसुआंग इंडस्ट्रियल जॉन, लाइचेंग, लाइवू चीन.जन.गण.-271122
4. कीचैंग कैमिकल कंपनी लि., बेचेनवैंग, टेन्जिइन काउंटी, एनीएंग सिटी, हेनन प्रोविंस, चीन.जन.गण.
5. जिआनजिन डोल्फिन कार्बन ब्लैक लि., ईस्ट ऑफ रेलवे, नॉर्थ ऑफ चिन्हेक्यों बेचेन डिस्ट्रिक, तिआनजिन, चीन जन.गण. 300400
6. एमआईएस हेबैई डागुआंगमिंग जुवुबा कार्बन ब्लैक कं. लि., साउथ ऑफ डोंगुआन रोड, शाहे सिटी, हेबैई प्रोविंस, चीन - 054100

फोन: 86-319-8707022

7. एमआईएस जियांगस ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक कंपनी लि0 ("ब्लैक कैट") जियाओ जिंगडनेजैंग सिटी, जियांगसी प्रोविंस, चीन0जन0गण0- 333000

फोन: 86-798 839 9126

8. सुझोऊ बोआहुआ कार्बन, जुशुगुआन सुझोऊ, चीन-215151

फोन: 0086-512-653

9. एमआईएस निंगबो डेटाई कैमिकल कं. लि., नं0 699, फेंगजियांग रोड, निंगबो कैमिकल इंडस्ट्री जोन, (जेइपु, झेंघाई) निंगबो सिटी, जेझियांग प्रोविंस, चीन

एमआईएस लोंगजिंग कैमिकल स्टॉक कं. लि0, नं0 1, लोंगजिंग स्ट्रीट, डोंगहुआन रोड, शाहे सिटी, हेबैई, चीन

फोन: 86- 3198869003

एमआईएस निंगबो शीन— ऑल केमिकल कंपनी लिमिटेड, जिनजिंगजियांग बिल्डिंग, नं 419, लिंगकिवाओ रोड, निंगबो सिटी, पीआरसी-315000

फोन: 86-574-87255359

10. चाइना रबड इंडस्ट्री एसोसिएशन, नॉर्थ यिन्हे ब्रिज, बेईचैंगदू, तियानजिन-300400

चीन फोन: 86-22-27276558

मै 0 जिन्नेंग साइंस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, नं. 1, जिन्नेंग स्ट्रीट, यिवहे, शेंगडॉग, चीन

चाइना रबड ग्रुप कार्बन ब्लैक रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, नं 568, हुईजियांग रोड, हुईडॉग डिस्ट्रिक, जिंगोंग सिटी, सिचुआन, चीन 0 जन 0 गण 0

रूस में कार्बन ब्लैक के उत्पादक/निर्यातक

1. ओमस्कटेचुगलेरोड ओजेएससी,

644049, बाराबिन्सक्या स्ट्रीट, 20,

ओमस्क, रूस

फोन: (3812) 42-02-63

2. एमआईएस यारोस्लेवस्की टेक्नीचेकिये अगलेरोड यारोस्लावी , 150000,

रूस

एमआईएस ट्राइगन गल्फ एफजैडसीओ, नं 0 एम ओ 0743, जाफजा, पो 0 ओ 0 बाक्स 61468, दुबई, यूएई

फोन: 971 48819337

3. अमटेल होल्डिंग कंपनी, अमटेल हाउस-45, कुटुजोवस्क, एमटेल होल्डिंग कंपनी, एमटेल हाउस 45, कुटुजोवास्क, प्रोस्पेलक्ट, 121170 मॉस्को, रूस

सेवरगाजप्रोम, 39/2 लेनिन स्ट्रीट उखटाकोमी, रिपब्लिक ऑफ रसियन फेडरेशन,

4. निजनेकामस्क कार्बन ब्लैक प्लांट

423570 निजमेकामस्क, प्रोमबाजा, रिपब्लिक ऑफ टारस्टान,

थाइलैंड में कार्बन ब्लैक के उत्पादक / निर्यातक

1. थाई कार्बन ब्लैक, 44, मोल, अयुथ्या—एंगथोंग हाईवे, थामबोलपासा, एमफुरमुआंग, एंगथांग 14000
2. थाई टोकाई कार्बन प्रोडक्ट कं0, लि0, ७वीं मंजिल, हरेस्थोन टॉवर, ५४ नार्थ सदर्न रोड, सिलोम बैंगरेक, बंगकोक— १०५००, थाइलैंड
3. ब्रिडगेस्टोन कार्बन ब्लैक (थाइलैंड) कं0, लि0, रोजाना इंडस्ट्रिय पार्क, बन खाई डिस्ट्रिक, रेयोंग प्रोविन्स,

iv) संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर प्रतिक्रिया व्यक्त की है:

क्र०सं०	उत्पादक/निर्यातक का नाम	देश
1.	मै0 जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक, लि0, जिंगडेझेन, चीन0जन0गण0	चीन जन0 गण0
2.	मै0 जिनेंग साईस एंड टेक्नोलॉजी कं0 लि0 चीन जन0 गण0	चीन जन0 गण0
3.	मै0 शंघाई ह्यून टोंग इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं0 लि0 चीन0 जन0 गण0	चीन जन0 गण0
4.	मै0 सुझोऊ कार्बल ब्लैक कं0 लि0, चीन जन0 गण0	चीन जन0 गण0
5.	मै0 यारोस्लेवस्की टेक्नीचेस्की अगलेरोड, रूस	रूस
6.	मै0 ट्राइगन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई	यूएई

- v) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं। :

1	मै0 अपोलो टायर्स लि0, अपोलो हाऊस 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुडगांव - 122001 (हरियाणा)
2	मै0 जे0 के0 टायर्स इंडस्ट्रीज लि0, लिंक हाऊस, 3 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- - 110 002
5	मै0 गुडइयर साउथ टायर्स प्रा0 लि0 , एच-18, एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, वालुज, औरंगाबाद,
4	मै0 गुडइयर इंडिया लि0, मथुरा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा- 121004
5	मै0 केबोट इंडिया लि0, एनकेएम इंटरनेशनल हाऊस, 178, बैकबे रिकलेमेशन, बाबूभाई चेन्नई मार्ग, मुंबई- 400020
6	मै0 जनरल रबर्स पी जोन जैकहरियाह विलिंग्स, कोट्टायम-686001, केरल
7	आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए), पी एच डी हाउस, (चौथी मंजिल), एशियन गेम्स विलेज के सामने, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016
8	ऑल इंडिया रबड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 1009, पदमा टावर्स, 15, राजेन्द्रा पैलेस, नई दिल्ली 10008
9	मै0 जेम पॉली टैक इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0, गार्डन लेन, बेलियाघाटा, कोलकाता - 700010, पं0 बंगाल

- vi) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

(क) मै0 सिएट लि0

(ख) मै0 जे0 के0 टायर एंड इंड. लि0

(ग) मै0 अपोलो टायर्स लि0

vii) आवश्यक सूचना और उत्तर हेतु भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं ।

1. एसोसिएशन ऑफ कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स, 5 ए, राबा कैलाश,
55/4, बेलीगुंगी सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019

2. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि0, 31, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

हाई टैक कार्बन, मर्धवा इंडस्ट्रियल एरिया, पो. ओ. रेनूकूट,
जिला-सोनभद्रा (उ0प्र0) 231217

3. कॉन्टीनेटल कार्बल इंडिया लि., ए-14, इंडस्ट्रियल एरिया नं0 1,
साउथ साइड ऑफ जी टी रोड, गाजियाबाद-201001

4. मै0 केबोट इंडिया लि0, एनकेएम इंटरनेशनल हाऊस, 178, बैंकबे
रिक्लेमेशन, बाबूभाई चिनई मार्ग, मुंबई- 400020

viii) संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग माने गए संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों मै0 फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि0 और मै0 हाईटैक कार्बन ने क्षति संबंधी सूचना/आंकड़ों के साथ उत्तर/अनुरोध दायर किए हैं ।

ix) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच से संगत सूचना प्रदान नहीं की है अथवा प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है ।

x) जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयात के ब्यौरों की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे । घरेलू

उद्योग ने आई बी आई एस के आंकड़ों (गौण स्रोत) के आधार पर आयातों से संबंधित सूचना प्रदान की। तथापि, प्राधिकारी ने आयात मात्रा की गणना करने और अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया।

- xi) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध—III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
- xii) यह जांच 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी। तथापि, क्षति जांच वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 की अवधि और जांच अवधि के लिए की गई थी। संभावना संबंधी विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से जांचोत्तर अवधि (1 अप्रैल, 2011 से 30 सितंबर, 2011 तक) के लिए संगत सूचना/आंकड़े भी मांगे थे।
- xiii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 20 अप्रैल, 2012 और 30 अक्टूबर, 2012 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने दोनों मौखिक सुनवाइयों में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद उत्तर संबंधी अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था।
- xiv) जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में जहां संगत पाया गया है, विचार किया है। घरेलू उद्योग और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने जहां अपेक्षित हुआ है, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया

था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

- xvi) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों का प्रकटन 22 फरवरी, 2013 को जारी प्रकटन विवरण के तहत सभी हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी ने संभव समझी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया है।
- xvii) वर्तमान जांच के दौरान जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण दर्ज किया है।
- xviii) सक्षम प्राधिकारी ने संबद्ध जांच पूरी करने की समयावधि बढ़ाकर 28.02.2013 कर दी है।
- xix) *** यह चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का घोतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।
- xx) प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में जांच अवधि के दौरान प्रचलित 1 एमडा० = 46. 18 रुपए की औसत विनिमय दर अपनाई गई है।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु:

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद “रबड़ अनुप्रयोग में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक” था। मूल जांच में उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

“5” विचाराधीन उत्पाद “रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक” है। यह एक अकार्बनिक रसायन है जिसे (टायर रहित) के उत्पाद/प्रक्रिया में सुदृढ़कारी पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक को एसीटिलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक और नोइर डे कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों में कांटा जा सकता है। रबड़ कार्बन ब्लैक एप्लीकेशन और गैर-रबड़ कार्बन ब्लैक एप्लीकेशन। रबड़ एप्लीकेशन में कार्बन ब्लैक एक ऐसा कार्बन ब्लैक है जिसे रबड़ (टायरों सहित) के उत्पादन/प्रक्रिया में सुदृढ़कारी प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में किया गया अन्वेषण रबड़ एप्लीकेशन में प्रयुक्त कार्बन

ब्लैक जैसे कॉपियरों और कंप्यूटर के प्रिंटर कार्टिज्स, पेन्ट्स, केयोन्स और पॉलिशों में स्थाहियों, वर्तमान में किए गए अन्वेषण के दायरे में नहीं है ।

6. संबद्ध वस्तु अधिनियम के अध्याय 28 की उपशीर्ष सं. 28030010 के अंतर्गत आती है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है ।"
7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है । आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनके पास विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई मुददा नहीं है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में है ।

उ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

याचिकाकर्ता (ए टी एम ए), निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र के बारे में आवेदक (ए टी ए ए), निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मूल जांच में घरेलू उद्योग के घटकों में से एक घटक मै0 हाईटैक कार्बन थाइलैंड से संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक तथा निर्यातक अर्थात् मै0 थाई कार्बन ब्लैक कंपनी लि0 से संबद्ध है । जांच अवधि के दौरान उक्त संबद्ध उत्पादक/निर्यातक ने भारत को भारी मात्रा में निर्यात किया था और प्रश्नावली का उत्तर भी दायर नहीं किया । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हाईटैक कार्बन घरेलू उद्योग बनने की पात्र नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के स्तर का निर्धारण फिलिप्प कार्बन ब्लैक के निष्पादन के आधार पर ही किया जाना चाहिए ।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास संबद्ध देश के संबद्ध उत्पादक/निर्यातक हाईटैक कार्बन को नियमानुसार घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति देने का कोई विवेकाधिकार नहीं है ।

- iii. घरेलू उद्योग का यह तर्क निराधार है कि ए टी एम ए ने मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया है जिसमें हाईटैक को पहले ही घरेलू उद्योग माना गया है। हाईटैक के ब्यौरे देते हुए कोई याचिका दायर करने का तात्पर्य यह नहीं है कि ए टी एम ए यह मानता है कि हाईटैक घरेलू उद्योग का एक भाग है।
- iv. घरेलू उद्योग ने एक अन्य निराधार अनुरोध यह किया है कि ए टी एम ए ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसने उसके सदस्यों द्वारा किए गए शुल्क मुक्त आयातों के बारे में सूचना प्रकटित नहीं की है। अनुरोध है कि कुछ सदस्यों ने जांच की शुरूआत के उत्तर में आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इसके अलावा, डी जी ए डी से एक पत्र प्राप्त होने के बाद अधिकांश सदस्यों ने डी जी ए डी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान की है। अतः तथ्यों का कोई छिपाव नहीं किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है।
- v. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चूंकि संबद्ध निर्यातक से आयात शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को अलग नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः डी जी ए डी को समस्त संबद्ध देशों से अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों को अलग रखना चाहिए और उसके बाद ही क्षति तथा क्षति के खतरे का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- vi. फिलिप्प कार्बन ब्लैक लिंग (पी सी बी एल) और सिएट लिंग की वैबसाइटों से यह स्पष्ट होता है कि पी सी बी एल का एक निदेशक संबद्ध देशों से संबद्ध वर्तु के एक आयातक सिएट लिंग का प्रबंध निदेशक है। अतः पी सी बी एल को भी घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने की जरूरत है।
- vii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के अनुसार हाईटैक कार्बन और मैंगनियम फिलिप्प कार्बन ब्लैक लिंग को संबद्ध वर्तु के घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे उस कच्ची सामग्री जिसका भारत में मुख्यतः आयात तीसरे देश से किया जाता है, में मात्र 15 प्रतिशत का ही मूल्यवर्धन करते हैं।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

9. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) पी सी बी एल और सिएट में सामान्य निदेशक ने संगत अवधि के दौरान बोर्ड की कोई बैठक में भाग नहीं लिया है और इस प्रकार इसे नियम 2(ख) के अनुसार उनके संबंध के जरिए प्रभावित नहीं माना जा सकता है।

- (ख) हाईटैक कार्बन को (i) मूल जांच के समय प्राधिकारी के इस बारे में विगत निर्णय, (ii) संबद्ध उत्पादकों द्वारा निर्यातकों की कम मात्रा, (iii) भारत में कंपनी का उत्पादन काफी अधिक होना, (iv) कंपनी का ध्यान आयातों के बजाए घरेलू उत्पादन पर केन्द्रित होने को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से उसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए निर्यातों के बावजूद एक पात्र घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए ।
- (ग) प्रतिवादी घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा भाग बनता है; घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का स्पष्ट समर्थन किया जा रहा है ।
- (घ) मात्र इस तथ्य कि उत्पाद के एक या अधिक घरेलू उत्पादकों ने उक्त उत्पाद का स्वयं आयात किया है, का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं होना चाहिए ।
- (ङ.) याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है कि टी सी वी द्वारा थाइलैंड से किए गए आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत हुए थे । जांच अवधि के दौरान टी सी वी द्वारा भारत को किए गए कार्बन ब्लैक के कुल निर्यातों में से केवल ***% शुल्क प्रदत्त हैं और टी सी वी द्वारा किए गए शेष सभी निर्यात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत हैं । चूंकि ये आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं, इसलिए इससे हाईटैक घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किए जाने का अपात्र नहीं बन जाता है ।
- (च) माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय ने निर्मा लिलो बनाम सेंट गोवेन ग्लास इंडिया लिलो के मामले में यह निर्णय लिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास नियम 2(ख) और 27 फरवरी, 2010 के संशोधन के अंतर्गत विवेकाधिकार से निर्दिष्ट प्राधिकारी का विवेकाधिकार समाप्त नहीं हुआ है ।
- (छ) मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हाईटैक कार्बन पात्र घरेलू उद्योग है । विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने मूल जांच के समय और उसके बाद इसे चुनौती नहीं दी है ।
- (ज) आवेदकों ने हाईटैक कार्बन को घरेलू उद्योग मानते हुए मध्यावधिक समीक्षा की शुरुआत हेतु आवेदन दायर किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अब अपना मत बदल दिया है और अब वह यह कह रहा है कि हाईटैक एक पात्र घरेलू उद्योग नहीं है । यदि आवेदक के तर्क पर विचार किया जाता है तो घरेलू

उद्योग द्वारा बेहतर निष्पादन (जिसमें हाईटैक शामिल है) के दावे के साथ-साथ उनके आवेदन का समूचा आधार ही स्वीकार्य नहीं रह जाता है और इसलिए समूची जांच दोषपूर्ण और किसी तथ्यात्मक आधा से रहित है।

- (झ) संबद्ध पक्षकार से निर्यातों की मात्रा कुल भारतीय उत्पादन और मांग में कमशः मात्र ***% और ***% है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात अत्यधिक हैं।
- (ट) हाईटैक कार्बन भारत में कार्बन ब्लैक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका घरेलू बाजार के हिस्से में लगभग ***% है। कंपनी का फोकस घरेलू उत्पादन पर है।
- (ठ) प्रतिवादी कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- (ड) घरेलू उद्योग के दायरे से संबद्ध घरेलू उत्पादक को स्वतः अलग नहीं किया जाता है। उल्लू टी ओ के विभिन्न सदस्यों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध घरेलू उत्पादकों की पात्रता निर्धारित की है।
- (ढ) याचिकाकर्ता ने थाई कार्बन द्वारा किए गए निर्यातों की तुलना थाइलैंड से हुए कुल निर्यातों अथवा हाईटैक कार्बन के उत्पादन के साथ की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी या अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा इन दोनों में से किसी मापदंड को नहीं अपनाया जाता है। इसके विपरीत इस संबंध में स्थापित पद्धति यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में ऐसे आयातों पर विचार करते हैं।
- (ण) घरेलू उद्योग के बार-बार तर्कों के बावजूद याचिकाकर्ता ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसके सदस्यों द्वारा अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत आयात किए गए हैं। इस प्रकार ऐसे आयातों से केवल उत्पादन संबंधी प्रयास में सहायता मिलती है और न कि इससे हाईटैक कार्बन के उत्पादन प्रयासों का स्थानापन्न होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी और जांच प्राधिकारियों की यह स्थापित परंपरा है कि उत्पादन प्रयासों की सहायता हेतु किए गए आयातों पर ऐसी कंपनी को अपात्र मानने के पर्याप्त कारण के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- (त) जांचोत्तर अवधि में थाइलैंड से हुए आयातों में भारी गिरावट आई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :

वर्ष	थाइलैंड से आयात (मी०ट०)
2008-09	***
2009-10	***
2010-11	***
ति. 1 2011-12	***
ति. 2 2011-12	***
ति. 3 2011-12	***

- (थ) वर्तमान मामले में ए टी ए म ए द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त उपभोक्ता ही ऐसे हैं जो विभिन्न स्रोतों से शुल्क मुक्त आयात कर रहे हैं। वे घरेलू उद्योग को उसकी बिक्री कीमत घटा शुल्क लाभ के समतुल्य कीमत (अधिकतम स्तर जिसे घरेलू उद्योग ऐसी स्थितियों में कर सकता है) देने के अनिच्छुक हैं। इस प्रकार बाजार का यह खंड पाटनरोधी शुल्क लागाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार ने ऐसे आयातों को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान छूट प्रदान की है। यदि ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया होता तो इस बाजार की जरूरत की पूर्ति हो गई होती और उपभोक्ताओं ने उत्पाद का आयात नहीं किया होता।
- (द) संबद्ध कंपनियों के प्रचालनों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा कोई सांविधिक या संगठनात्मक प्रतिबंध नहीं : यदि दोनों संबद्ध कंपनियां अपनी व्यापार योजनाएं परिभाषित और उनका पालन करते समय स्वायत्त रूप से कार्य कर रही हैं और यदि संबंध से व्यवहार पर प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही संबद्ध उत्पाद के बारे में संदर्भाधीन घरेलू उत्पादक की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में विकृति नहीं आती है, तो उत्पादक को नियम 2(ख) के अंतर्गत अलग नहीं रखा जा सकता।
- (ध) संबद्ध उत्पादक प्रतिस्पर्धा में प्रचालन कर रहे हैं और उनके हित विरोधाभासी हैं : यदि दोनों कंपनियों यद्यपि, वे संबद्ध हैं, के हित पाटनरोधी उपाय लागाए जाने के बारे में विरोधाभासी हैं, तो ऐसे संबद्ध घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

(न) क्या संबद्ध पक्षकारों का व्यवहार असंबद्ध पक्षकारों की तुलना में विशिष्ट तथा अलग है : जांच प्राधिकारी संबद्ध पक्षकारों के व्यवहार पर विचार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या इससे असंबद्ध पक्षकारों की तुलना में विशिष्ट या अलग व्यवहार का पता चलता है ? इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं :

क. घरेलू देश में उत्पाद के अलग—अलग विनिर्माताओं के बीच कंपनी की स्थिति;

ख. क्या कंपनी का फोकस घरेलू उत्पादन पर है;

ग. संबद्ध कंपनी पर पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने का प्रभाव;

घ. अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ संबद्ध उत्पादक की क्षति सूचना की प्रवृत्ति

(प) क्या संबद्ध उत्पादकों द्वारा संदर्भाधीन उत्पाद के निर्यातों से घरेलू उद्योग को लाभ मिलता है या पाटन के प्रभावों से उसका संरक्षण होता है । यदि किसी घरेलू उत्पादक ने उक्त संबद्ध पक्षकार द्वारा निर्यातों का सहारा लेकर पाटन के प्रभाव से स्वयं का बचाव किया है तो कंपनी को अलग रखा जाना चाहिए और यदि किसी घरेलू उत्पादक ने पाटन के व्यवहार में किसी भी रूप में भाग लिया है, अथवा उससे अन्यथा अनुचित लाभ प्राप्त किया है तो उसे अलग रखा जाए ।

(ब) क्षति विश्लेषण पर प्रभाव— जहाँ संबद्ध पक्षकारों को बाहर रखे जाने से घरेलू उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़ों में अनुचित रूप से कमी रहेगी, वहाँ उसे शामिल किया जाना चाहिए और यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल किए जाने से क्षति संबंधी जांच परिणाम में विकृति आएगी, वहाँ उसे अलग रखा जाना चाहिए ।

(भ) संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यात : संबद्ध पक्षकार होने के अलावा, किसी मामला विशेष में संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों, यदि कोई हो, के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी संगत होता है । क्या ऐसे संबद्ध पक्षकार ने उक्त अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था, यदि हाँ, तो क्षति के दावे पर उसका प्रभाव क्या है ? यदि नहीं, तो क्या उसे बाहर रखे जाने को अभी भी न्यायोचित ठहराते हुए कोई अन्य आधार है । यदि संबद्ध पक्षकार ने संबद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है, तो निम्नलिखित का मूल्यांकन करने की भी जरूरत है :

i. ऐसे संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा;

- ii. संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों का प्रयोजन;
- iii. क्या यह प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों के कारण हुई थी;
- iv. क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक का सामान्य जोर संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर था अथवा क्या उक्त सामान्य जोर धीरे-धीरे और निरंतर रूप से आयातों की ओर मुड़ गया;
- v. ऐसा कोई अन्य तथ्य जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कार्यवाही के दौरान प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया हो ।

(भ) वर्तमान मामले में हाईटैक कार्बन और टी सी बी को सरसरी तौर पर संबद्ध पक्षकार कहा जा सकता है परंतु पाटनरोधी नियमों के प्रयोजनार्थ वे संबद्ध पक्षकार इसलिए नहीं हैं क्योंकि (क) उनमें से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखता है; (ख) उनमें से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है; और (ग) वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्षकार को नियंत्रित नहीं करते हैं । यह मानते हुए यद्यपि, उसे स्वीकार न करते हुए कि दोनों कंपनियां संबद्ध हैं, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि नियमों में उपर्युक्तानुसार विवेकाधिकार का प्रावधान है और उक्त विवेकाधिकार निम्नलिखित कारण की वजह से घरेलू उद्योग के रूप में कंपनी को शामिल करने के पक्ष में होना चाहिए ।

- i. हाईटैक कार्बन ने संबद्ध देशों के किसी संबद्ध निर्यातक से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है ।
- ii. हाईटैक कार्बन आदित्य बिड़ला नूवो लि�0 (ए बी एन एल) की एक व्यापार शाखा है और यह कार्बन ब्लैक का व्यापार करती है ।
- iii. आदित्य बिड़ला नूवो लि�0 और थाई कार्बन (टी सी बी) दो पृथक सूचीबद्ध नैगमिक सत्ताएं हैं और इनमें से एक का दूसरे में कोई शेयर नहीं है । ये संबंधित शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित हैं ।
- iv. दो निदेशक ऐसे हैं, जो दोनों कंपनियों के बोर्ड में साझा हैं और यह हैं श्री कुमार मंगलम बिड़ला और श्रीमती राजश्री बिड़ला । तथापि, ये दोनों गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और ये अपनी अलग-अलग क्षमता में बोर्ड में शामिल हुए हैं । यह भी नोट करना संगत है कि ए बी एन एल और टी सी बी के निदेशक मंडल में कमशः 11 और 12 निदेशक शामिल हैं और इन

दोनों निदेशकों में से कोई भी निदेशक नहीं किया है अथवा किसी वीटो अधिकार का प्रयोग नहीं किया है ।

- v. अपनी व्यापार योजनाओं को आगे बढ़ाने में व्यापारिक निर्णय लेते समय दोनों कंपनियां स्वायत्त रूप से कार्य करती हैं ।
- vi. दोनों कंपनियां भारतीय बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में कार्य कर रही हैं क्योंकि एक संबद्ध वस्तु की घरेलू उत्पादक है और दूसरी निर्यातक ।
- vii. दोनों कंपनियों के प्रचालन के संबंध में शेयरधारकों का कोई सांविधिक या संगठनात्मक प्रतिबंध नहीं है ।
- viii. दोनों कंपनियों के पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बारे में विरोधाभासी हित हैं । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू कंपनी अर्थात् ए बी एल को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा किए गए पाटन के क्षतिकारी प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी जबकि टी सी बी द्वारा निर्यातित वस्तु पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहेगी ।
- ix. हाईटैक कार्बन का व्यवहार भारत में घरेलू उत्पादकों से असंबद्ध फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिंग की तुलना में विशिष्ट तथा अलग नहीं है । दोनों ही घरेलू उत्पादकों को थाइलैंड सहित संबद्ध देशों के निर्यातकों के पाटन के व्यवहार के प्रभाव से क्षति हुई है । दोनों घरेलू उत्पादकों के विभिन्न आर्थिक कारकों की प्रवृत्तियां समान हैं । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि टी सी बी द्वारा पाटन के हाईटैक कार्बन को लाभ मिल रहा है ।
- x. उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, महाराष्ट्र के पाताल गंगा और तमिलनाडु के गुमिलीपुंडी में विनिर्माण संयंत्र होने के कारण हाईटैक कार्बन भारत में कार्बन ब्लैक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका घरेलू बाजार के हिस्से में लगभग ***प्रतिशत हिस्सा है । कंपनी का फोकस घरेलू उत्पादन पर है ।
- xi. पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से हाईटैक कार्बन के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है । परिणामतः आयातों की कम कीमत से घरेलू उद्योग अपनी कीमत को बढ़ाने से बच्चित हुआ है । लाभ में कमी आने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट आई है । इस प्रकार लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट प्रत्यक्ष तौर पर पाठित आयातों के कारण आई है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध जांच की शुरूआत के समय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) निम्नानुसार था :—

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा ।”

11. तथापि, जांच शुरूआत के बाद नियम 2(ख) में 1 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं0 86/2011-सी.शु. (गैर टैरिफ) के तहत संशोधन किया गया है और वर्तमान में यह निम्नानुसार है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।”

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह उपबंध है कि जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध नहीं हैं अथवा जां स्वयं आरोपित पाटित वस्तुओं के आयातक नहीं हैं, उन्हें कुछ स्थितियों में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय अलग रखा जाए । प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि नियम 2(ख) में “जाए” शब्द के प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि संदर्भाधीन दोनों प्रकार के उत्पादक अर्थात् संबद्ध उत्पादक और पाटित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादक घरेलू उद्योग का भाग होने से स्वतः अलग नहीं हो जाते हैं । इसके प्रतिकूल जांच प्राधिकारियों की यह सुसंगत परंपरा रही है कि ऐसे उत्पादकों को बाहर रखने का निर्णय उचित और समान आधार पर मामला दर मामला आधार पर और शामिल सभी विधिक तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए लिया जाना चाहिए ।

13. जहां तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी के पास किसी घरेलू उत्पादक पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातकों के साथ उसके संबंध और उसके द्वारा स्वयं अथवा संबद्ध कंपनियों के जरिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किए जाने के मद्देनजर नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने या न करने का विवेकाधिकार नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा

चीन जन.गण., पाकिस्तान, केन्या आदि से सोडा ऐश के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील सं 193/2012, 194/2012, 189/2012 तथा 195/2012 में 27.4.2012 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्णय दिया था :

“ 62.....(ii) दिनांक 27.2.2010 को यथासंशोधित “घरेलू उत्पाद” पद से निर्दिष्ट प्राधिकारी का विवेकाधिकार समाप्त नहीं हुआ है

14. इसके अलावा, मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने डब्ल्यू ए सं. 2012 की 195 में एम पी 2012 की एक का निपटान करते समय 18.06.2012 के अपने आदेश के तहत अपने पूर्ववर्ती इस निर्णय को दोहराया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस बारे में विवेकाधिकार है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के विवेकाधिकार के बारे में आगे कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

15. प्राधिकारी ने सोडा ऐश, विस्कोस स्टेपल फाइबर आदि के आयातों से संबंधित जांचों के बारे में अपने कुछ पूर्ववर्ती जांच परिणामों में उसके द्वारा भरोसा किए गए और इस विषय पर उपलब्ध न्यायशास्त्र को संज्ञान में लिया है। इस न्यायशास्त्र से निम्नलिखित परिस्थितियों का संकेत मिलता है जिनमें किसी संबद्ध घरेलू उत्पादक को शामिल या अलग रखा जा सकता है :-

(क) इस बारे में एक महत्वपूर्ण कारक विनिर्माण और आयात के बीच घरेलू उत्पादक के व्यापार का संतुलन है। यदि कंपनी मुख्य रूप से भारत में उत्पाद का विनिर्माण करती है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, यदि घरेलू उत्पादक अपना उत्पादन बंद कर देता है या उसे कम कर देता है और इसके बजाए वह उत्पाद का आयात करता है अथवा अपने व्यापार का सामान्य जोर उत्पादन के स्थान पर आयातों पर लगाता है तो उसे अलग रखा जाना चाहिए।

(ख) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने आयातों का सहारा लेकर या किसी संबद्ध पक्षकार को निर्यात कर पाटन के प्रभाव से स्वयं का बचाव किया है तो उस कंपनी को अलग रखा जाना चाहिए।

- (ग) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने पाटन के व्यवहारों में किसी भी रूप में भाग लिया है अथवा उससे अन्यथा अनुचित लाभ प्राप्त किया है तो उसे अलग रखा जाना चाहिए ।
- (घ) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल किए जाने से क्षति संबंधी जांच परिणाम में विकृति आती है तो उसे अलग रखा जाना चाहिए ।
- (ड.) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है तो प्राधिकारी ऐसे घरेलू उत्पादक को अपात्र मान सकते हैं ।
16. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मैं ० जैको, ह्यूमन एंड बिरांडा द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक में अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा ऐसी स्थितियों में लागू किए गए मानदंडों का उल्लेख निम्नानुसार है :-
- (क) संदर्भाधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का वह हिस्सा जो संबद्ध उत्पादकों द्वारा धारित है ।
- (ख) क्या संबद्ध उत्पादकों द्वारा संदर्भाधीन उत्पाद के आयातों से उन्हें लाभ मिला है अथवा पाटन के प्रभावों से उनका बचाव हुआ है ।
- (ग) क्या संबद्ध पक्षकारों को बाहर रखे जाने से उद्योग के शेष सदस्यों हेतु आंकड़ों में अनुचित कमी आएगी ।
- (घ) उत्पादक द्वारा आयात कार्यकलापों के प्रतिकूल घरेलू उद्योग के प्रति प्रदर्शित प्रतिबद्धता का स्तर अथवा उसका दीर्घावधिक स्वरूप ।
- (ड.) संबद्ध उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन में आयात खेपों का अनुपात ।

17. प्राधिकारी यह मानते हैं कि कुछ घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या अलग रखने के विवेकाधिकार का उद्देश्य उन घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग से अलग रखकर जो क्षति कारी पाटन में शामिल रहे हैं, भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयात पर प्रभाव के बारे में तथ्यपरक तथा अविकृत निर्धारण करने में प्राधिकारी को समर्थ बनाना है। जांचकर्ता प्राधिकारी किसी संबद्ध उत्पादक को वहां अलग रख सकते हैं जहां संबद्ध पक्षकार ने या तो :

- (क) बाजार में कीमतों में गिरावट लाने में प्रोत्साहन या योगदान किया है,
- (ख) उसके प्रभावों से बचाव किया है, अथवा
- (ग) जहां वे उससे अनुचित रूप से लाभान्वित हुए हैं।

18. जहां तक प्रथम श्रेणी अर्थात् पाटन के व्यवहार में भागीदारी का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि कई विशिष्ट स्थितियों का भेद किया जा सकता है। एक ओर अपवर्जन वहां पर वास्तव में उचित होता है जहां किसी उत्पादक को क्षति स्वतः स्फूर्त होती है क्योंकि पाटनकर्ता उत्पादकों से हुए आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों की खुद की क्षमता के प्रयोग में कमी आती है अथवा घरेलू उत्पादकों के खुद के उत्पादन में वृद्धि के लिए तैयार की गई उसकी परियोजनाओं का परित्याग होता है। प्राधिकारी का यह मत है कि किसी घरेलू उत्पादक को अलग रखना प्रथम दृष्टया उचित नहीं होता है। यदि पाटन में भागीदारी आत्मरक्षा के कार्य के रूप में की गई हो। अतः संगत घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय ऐसे किसी घरेलू उत्पादक पर विचार किया जाना चाहिए।

19. प्राधिकारी आगे यह मानते हैं कि ऐसे घरेलू उत्पादक, जो पाटित उत्पादों का आयात करते हैं अथवा जिसका संबद्ध पक्षकार पाटित उत्पादों का निर्यात करता है अथवा जिसका संबद्ध पक्षकार पाटित उत्पादों का आयात करता है, पाटन के व्यवहार से अनुचित ढंग से लाभान्वित नहीं होते हैं यदि ऐसे निर्यातों/आयातों का हिस्सा उनकी बिकी या बाजार के आकार का एक बड़ा भाग न हो। वस्तुतः बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसी स्थिति में ऐसे घरेलू उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होगा। अन्य देशों के जांच प्राधिकारियों द्वारा यह निर्णय लेते समय कि क्या किसी घरेलू उत्पादक को अलग रखा जाना चाहिए, किया गया एक अन्य भेद है : क्या घरेलू उत्पादक कुछ पाटित आयातों से अपने घरेलू उत्पादन की मात्रा भरपाई कर रहा है अथवा क्या वह अपेक्षाकृत सीमित उत्पादन के साथ मुख्यतः एक आयातक है ? यदि फोकस घरेलू उत्पादन के बजाए आयातों पर आ जाता है तो ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रमुख तत्व पर इस विषय के बारे में विचार करना जरूरी है, वह है कि क्या संदर्भाधीन घरेलू उत्पादक आयातों के देश में उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय तत्समय विद्यमान संगत प्रावधानों और विधिक स्थिति से प्राधिकारी को संबद्ध घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में उस पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि यदि आवेदक निर्यातक देश में किसी उत्पादक से संबद्ध है तो ऐसे संबंध के मात्र तथ्य से ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से स्वतः बाहर नहीं रखा जाता है। वस्तुतः प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग ऐसे मामलों में प्राधिकारी द्वारा मामला दर मामला आधार पर आगे जांच करने और इस बात पर विचार करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से करना होता है कि क्या ऐसे किसी संबद्ध उत्पादक को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए या अपात्र। परिस्थितिवश इस प्रयोजनार्थ मामले के तथ्यों पर संबंध के प्रभाव को समझने की जरूरत होती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया :-

- (क) क्या संबद्ध पक्षकारों का व्यवहार असंबद्ध पक्षकारों की तुलना में विशिष्ट या अलग है;
- (ख) क्या यह प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य है कि ऐसे संबद्ध उत्पादक ने भारतीय बाजार में पाठन की शुरुआत की है या उसमें तेजी लाई है।
- (ग) क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक का पाठन के प्रभावों से अनुचित बचाव हुआ है या उसे अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है।
- (घ) क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक ने भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बाधा डाली है।

- (ङ.) क्या यह मामला स्वजनित क्षति का है ?

21. प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध पक्षकार होने के अलावा किसी मामला विशेष में संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों/आयातों, यदि कोई हो, के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी संगत होता है। क्या ऐसे संबद्ध पक्षकार ने अवधि के दौरान भारत से संबद्ध वस्तु का निर्यात/वहां आयात किया था। यदि हां, तो क्षति के दावे पर उसका क्या प्रभाव है? यदि नहीं, तो क्या उसके अपवर्जन को न्यायोचित रहाने का कोई अन्य आधार है। यदि संबद्ध पक्षकार ने संबद्ध वस्तु का निर्यात/आयात भी किया है तो निम्नलिखित का मूल्यांकन करने की भी जरूरत है :

- ऐसे संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों/आयातों की मात्रा।

- संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों/आयातों का उददेश्य
 - क्या यह प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों/आयातों के कारण हुई थी;
 - क्या संबद्ध घरेलू उत्पादक का सामान्य जोर संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर था अथवा क्या सामान्य जोर धीरे-धीरे या सतत रूप से आयातों की ओर हो गया था ।
 - क्या ऐसे संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों/आयातों की मात्रा इतनी अधिक थी जिससे संबद्ध निर्यातिक धीरे-धीरे या सतत रूप से असंबद्ध घरेलू उत्पादकों के बाजार में पैठ बना रहा है ।
 - ऐसा कोई अन्य तथ्य जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के दौरान प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया हो ।
22. जांच अवधि के दौरान हाईटैक द्वारा आयात नहीं किए गए थे । इसके बजाए आयात सीधे असंबद्ध आयातकों द्वारा किए गए थे । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान मैं 0 थाई कार्बन ब्लैक (टी सी बी) द्वारा भारतीय आयातकों को अधिकांश निर्यात शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों पर किए गए थे । उन्होंने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान टी सी बी द्वारा भारत को किए गए कार्बन ब्लैक के कुल ***मि. ट. में से केवल ***मि. ट. (कुल निर्यातों का ***%) का निर्यात शुल्क प्रदत्त प्रणाली के तहत किया गया था और शेष ***मि. ट. का निर्यात शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों पर किया गया था । इस संदर्भ में प्राधिकारी ने आवेदक से अनुरोध किया कि वह जांच अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंस पर उसके सदस्य आयातकों द्वारा किए गए आयातों के बारे में सूचना प्रदान करे । आवेदक ने यह सूचित किया कि उसके 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों अर्थात् मैं 0 सिएट लिंग, अपोलो टायर्स लिंग, जे.के.टायर्स एंड इंड. लिंग, ब्रिज स्टोन इंडिया प्रा० लिंग और एम आर एफ ने मिलकर जांच अवधि के दौरान मैं 0 टी सी बी से कुल ***मि. ट. संबद्ध वस्तु का आयात किया है जिसमें से ***मि. ट. का आयात शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों पर किया गया था । उपर्युक्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शुल्क का भुगतान कर केवल ***मि. ट. संबद्ध वस्तु (कुल आयातों का ***%) का आयात किया गया था और जांच अवधि के दौरान मैं 0 टी सी बी थाईलैंड से शेष ***मि. ट. का आयात शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों पर किया गया था । इससे घरेलू उद्योग के उस दावे को बल मिलता है कि संबद्ध निर्यातिक ने जांच अवधि के दौरान भारत को अधिकांश निर्यात अग्रिम लाइसेंसों पर किए हैं ।
23. यद्यपि, मैं 0 हाईटैक कार्बन और मैं 0 थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक कंपनी (टी सी बी) संबद्ध कंपनियां हैं । तथापि, दोनों कंपनियां संबंधित देशों के विधिक कार्यदांचे के अंतर्गत स्वतंत्र कंपनियां हैं

जिनमें से एक भारत के कंपनी कानून के अंतर्गत और दूसरी थाइलैंड के कंपनी कानून के अंतर्गत प्रचालन कर रही है। थाई कार्बन संबद्ध देशों में से एक देश थाइलैंड से जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की उत्पादक और निर्यातक है परंतु उसने उत्तर दायर नहीं किया है। पाटनरोधी शुल्क निरंतर लागू रखने की स्थिति में संबद्ध निर्यातक असहयोगी होने के कारण वह अवशिष्ट शुल्क के अधीन होगा। इसी स्थिति में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उससे मै0 हाईटैक को किसी भी रूप में लाभ मिलेगा। थाइलैंड के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ही घरेलू उद्योग की मंशा की पुष्टि हो जाती है। यदि हाईटैक कार्बन को संबद्ध पक्षकार के निर्यातों से लाभ हुआ होता तो उसने इसी मामले में थाइलैंड के खिलाफ याचिका दायर नहीं की होती। यह नोट करना संगत है कि संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू है और इसलिए यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि हाईटैक कार्बन को अनुचित लाभ मिला है। हाईटैक का फोकस उत्पादन पर बना हुआ है। कंपनी व्यापारी नहीं बनी है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि दोनों पक्षकारों ने साठ-गाठ की है।

24. मूल और वर्तमान समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग देश में कार्बन ब्लैक के 2 प्रमुख असंबद्ध प्रमुख घरेलू उत्पादक अर्थात् मै0 फिलिप्स कार्बन और मै0 हाईटैक कार्बन हैं। यदि हाईटैक कार्बन के संबद्ध निर्यातक अर्थात् टी सी बी द्वारा संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई होती तो मै0 फिलिप्स कार्बन को भी समान रूप से क्षति हुई होती। उस स्थिति में एक असंबद्ध पक्षकार होने के कारण कल्पनातीत ढंग से मै0 फिलिप्स कार्बन ने पाटनरोधी जांचों में हाईटैक से हाथ मिला लिया होता। इसके अलावा, हाईटैक कार्बन का व्यवहार भारत में असंबद्ध घरेलू उत्पादक फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि0 की तुलना में विशिष्ट और अलग नहीं है। दोनों घरेलू उत्पादकों को थाइलैंड सहित संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा पाटन के व्यवहार के प्रभाव से क्षति हुई है। दोनों घरेलू उत्पादकों के विभिन्न आर्थिक कारकों की प्रवृत्ति कमोवेश एक जैसी है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हाईटैक कार्बन को टी सी बी द्वारा किए गए पाटन से लाभ मिला है।

25. इसके अलावा, मूल जांच के दौरान मै0 हाईटैक कार्बन का मै0 थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक कंपनी लि0 (टी सी बी) के साथ संबंध होने के कारण घरेलू उद्योग के रूप में उसकी अपात्रता से संबंधित मुददा उठा था। प्राधिकारी ने 24 दिसंबर, 2009 के अपने अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/21/2008-डी जी ए डी में निम्नानुसार मत व्यक्त किया था :

20. प्राधिकारी ने नोट किया है कि मै0 हाई टैक कार्बन का मै0 थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक कंपनी और मै0 लिओविंग बिरला कंपनी लि0 से संबंध है। मै0 हाई-टैक कार्बन ने दावा किया है कि मै0 लिओनिंग बिरला कंपनी ने भारतीय बाजार में कार्बन ब्लैक का निर्यात नहीं किया है।

हालांकि मैसर्स थाई कार्बन ब्लैक पब्लिक ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तथा जांच अवधि में एम.टी. में 518624 एम.टी. के कुल निर्यात योग में से उनकी पूरी निर्यात मात्रा केवल 2178 एम.टी. ही है। कुछ हितबद्ध पार्टियों ने मै0 हाईटैक की संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों के मद्देनजर उसे बाहर रखने के बारे में अपने तर्क को दोहराया है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाई संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए निर्यात इतने अधिक नहीं हैं और यह ऐसी स्थिति में नहीं किए गए हैं जिससे यह माना जा सके कि मै0 हाईटैक पर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में आपात्र मानने की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हाईटैक कार्बन ने आयात और व्यापार नहीं किया है। कंपनी का मुख्य ध्यान उत्पादन पर अधिक केन्द्रित रहा है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि�0 और मै0 सिएट लि�0 संबद्ध कंपनियां हैं। यद्यपि, एटीएमए ने एक हितबद्ध पार्टी के रूप में वर्तमान जांच में भाग लिया है और मै0 सिएट लि�0 उनका सदस्य है, तथापि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि मै0 सिएट लि�0 ने सीमाशुल्क के भीतराने के बाद संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया है।

21. प्राधिकारी ने नोट किया है कि थाई कार्बन ब्लैक द्वारा किया गया निर्यात भारत के उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत ही कम है। इसके साथ-साथ यह स्थापित नहीं किया गया है कि मै0 हाई टैक कार्बन को घरेलू उद्योग की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि निर्यात संबंध रखने वाले कंपनी द्वारा किए गए हैं। प्राधिकारी उचित समझते हैं कि हाई-टैक कार्बन को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया जाए। जहां तक मै0 फिलिप्स कार्बन की पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे बाहर रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए हितबद्ध पार्टियों ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

22. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै0 फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और हाईटैक कार्बन का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से में शामिल है जो भारत के उत्पादन के 50 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, याचिका का समर्थन मै0 कंटीनेंटल कार्बन ने किया है। इस प्रकार आवेदन, पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं का समाधान करता है। इसके आगे, मै0 फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि�0 और मै0 हाई-टैक कार्बन को वर्तमान प्रयोजन से पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के साथ पढ़ने पर नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग के तहत माना जा रहा है।

26. यह नोट करना संगत है कि वर्तमान समीक्षा जांच में आवेदक जो मूल जांच में भी हितबद्ध पक्षकार था और जिसने थाई कार्बन के साथ संबंध के कारण हाईटैक को घरेलू उद्योग के दायरे

से अलग रखने हेतु यही आधार दिया था, ने नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में हाईटैक पर विचार करने के निर्णय पर विवाद नहीं उठाया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच के आवेदक ने टी सी बी के साथ संबंध होने की स्थिति में घरेलू उद्योग के रूप में मै0 हाईटैक के आधार और क्षेत्र के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं दर्शाया है। इसके बजाए आवेदक द्वारा वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के लिए जिस आधार की मांग की थी वह यह था कि :

- “कार्बन ब्लैक की आयात कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;
- घरेलू बिकी कीमत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है
- कच्ची सामग्री— कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सी बी एफ एस) की लागत में भारी गिरावट आई है और यह कि प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट आने से घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में भारी कमी आई है।
- आयात कीमत में भारी वृद्धि होने के कारण आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि होने के साथ क्षति मार्जिन में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क के वर्तमान स्तर की समीक्षा करने की जरूरत उत्पन्न हुई है।”

27. जहां तक ए टी एम ए के इस तर्क का संबंध है कि साझा निदेशक होने के संदर्भ में फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि�0 (पी सी बी एल) और सिएट लि�0 संबद्ध हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिएट लि�0 ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर कर वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का विरोध किया है। इसके अलावा, संबद्ध आयातक ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग का विरोध किया था। इससे इस बात को बल मिलता है कि संबंध दोनों कंपनियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई निर्धारणकारी प्रभाव नहीं रखता है। यदि संबंध इन कंपनियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खास महत्व रखता होता तो संबंधित घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग नहीं की होती और संबंधित आयातक ने घरेलू उद्योग की इस पहल का विरोध किया होता।

28. इस विषय पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद तथा मामले के विधिक प्रावधानों और तथ्यों एवं ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी की सुसंगत राय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से मै0 हाईटैक और पी सी बी एल को नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। मै0 फिलिप्स कार्बन और मै0 हाईटैक कार्बन का भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और इसलिए वे नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

29. जहां तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का संबंध है कि शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों को क्षति विश्लेषण करते समय अलग रखा जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की सुसंगत परंपरा क्षति विश्लेषण करते समय ऐसे आयातों को अलग रखने की रही है। प्राधिकारी ने विगत में यूरोपीय संघ, चीनी ताइपेई, सिंगापुर, दक्षिण अफ़्रीका और अमरीका के मूल के या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांचों से संबंधित ऐसे ही मुद्दों की जांच की है और निम्नानुसार निर्णय लिया है :

“56. यह उल्लेख किया गया है कि शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अलग रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और कीमत लाइन में अंतर आ जाता है क्योंकि आयातक ऐसे निर्यातकों या आयातकों से वस्तु की खरीद करेंगे जो उन्हें प्रतिस्पर्धा कीमत देंगे, इसलिए शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों पर बाजार में कीमत पर प्रभाव न डालने वाले आयातों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ समस्त शुल्क मुक्त आयातों को बाहर रखना उचित पाया है।”

30. अतः शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों पर घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव न डालने वाले आयातों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। किसी अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकार धारक के पास यह विकल्प होता है कि वह शुल्क मुक्त आधार पर निविष्टि का आयात करे या अग्रिम निर्गम आदेश के तंत्र का प्रयोग कर स्वदेशी स्रोतों से उसकी खरीद करे। क्षति विश्लेषण का उददेश्य घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना और उसकी पुष्टि करना होता है। अतः क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ समस्त शुल्क मुक्त आयातों को अलग रखना उचित नहीं होगा।

31. जहां तक याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के अनुसार हाईटैक कार्बन और मैट्रो फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड को संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे तीसरे देश से भारत में मुख्य रूप से आयातित कच्ची सामग्री में केवल 15 प्रतिशत का मूल्यवर्धन करते हैं। इस संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के उपबंधों को नीचे उद्धृत किया जा सकता है :

“25. पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन – (1) जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का आयात उद्गम के देश या पाटनरोधी शुल्क की लेवी के प्रयोजनार्थ अधिसूचित निर्यात के देश सहित किसी देश से भारत में असंयोजित, अप्रसंस्कृत या अपूर्ण रूप में किया जाता है और उसे भारत में या ऐसे देश में संयोजित, प्रस्कृत या पूर्ण किया जाता है तो ऐसे संयोजन, परिष्करण या पूर्ता

को लागू पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन माना जाएगा, यदि,—

(क) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद या उससे ठीक पूर्व शुरू हुआ है या उसमें वृद्धि हुई है और पुर्जों तथा संघटकों का आयात उद्गम के देश या पाटनरोधी शुल्क की लेवी के प्रयोजनार्थ अधिसूचित निर्यात के देश से किया गया है; और

(ख) संयोजन, प्रसंस्करण या पूर्णता संबंधी प्रचालन के परिणामस्वरूप मूल्य संयोजित, प्रसंस्कृत या पूर्ण वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम रहा हो ।

स्पष्टीकरण।— “मूल्य” का तात्पर्य आयातित पुर्जों या संघटकों के मूल्य से कम संयोजित, पूर्ण या प्रसंस्कृत वस्तु की लागत से है ।

स्पष्टीकरण॥ — “मूल्य” की गणना के प्रयोजनार्थ बौद्धिक संपदा अधिकारों, रायल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क और परामर्शी प्रभारों से जुड़े भुगतानों के लिए किए गए व्यय को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(2) जहाँ पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में आयात उद्गम के देश या पाटनरोधी शुल्क की लेवी हेतु अधिसूचित निर्यात के देश से वस्तु विवरण, नाम या उसकी संरचना में परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को उस स्थिति में लागू पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन माना जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क के अधीन वस्तु के वर्णन या नाम या संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना परिवर्तित की जाने वाली वस्तु के स्वरूप या दिखावट में भले ही मामूली ही अंतर हुआ हो ।

(3) जहाँ पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में आयात ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों या देश के जरिए किया जाता है जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं है, वहाँ ऐसे निर्यातों को उस स्थिति में लागू पाटनरोधी शुल्क का अपवंचन करने वाला माना जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी हेतु अधिसूचित निर्यातक या उत्पादक अपने व्यापार व्यवहार, व्यापार की प्रणाली या वस्तु की बिक्री के माध्यमों में परिवर्तन करते हैं ताकि वे अपने उत्पादों का भारत में निर्यात ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों या देश के जरिए कर सकें जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है ।

स्पष्टीकरण — इस उप नियम के प्रयोजनार्थ इस बात की पुष्टि की जाएगी कि व्यापार व्यवहार, व्यापार की प्रणाली या बिक्री के माध्यमों में परिवर्तन हुआ है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात् :—

(क) पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से इतर आर्थिक या अन्यथा किसी औचित्य का अभाव;

(ख) इस आशय का साक्ष्य कि पाटनरोधी शुल्क के निवारक प्रभावों में समान उत्पादों की कीमत या उनकी गुणवत्ता के संबंध में कमी आई है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के उपबंध इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि पाटनरोधी शुल्क के अधीन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उल्लंघनजनित पूर्णतः अलग स्थिति का समाधान किया जा सके। उक्त नियम में प्रदत्त मानदंड पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र से संबंधित मामले में लागू नहीं होते हैं।

च. गोपनीयता

33. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि सूचना या तो गोपनीय या अगोपनीय रखी जा सकती है; ऐसा कोई विनियम नहीं है जिसमें केवल कुछ हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना को गोपनीय माना जाए और उसे अन्य दूसरों के लिए अगोपनीय माना जाए। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि आवेदक ने घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना को स्वयं घरेलू उद्योग से गोपनीय होने का दावा किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीयता के बारे में काई बड़ा मुददा नहीं उठाया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार, गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

छ. विविध अनुरोध

याचिकाकर्ता (एटीएमए), निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

35. याचिकाकर्ता (ए टी एम ए), निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र निर्णयक समीक्षा के क्षेत्र से भिन्न होता है। किसी मध्यावधि समीक्षा में डी जी ए डी के लिए इस बात पर विचार करना और उसका निर्धारण करना अपेक्षित होता है कि क्या 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पाटनरोधी शुल्क को समाप्त

करने का पर्याप्त औचित्य है जबकि निर्णयिक समीक्षा में डी जी ए डी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष समाप्त होने के बाद आगे लागू करना अपेक्षित है या नहीं ।

- ख. याचिकाकर्ता ने “समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना” प्रदान कर मौजूदा उपायों की समीक्षा करने की मांग की है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया यह तर्क आधारहीन है कि यह सिद्ध करने का दायित्व घरेलू उद्योग पर है कि शुल्क समाप्त किए जाने से क्षति नहीं होगी ।
- ग. घरेलू उद्योग के तर्क के अनुसार जांच अवधि में विस्तार नहीं किया जाना चाहिए । यदि घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि “समीक्षा अवधि के दौरान निष्पादन असंगत है” और आज की स्थिति के अनुसार निष्पादन की जांच की जानी चाहिए, किसी अवधि के निष्पादन की समीक्षा करने की अवधारणा अपना विधिक महत्व खो देगी और किसी पाटनरोधी जांच का कोई अंत नहीं होगा क्योंकि समय के साथ-साथ नए आंकड़े आते रहेंगे ।
- घ. जांच की शुरूआत के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, उत्पादक अपने व्यापार को इस ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे ताकि वे जांच शुरूआत के बाद की अवधि में घाटा दिखा सकें और पुनरावृत्ति के संकेत के रूप में क्षति का दावा कर सकें ।
- ड. रक्षोपाय जांच केवल चीन के लिए है और यह अन्य संबद्ध देशों के लिए प्रासंगिक नहीं है ।
- च. डी जी ए डी रक्षोपाय जांच परिणाम पर विचार करने का अपीलीय प्राधिकारी नहीं है । डी जी ए डी से रक्षोपाय जांच के विपरीत जिसमें विशिष्ट जांच अवधि नहीं होती है, जांच अवधि से पूर्व की परिभाषित क्षति अवधि के साथ परिभाषित जांच अवधि के दौरान निष्पादन की जांच करने की अपेक्षा की जाती है ।
- छ. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों में प्रस्तुत आंकड़ों और रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा दर्ज जांच परिणामों के आंकड़ों में भारी अंतर है ।
- ज. यद्यपि, रक्षोपाय महानिदेशक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश की । तथापि, वित्त मंत्रालय ने यह माना कि चीन जन.गण. से आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को दूर करने के लिए 15 माह की अवधि हेतु रक्षोपाय शुल्क लागू करना घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त है । अतः केन्द्र सरकार के अनुसार भी 31 दिसंबर, 2013 के बाद चीन जन.गण. से आयातों के कारण क्षति की संभावना नहीं है ।

- झ. संशोधित नियम में हितबद्ध पक्षकार से समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। घरेलू उद्योग के तर्कानुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की जरूरत की पुष्टि करते हुए सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- ट. घरेलू उद्योग का यह तर्क किसी विधि आधार से रहित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की जरूरत की जांच करने के लिए समीक्षा अवधि के दौरान उसका निष्पादन पूर्णतः अपर्याप्त है। समीक्षा अवधि के रूप में किसी विशेष अवधि को निर्दिष्ट करने का उद्देश्य उक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करना और उसके पश्चात शुल्क समाप्त किए जाने की जरूरत की समीक्षा करना है।
- ठ. वर्तमान मामले के लिए निर्धारित समीक्षा अवधि अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 की है। जांच 30 अगस्त, 2011 अर्थात् समीक्षा अवधि की समाप्ति के 5 माह बाद शुरू की गई थी। अतः घरेलू उद्योग के तर्क के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समीक्षा अवधि को ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता।
- ड. अंतिम निर्धारण करते समय डी जी ए डी द्वारा रक्षोपाय महानिदेशक के जांच परिणामों पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें निहित सूचना वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना से सर्वथा भिन्न है।
- ढ. कुछेक सदस्यों की खरीद कीमत के बारे में सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उन सदस्यों की क्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने सूचना प्रदान की है।
- ण. घरेलू उद्योग का यह तर्क सर्वथा गलत है कि आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बंद किया जाना चाहिए था। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटन के क्षतिकारी प्रभाव को समाप्त करना है न कि आयातों को बंद करना।
- ट. मध्यावधि समीक्षा जांच वर्तमान जांच की समीक्षा अवधि तक सीमित रखी जानी चाहिए और समीक्षा अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रत्येक नए और पुराने आंकड़ों पर विचार होगा जिससे जांच को पूरा करने में विलंब होगा।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

36. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- क. मध्यावधि समीक्षा जांच का क्षेत्र इस अर्थ में मूल और निर्णायक समीक्षा जांच के क्षेत्र से अत्यधिक भिन्न होता है कि जहां किसी मध्यावधि समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार

करना और उसका निर्धारण करना अपेक्षित होता है कि क्या समय पूर्व पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने का पर्याप्त औचित्य है, वहीं निर्णायक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार कर उसका निर्धारण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे बढ़ाना अपेक्षित है। तथापि, दोनों प्रकार की समीक्षा में पाटन और क्षति के बारे में संभावना का विश्लेषण एक अनिवार्य अवधारणा है।

ख. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच अवधि ऐतिहासिक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में उसके बाद भारी परिवर्तन हुआ है। अतः वर्तमान अवधि पर विचार किए बिना किया गया कोई निर्धारण नियम 23(1क) की भावना के विरुद्ध होगा।

ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों को स्थायी स्वरूप की कहा जा सकता है। परिस्थिति में मात्र परिवर्तन अपर्याप्त है। वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन और संबद्ध देशों से आयातों का स्तर परिवर्तित परिस्थितियों के स्थायी स्वरूप का निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद साक्ष्य है।

घ. इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि रक्षोपाय जांच परिणामों पर आंकड़ों में कुछ अंतरों की वजह से ही विचार नहीं किया जाना चाहिए। रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा उत्पादन, घरेलू एवं निर्यात बिक्री मात्रा, मालसूची की मात्रा के निर्धारण हेतु लिया गया आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए गए आधार से भिन्न है। जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी वार्षिक लेखों के भाग स्वरूप वित्तीय रिकॉर्डों और वित्तीय विवरण को अपनाते हैं, वहीं रक्षोपाय महानिदेशक, उत्पाद शुल्क संबंधी रिकॉर्डों को अपनाते हैं। महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संगत उद्धरण निम्नानुसार है। :-

क. उत्पादन : उत्पादन का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उसके उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों में सूचित उत्पादन के आधार पर किया गया है।

ख. बिक्री : बिक्री का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा निकासी की गई और उसके उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों में सूचित की गई वस्तु के आधार पर किया गया है।

ग. मालसूची : मालसूची के स्तर पर घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों के अनुसार विचार किया गया था।

ड. अतः दोनों आंकड़ों के बीच मामूली अंतर लाजिमी है। जैसा कि लिखित अनुरोधों में उल्लेख किया गया है, यहां तक कि आयकर अधिनियम के अनुसार, लाभ/हानि और वार्षिक रिपोर्ट में लाभ/हानि जैसे प्रमुख मानदंड भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी अधिनियम के अंतर्गत

निर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। तथापि, ये अंतर निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए संगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा अपनाए गए आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर विचार करने का अनुरोध किया है। यह सिद्ध नहीं किया गया है कि दोनों मामलों में निर्णय से दो अलग-अलग निर्णय निकाले गए हैं। वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा दोनों आधार पर प्रस्तुत सूचना से एक समान निष्कर्ष निकलते हैं अर्थात् :

- i. वर्ष 2010–11 तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से जैसे मापदंडों कारण सुधार हुआ है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है।
- ii. वर्ष 2010–11 तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में सुधार हुआ है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है।

च. दोनों प्रकार की सूचना अर्थात् रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा भरोसा की गई सूचना एवं वित्तीय रिकॉर्डों के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना से इन निष्कर्षों की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है।

छ. आयातों में अंतर इस तथ्य के कारण है कि जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पाद विवरण पर विचार करते हैं और वर्गीकरण जिसके अंतर्गत आयात किया गया है, पर ध्यान दिए बिना विचाराधीन उत्पाद के आयातों को शामिल करते हैं, वहीं महानिदेशक ने केवल एच एस कोड 28030010 के अंतर्गत आने वाले आयातों पर ही विचार किया है। घरेलू उद्योग ने महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों का हवाला दिया है जो वर्तमान मुददे के लिए प्रासंगिक है। महानिदेशक (रक्षोपाय) के जांच परिणाम के संगत उद्धरण निम्नानुसार हैं :—

30. भारत में जांचाधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 28030010 के अंतर्गत किया गया है। रक्षोपाय जांच वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों और शेष अवधि के लिए गौण आंकड़ा संकलनकर्ता एजेंसी (आई बी आई एस) से घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम में समूची अवधि के लिए आयात के आंकड़ों पर घरेलू उद्योग द्वारा गौण आंकड़ा संकलनकर्ता एजेंसी (आई बी आई एस) से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि उसमें ऐसे उत्पादों के कुछ आयातों को शामिल किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। अतः यद्यपि, याचिकाकर्ताओं ने आई बी आई एस के अनुसार, ऐसे आयातों की सूचना दी थी जिनमें एच एस कोड 28030020 और 28030090 के अंतर्गत किए गए आयात भी शामिल थे, तथापि, जांच के बाद एच एस कोड 28030010 के अंतर्गत आने वाले आयातों पर भी विचार किया गया है। संवर्धित आयातों का

विश्लेषण केवल “रबड़ अनुप्रयोग” हेतु सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 28030010 के अंतर्गत आने वाले कार्बन ब्लैक के आयातों पर विचार करते हुए संगत अवधि के लिए किया गया था।

ज. किसी पूर्वाग्रह के बिना घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि दोनों आंकड़ों में अंतर मामूली है। दोनों आंकड़ों से अंततः समान निष्कर्ष निकलता है। नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी अंततः आर्थिक संकेतकों में प्रवृत्तियों से सरोकार रखते हैं। यदि रक्षोपाय जांच में निहित आंकड़ों या घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अब प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया जाए तो निकाला गया अंतिम निष्कर्ष समान रहेगा। उदाहरणार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी का सरोकार इस बात से है कि क्या उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है या गिरावट आई है। भले ही उत्पादन पर उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों के अनुसार या वित्तीय रिकॉर्डों के अनुसार विचार किया गया हो, निष्कर्ष एक समान ही निकलेगा। अतः आर्थिक मापदंडों के निर्धारण हेतु दो अलग-अलग आधारों पर विचार करने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में निम्नानुसार उल्लेख है:

(1) अधिनियम की धारा 9 के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए उस अवधि तक और उस सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, अपनी खुद की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर जो ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उचित समयावधि बीत जाती है, किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में उसकी समाप्ति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त या परिवर्तित कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की सम्भावना नहीं है और इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है।

(1 ख) उप नियम (1) या (1क) में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कि

उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुल्क की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी ।

(3) नियम 6,7,8,9,10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

38. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो, वहां अपनी खुद की पहल पर या समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रदान करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बाद एक उचित समयावधि बीत गई हो । हितबद्ध पक्षकारों के पास प्राधिकारियों से इस बात की जांच करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखना आवश्यक है अथवा क्या शुल्क समाप्त किए जाने या उसकी राशि में अंतर किए जाने से क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने अथवा दोनों की संभावना होगी । यदि इस पैराग्राफ के अंतर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क आगे अपेक्षित नहीं है तो वे उसे तुरंत समाप्त कर सकेंगे ।

39. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र निर्णयक समीक्षा के क्षेत्र से अलग है । आवेदक ने यह तर्क दिया है कि किसी मध्यावधि समीक्षा में डी जी ए डी के लिए इस बात पर विचार कर उसका निर्धारण करना अपेक्षित होता है कि क्या 5 वर्ष पूरे होने से पहले पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने का पर्याप्त औचित्य है जबकि निर्णयक समीक्षा में डीजीएडी के लिए यह निर्धारण करना अपेक्षित होता है कि क्या 5 वर्ष की समाप्ति के बाद पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे बढ़ाना अपेक्षित है अथवा नहीं । दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि किसी मध्यावधि समीक्षा में यह निष्कर्ष निकालने के लिए केवल वर्तमान निष्पादन अपर्याप्त है कि क्या इस चरण पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जा सकता है और यह कि प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावित स्थिति पर विचार करना अपेक्षित होता है ।

40. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुददों की जांच की है और वह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत प्राधिकारी का दायित्व है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उचित समयावधि समाप्त होने के पश्चात ऐसी समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रदान करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर किसी पाटनरोधी शुल्क को निरंतर रूप से

लगाए जाने की जरूरत की समीक्षा करें, प्राधिकारी उस स्थिति में शुल्क को समाप्त करने के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें अंतर किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए आगे इसकी जरूरत नहीं है।

41. जहां तक जांचोत्तर अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार जांचोत्तर अवधि के घटनाक्रमों पर समीक्षा तंत्र के जरिए विचार करना अपेक्षित है, जो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने या उसे निरंतर लागू रखने की जरूरत के निर्धारण के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी ने न केवल जांच अवधि के संदर्भ में सूचना/आंकड़ों की जांच और उनका मूल्यांकन किया है अपितु, निष्कर्ष निकालने के लिए पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के निर्धारण हेतु जांचोत्तर अवधि की सूचना/आंकड़ों का भी विश्लेषण किया है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने क्षति अवधि पर मार्च, 2011 तक विचार किया है। तथापि, अप्रैल-सितंबर, 2011 की अवधि पर भी पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के निर्धारण हेतु विचार किया गया है।
42. जहां तक रक्षोपाय और पाटनरोधी जांच के बीच आंकड़ों में अंतर का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा उत्पादन, घरेलू एवं निर्यात बिकी की मात्रा, मालसूची की मात्रा के निर्धारण हेतु अपनाया गया आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आधार से भिन्न है। जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी वार्षिक लेखों के भाग स्वरूप वित्तीय रिकॉर्डों और वित्तीय विवरण को अपनाते हैं, वहीं रक्षोपाय महानिदेशक उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों को अपनाते हहैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच परिणाम सहयोगी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है।

ज. पाटन मार्जिन का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था के दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

43. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- चीन को निम्नलिखित कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए:

- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि मापदंडों में से एक की भी पूर्ति नहीं होती है।
- सिद्ध करने का भार प्राधिकारी पर नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन कर रही हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की पात्र हैं। इसके विपरीत चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का यह दायित्व है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रही हैं।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह यह दावा न करे। यदि उक्त समूह के भाग स्वरूप एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं परंतु उन्हें किसी अन्य पक्षकार से अर्जित किया है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए रूपांतरण की प्रक्रिया की पूर्ण पुष्टि न की गई हो।

ii. चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता (ए टी एम ए), निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन के उत्पादकों के पास भारी बेशी क्षमता है जिससे भारत में पाटन का खतरा उत्पन्न हो गया है। अनुरोध किया जाता है कि चीन जन.गण. के

पास काफी पहले से बेशी क्षमता रही है लेकिन बेशी क्षमता की मात्र उपलब्धता यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इससे भारत में पाटन की पुनरावृत्ति होगी ।

- चीन उत्पाद और घरेलू उत्पाद की कीमत में अंतर का मुख्य कारण घरेलू उद्योग और चीन के उसके समकक्ष उद्योग द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री में अंतर है । मात्र इस कारण कि चीन के उत्पादक सस्ती कीमत पर संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में समर्थ हैं, का तात्पर्य यह नहीं है कि वे वस्तु का पाटन कर रहे हैं । प्रयुक्त अलग-अलग कच्ची सामग्री से उत्पन्न किसी क्षति का कारण पाटन को नहीं माना जा सकता ।

बाजार अर्थव्यवस्था के दारों की जांच

चीन.जन.गण.

44. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों को एम ई टी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं । प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी यह अनुरोध किया कि वह अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें ।

45. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन0 जन0 गण0 से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

i. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिकियां और निवेश के बारे में चीन.जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

- ii.इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;
- iii.इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- iv.विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

46.वर्तमान जांच में मै0 जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक लि0, जिंगडेचैन, चीन.जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक) को छोड़कर चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने एम ई टी प्रश्नावली का उत्तर दायर कर बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया;

1. मै0 जिनेंग साईस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लि., चीन जन.गण.
2. मै0 शंघाई ह्यूनटोंग इंडस्ट्री इंट. कंपनी लि., चीन जन.गण..
3. मै0 सुझोऊ बोहुआ कार्बन ब्लैक कंपनी लि0, चीन जन.गण..

47.प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 शंघाई ह्यूनटोंग इंडस्ट्री इंट. कंपनी लि., चीन जन.गण. और मै0 सुझोऊ बोहुआ कार्बन ब्लैक कंपनी लि0, चीन जन.गण. ने अपने आंकड़ों/सूचना के सत्यापन की पेशकश करते हुए सहयोग नहीं किया और इसलिए उन्हें वर्तमान जांच में असहयोगी माना गया है।

48.मै0 जिनेंग साईस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लि., चीन जन.गण, जिसने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया और मै0 जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक. लि., जिंगडेचैन, चीन.जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक), जिसने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया, द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी ने सत्यापन किया था ।

मै0 जिनेंग साईस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लि., चीन जन.गण

49.मै0 जिनेंग साईस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लि., ने वर्तमान जांच में एम ई टी प्रश्नावली दायर की और बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया । मै0 जिनेंग साईस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी

लि., द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी ने सत्यापन किया था । मौके पर सत्यापन के दौरान प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किए गए थे :

- i. मौके पर सत्यापन के दौरान यह सूचित किया गया था कि संबद्ध कंपनी और उसकी नियंत्रणकर्ता मूल कंपनियां और संबद्ध कंपनियां पूर्णतः परिवार द्वारा धारित कारोबार हैं । आगे यह बताया गया था कि संबद्ध कंपनी की स्थापना से पूर्व संबद्ध कंपनी पर स्वामित्व रखने वाला परिवार रसोई उपकरण के कारोबार में शामिल था । तथापि, संबद्ध कंपनी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि उक्त परिवार रसोई उपकरण के कारोबार से इतना अधिक धन कैसे जुटा सकी जिससे उसने 10 वर्ष या इतनी अवधि के भीतर भारी निवेश किया ।
- ii. मै० शेनडॉंड रिपु और मै० शेनडॉंग चैनमिंग कैमिकल कंपनी लि० के बीच संबंध के बारे में पूछे जाने पर यह सूचित किया गया था कि श्री विवनपिंग, संबद्ध कंपनी के अध्यक्ष ने खाद्य अभिवर्धकों का उत्पादन करने के लिए ***% शेयर के साथ वर्ष 1998 में मै० शेनडॉंग चैनमिंग कैमिकल कंपनी लि० की स्थापना की थी । आगे यह बताया गया था कि यह कंपनी 2002 में बंद हो गई थी और कंपनी की भूमि और परिसंपत्तियों को बेच दिया गया था । परंतु कंपनी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस सौदे की पुष्टि नहीं कर सकी । तथापि, जब वैब आधारित इस सूचना के बारे में बताया गया कि मै० शेनडॉंग रिपु का पुराना नाम मै० शेनडॉंग चैनमिंग कैमिकल कंपनी लि० है तो संबद्ध कंपनी ने यह बताया कि मै० चैनमिंग कैमिकल्स लि० के कारोबार को संबद्ध कंपनी की नियंत्रणकर्ता मूल कंपनी मै० रिपु ने अपने हाथ में ले लिया था । परंतु संबद्ध कंपनी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह सिद्ध नहीं कर सकी कि उक्त सौदा बाजारी प्रक्रिया के अनुसार किया गया था ।
- iii. कंपनी ने यह सूचित किया था कि संबद्ध कंपनी सहित समूचा ग्रुप परिवार द्वारा धारित है और समस्त निवेश एवं आर्थिक सौदे नकद में किए जाते हैं । निवेशकों की निधि के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर दस्तावेजों द्वारा समर्थित कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका । कंपनी यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी कि संबद्ध कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद खुले बाजार में कीमत के अनुसार की गई थी । कंपनी प्रचलित बाजार कीमत पर कच्ची सामग्री की खरीद का ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं कर सकी ।
- iv. इसके अलावा, वैब आधारित एक सूचना में यह उल्लेख है कि संबद्ध कंपनी कोयला रसायन राज्य मंत्रालय की प्रमुख अनुसूचीबद्ध संपर्क कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध थी । ऐसे विवरण की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न किए जाने पर कंपनी दस्तावेजों के साथ पुष्टि करते हुए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी ।

- v. तुलन पत्र में कंपनी ने उसकी स्थापना के पहले ही वर्ष में ***मिलियन आर एम बी का निवल मूल्य होने का दावा किया है और कंपनी ने इसके लिए मूल्यहास का दावा किया है। परंतु कंपनी उसके द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों की खरीद के समर्थकारी संगत दस्तावेजों के साथ परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं करा सकी। कंपनी बाजार कीमत पर भूमि और भवन की खरीद के समर्थन में दस्तावेज और विस्तृत भूमि संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सकी।
- vi. कंपनी यह कहते हुए वर्ष 2011 के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रदान नहीं कर सकी कि वे तैयार नहीं हैं। परंतु यह पाया गया था कि जहां कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे वर्ष के फरवरी माह तक आम तौर पर तैयार हो जाते हैं, वहीं कंपनी द्वारा जून माह के अंत तक जब कंपनी का सत्यापन किया गया था, वर्ष 2011 के लिए वार्षिक लेखेक न रखने के बारे में कोई संतोषजनक कारण नकहीं दिया जा सका। कंपनी से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई वचनत्र प्रस्तुत करे परंतु उसने ऐसा नहीं किया।
- vii. कंपनी ने यह सूचित किया कि कंपनी के पर्यवेक्षक मंडल का संचालन तीन सदस्यों द्वारा किया जाता है। हालांकि दो सदस्यों के बारे में कंपनी के कर्मचारी होने का दावा किया गया था। तथापि, बी ओ एस के अध्यक्ष के बारे में यह बताया गया था कि वह लेबर यूनियन का भी अध्यक्ष है। परंतु कंपनी बी ओ एस के सदस्यों की भागीदारी के बारे में और प्रदान कर सकी और न ही वह उन्हें रोजगार एवं मासिक वेतन के भुगतान के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकी।
50. सत्यापन रिपोर्ट संबद्ध कंपनी को उसके प्रतिनिधियों के जारिए टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। सत्यापन रिपोर्ट के उत्तर में मै0 जिनेंग ने गैर बाजार के दर्जे के बारे में प्राधिकारी के अभिमतों का खंडन नहीं किया जिसके तहत गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकार किया गया था। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मै0 जिनेंग साईंस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लि0, चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं करते हैं।
51. इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को एम ई टी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है और उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करने के लिए घरेलू उद्योग सहित किसी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को कोई वास्तविक तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार उचित आधार पर चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपबंध है कि :

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमतम अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे

देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत जहां यह संभव न हो, अथवा किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यार रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की ई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ”

53. तदनुसार, चीन के सभी निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के कारखाना सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध—। के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार उचित आधार पर चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली

54. प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधार पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है—

(क) प्रमुख निविष्टि, कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर हैवी स्टॉक जी सी 3 प्रतिशत हेतु प्लेट्स मैगजीन द्वारा प्रकाशित कीमत के आधार पर विचार किया गया है ।

(ख) कच्ची सामग्री की खपत और परिवर्तन लागत को घरेलू उद्योग के कुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है ।

(ग) बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत को घरेलू उद्योग के कुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है ।

(घ) लाभ को व्याज छोड़कर कारखाना लागत के 5 प्रतिशत की दर से लिया गया है ।

55. निष्पक्ष तुलना के उद्देश्यों से उत्पत्ति और बेचे गए संबद्ध वस्तु के प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग सामान्य मूल्य की गणना की गई है और जांच की प्रत्येक तिमाही के लिए भी सामान्य मूल्य की

गणना अलग से की गई है। तथापि, यह किए गए पाटन मार्जिन को इस तरह से औसतन रखा गया है कि वे समूची जांच अवधि के बराबर हों और बाद में भी "विचाराधीन उत्पाद" माना जाए।

56. तदनुसार, चीन.जन.गण. के संबंध में प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य *** अम0डा0 प्रति मी0ट0 निर्धारित किया गया है।

रूस, आस्ट्रेलिया तथा थाइलैंड के मामले में सामान्य मूल्य

57. हालांकि आस्ट्रेलिया और थाइलैंड के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है तथापि, मै0 यारोसलावस्की टेक्नीचेस्की अगलेरोड, रूस ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

मै0 यारोसलेवस्की टेक्नीकेस्की अगलेरोड (उत्पादक) तथा मै0 ट्राईगॉन गल्फ, एफजैडसीओ दुबई यू.ए.ई.

58. प्राधिकारी द्वारा मै. यारोसलावस्की टेक्नीकेस्की अगलेरोड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का सत्यापन किया गया था। जांच अवधि के दौरान यद्यपि कंपनी ने तीसरे देशों को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया तथापि उसने भारत को निर्यात अपने वितरक मै. ट्राईगॉन गल्फ, जो यूएई के दुबई में एक व्यापार कंपनी है, के जरिए ही किया। यह बताया गया था कि मै. ट्राईगॉन गल्फ ने संबद्ध वस्तु की कारखाना खरीद मै. यारोसलावस्की से की और उसके बाद उसने समर्त अपेक्षित दस्तावेज तैयार कर और सभी जरूरी व्यय वहन कर भारत को निर्यात किया। वस्तुओं का पोत लदान सीधे फैक्टरी से भारतीय उपभोक्ताओं को किया जाता है। तथापि भुगतान ट्राईगॉन द्वारा किया जाता है। समूचे सौदे को यारोसलावस्की और ट्राईगॉन गल्फ के बीच हस्ताक्षरित संविदा द्वारा शासित किया हुआ बताया गया था।

59. सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि यादृच्छिक ढंग से संबद्ध वस्तु के बारे में चुने गए सभी बीजकों में यह दावा किया गया था कि जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया गया है जिसमें परेषिती का नाम ***, कोलम्बो, श्रीलंका दर्शाया गया था। पूछे जाने पर कंपनी ने यह सूचित किया कि समस्त अन्य निर्यात परेषण भी कोलम्बो में उसी कंपनी को भेजे गए थे और वे कोलम्बो के पक्षकार को ट्राईगॉन गल्फ, दुबई के जरिए भारत को उनके सभी निर्यातों के संबंध में परेषिती के रूप में दर्शाने का उनके इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंतु कंपनी भारत को निर्यात हेतु वास्तव में नियत संबद्ध वस्तु के बारे में अपने बीजकों आदि में परेषिती के रूप में ***, कोलम्बो, श्रीलंका का नाम दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कोई संतोषजनक कारण/औचित्य प्रदान नहीं कर सकी और यह कि इसकी जानकारी उसे थी। संविदा की परिशिष्ट की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि यारोसलावस्की की जानकारी में पूरी तौर पर यह बात थी कि उसके द्वारा भेजी गई संबद्ध वस्तु वास्तव में भारतीय क्रेताओं के लिए थी।

और ट्राइगॉन गल्फ की जानकारी में भी यह बात थी कि यारोसलावस्की द्वारा भारतीय क्रेताओं को निर्यात हेतु उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु के संबंध में परेषिती के रूप में ***, कोलंबों को दर्शाया जा रहा है। इस जानकारी के बावजूद यारोसलावस्की ने अपने निर्यात दस्तावेजों में ***, कोलंबों का नाम दर्शाना जारी रखा और ट्राइगॉन ने इस परंपरा पर आपत्ति नहीं की और वह अपने निर्यात दस्तावेजों में भारतीय क्रेताओं के नाम उन्हीं खेपों को दर्शाता रहा ।

60. इसके अलावा, मै. ट्राइगॉन गल्फ ने जांच अवधि के दौरान अन्य रूसी तथा चीनी उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात भी किया। परंतु ऐसे सौदों के बारे में रूस और चीनी जन गण के संबंधित उत्पादकों द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। अतः वर्तमान जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को हुए संबद्ध वस्तु के ट्राइगॉन के निर्यात के एक भाग का संबंधित उत्पादकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

61. सत्यापन के दौरान मै. ट्राइगॉन से यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि वह यारोसलावस्की द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में उनके द्वारा हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार भारतीय ग्राहकों को वास्तव में बिक्री के लिए नियत वस्तु के लिए ***, कोलंबो के रूप में पक्षकार का नाम क्यों दर्शाया गया है। ट्राइगॉन द्वारा ऐसी परंपरा अपनाने हेतु जांच दल को दस्तावेजी समर्थन के साथ कोई संतोषजनक कारण/औचित्य प्रदान नहीं किया गया था।

62. मै. यारोसलावस्की टेक्नीकेसकी अगलेराड, रूस से काफी समय पूर्व यह अनुरोध किया गया था कि वह सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित दस्तावेज/रिकार्ड अंग्रेजी भाषा में विधिवत रूपांतरित कर तैयार रखें। स्पष्ट और पूर्व निर्देशों के बावजूद अधिकांश दस्तावेजों/रिकार्ड को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं कराया गया था और उन्हें सत्यापन हेतु तैयार नहीं रखा गया था। परिणामतः दल उक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का सत्यापन नहीं कर सका।

63. प्राधिकारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट संबंधित उत्पादक और निर्यातिक को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। परंतु जहां तक भारतीय क्रेताओं के लिए नियत खेप के संबंध में उत्पादक के बीजकों में परेषिती का नाम ***, कोलंबों का नाम दर्शाए जाने के मुद्दे का संबंध है उत्पादक या निर्यातिक द्वारा दस्तावेजी समर्थन के साथ ऐसी परंपरा का पालन करने का कोई संतोषजनक कारण/औचित्य प्रदान नहीं किया जा सका।

64. कुछ अन्य अभिमतों के साथ—साथ उपर्युक्त अभिमत सत्यापन में नोट किया गया था जिन्हें टिप्पणियों के लिए संबंधित पक्षकारों को भेजा गया था। उत्तर में मै. ओपन ज्वाइंट स्टाक कंपनी "यारोसलावस्की टेक्नीकेसकी अगलेराड", रूस (उत्पादक) ने अन्य बातों के साथ—साथ निमानुसार अनुरोध किया है:

"ट्राइगॉन गल्फ यारोसलाव के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य देश/बाजार में सीबी की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत है और वह भारत के साथ—साथ किसी अन्य

स्थान पर वस्तु भेज सकती है। अतः यारोसलाव से प्राप्त अंतिम बीजक में ' ***- श्रीलंका' के रूप में उल्लिखित परेषिती का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह यारोसलाव का अपना खुद का निर्यात मामला है (वह किस प्रकार दस्तावेज तैयार करना चाहती है) और इसलिए ***, श्रीलंका के रूप में उल्लिखित परेषिती पर ध्यान दिए बिना ट्राइगॉन भारत में अपनी पसंद के ग्राहकों को वस्तु की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत है। ट्राइगॉन गल्फ को आपूर्ति की गई वस्तु के प्रत्येक मीट को उसके द्वारा समुचित रूप से प्रलेखित किया जाता है और बीएल प्रतियों/बीजाकों से भारत के रूप में अंतिम गंतव्य को सिद्ध किया जा सकता है। यह यारोसलाव का अंतरिक मामला है कि वह किस प्रकार निर्यात दस्तावेज तैयार करे। इस पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।"

65. अपने उत्तर में मै. ट्राइगॉन गल्फ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"बिंदु 3: ट्राइगॉन गल्फ ने मै. ***-रूस और मै. ***- चीन द्वारा उत्पादित कार्बन ब्लैक की भारत को आपूर्ति भी करती है। तथापि प्रश्नावली का उत्तर दायर करने को न्यायोचित रहनाने के लिए इन दोनों कंपनियों का मात्रा काफी कम है। मध्यावधि समीक्षा के बारे में यारोसलाव और ट्राइगॉन ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं तथा पाटनरोधी कार्वाई से बचने के लिए समूची जांच में सहयोग किया है।"

बिंदु 5: कृपया इसी विषय पर मै. यारोसलावस्की का उत्तर (बिंदु 7) भी देखें। ट्राइगॉन गल्फ ने यारोसलाव से खरीदे गए प्रत्येक मीट. और भारत के विभिन्न ग्राहकों को भेजी गई मात्रा के समस्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। यारोसलाव के निर्यात दस्तावेज में ही परेषिती को "- श्रीलंका दर्शाया जाता है जो वर्तमान जांच के लिए अप्रासंगिक है।"

66. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मै. यारोसलावस्की टेक्नीकेसकी अगलेराड (उत्पादक) और मै. ट्राइगॉन गल्फ, एफजेडसीओ, दुबई, यूएई के प्रश्नावली के उत्तर को भरोसेमंद और उचित शंका से परे नहीं पाते हैं। अतः प्राधिकारी ने उनके उत्तरों पर विचार नहीं किया और संबद्ध उत्पादक-निर्यातक के संयोजन को अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया।

रूस, थाइलैंड और आस्ट्रेलिया के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

67. चूंकि प्राधिकारी ने मै. यारोसलावस्की टेक्नीकेसकी अगलेराड (उत्पादक) और मै. ट्राइगॉन गल्फ, एफजेडसीओ, दुबई, यूएई द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किया है और रूस, थाइलैंड तथा आस्ट्रेलिया के संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार

पर रूस, थाइलैंड और आस्ट्रेलिया के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार, रूस, थाइलैंड और आस्ट्रेलिया के संबंध में कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण इस जांच-परिणाम के पैरा 54 और 55 में स्पष्ट की गई कार्य प्रणाली के आधार पर किया गया है। भारत को निर्यातित ग्रेडों के लिए इस प्रकार से निर्यातित भारित औसत सामान्य मूल्य क्रमशः *** अम.डा. प्रति मी.ट, *** अम.डा. प्रति मी.ट. और *** अम.डा. प्रति मी.ट. है।

अ. निर्यात कीमत

प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

68. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर किया जा सकता है।

मै. जिनेंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि., जिनान, चीन जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक)

69. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है संबद्ध वस्तु के प्रत्येक ग्रेड / प्रकार के लिए भारत हेतु पृथक भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्यातक के दावे के अनुसार अंतर्देशी परिवहन, विदेशी परिवहन, विदेशी बीमा, ऋण, बैंक प्रभारों और निर्यात पैकिंग के लिए समायोजन किए गए हैं। सत्यापन के दौरान जिनेंग ने यह दावा किया कि संबद्ध वस्तु के निर्यातों के लिए वैट की कोई वापसी नहीं होती है। निर्यातकों की सत्यापन रिपोर्ट में यह नोट किया गया था कि मै. जिनेंग ने प्रदत्त / संदेय वैट और वैट वापसी के बीच अंतर के लिए किसी समयोजन का दावा नहीं किया है। सत्यापन रिपोर्ट के अपने उत्तर में जिनेंग ने यह दावा किया कि परिशिष्ट 2 में दर्शायी गई कीमतें वैट से रहित हैं और इसलिए उसने किसी समयोजन का दावा नहीं किया है। सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिनेंग ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** अम.डा. के सकल मूल्य की *** मी.ट. संबद्ध वस्तु और जांचोत्तर अवधि (अप्रैल 2011 – सितम्बर 2011) के दौरान *** अम.डा. के सकल मूल्य की *** मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया। स्वीकार्य समयोजन करने के बाद जांच अवधि के दौरान प्राधिकारी जिनेंग की निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति मी.ट. निर्धारित करते हैं।

मै. जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक. लि., जिंगडेझेन, चीन जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक)

70. मै. जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक. लि., चीन जन.गण. ने यह दावा किया कि संबद्ध मध्यावधि समीक्षा की जांच अवधि अर्थात् अप्रैल 2010– मार्च 2011 के दौरान उसने एक संबद्ध कंपनी मै. जिंगडेझेन केएमजेड ग्रुप इंप. एंड एक्स. कं. लि. (केएमजेड) के जरिए भारत को अपनी निर्यात बिक्री के एक भाग के बिक्री की। मौके पर सत्यापन के दौरान ब्लैक कैट से यह स्पष्ट करने का

अनुरोध किया गया था कि उसके संबद्ध पक्षकार मै. केएमजेड ने निर्यातिक प्रश्नावली का उत्तर दायर क्यों नहीं किया क्योंकि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। ब्लैक कैट ने यह स्पष्ट किया कि केएमजेड केवल ब्लैक कैट के एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। वह संबद्ध उत्पाद के व्यापारी /निर्यातिक के रूप में कार्य नहीं कर रही है क्योंकि वह किसी सौदे में कोई लाभ नहीं कमा रही है। सत्यापन रिपोर्ट के बाद उपर्युक्त के बारे में पक्षकार द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां भी असंतोषजनक पाई गई थीं।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. ब्लैक कैट की संबद्ध पक्षकार मै. केएमजेड द्वारा कोई उत्तर दायर किए बिना ब्लैक कैट की निर्यात कीमत को भारत को समग्र कंपनी समूह द्वारा किए गए निर्यातों की प्रतिनिधिक निर्यात कीमत नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने मै. जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन ब्लैक इंक. लि., चीन जन.गण. को अलग पाठन मार्जिन प्रदान नहीं किया है।

चीन जन.गण. के असहयोगी निर्यातकों / उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

72. प्राधिकारी ने पाठनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार चीन जन.गण. के सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति मी.ट. निर्धारित की जाती है।

रूस, आस्ट्रेलिया एवं थाइलैंड से निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

73. जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने मै. यारोसलावस्की टेक्नीकेसकी अगलेराड (उत्पादक) और मै. ट्राइगॉन गल्फ, एफजेडसीओ, दुबई, यूएई (निर्यातक) द्वारा दायर उक्त उत्तर को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है और चूंकि रूस एवं थाइलैंड तथा आस्ट्रेलिया से संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातिक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने पाठनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनकी निर्यात कीमत निर्धारित करने का निर्णय लिया है। आंकड़ों का मिलान आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना और सहयोगी निर्यातिक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार किया गया है। इन देशों से हुए आयातों का भारित औसत सीआईएफ मूल्य निकालने का प्रयास प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विचार किया है। इन देशों के संबंध में निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशी भाड़ और बैंक प्रभारों के लिए घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार समायोजनों पर विचार किया गया है। तदनुसार, कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत रूस से *** अम.डा. प्रति मी.ट., आस्ट्रेलिया से *** अम.डा. प्रति मी.ट. और थाईलैंड से *** अम.डा. प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है।

ज.पाटन मार्जिन

74. उपरोक्त निर्धारित सामान्य कीमत एवं निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं:

निर्यातक	देश	पाटन मार्जिन अम. डा. प्रति मी.ट.	पाटन मार्जिन प्रतिशत के रूप में	पाटन मार्जिन रेंज प्रतिशत
मै. जिनेंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि.	चीन जन.गण.	***	***	35-45
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	चीन जन.गण.	***	***	55-65
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	रूस	***	***	10-20
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	आस्ट्रेलिया	***	***	10-20
असहयोगी उत्पादक / निर्यातक	थाइलैंड	***	***	5-15

ट. क्षति निर्धारण हेतु कार्यप्रणाली और क्षति तथा कारणात्मक संबंध का निर्धारण

आवेदक (एटीएमए), निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

75. इस बारे में आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. मूल जांच की जांच अवधि और वर्ष 2010-11 के बीच सभी संबद्ध देशों से आयात कीमत में 24 प्रतिशत का अत्यधिक सुधार हुआ है। मौजूदा उपायों की केवल इस वजह से समीक्षा किए जाने की जरूरत है कि वर्ष 2007-08 और मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आयात कीमतों में पर्याप्त और अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

ख. प्रमुख कच्ची सामग्री सीबीएफएस की खरीद कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है जिसमें मूल जांच की जांच अवधि तथा 2010-11 के बीच अपरिष्कृत तेल की कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक अन्य कच्ची सामग्री, तार आयल की लागत में भी गिरावट आई है। अतः क्षति रहित कीमत में भारी गिरावट आनी चाहिए थी।

- ग. संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। भारतीय घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी परिवर्तन हुआ है और सभी मापदंडों में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के जिस निष्पादन हेतु शुल्क लगाया गया था उसमें भारी सुधार हुआ है, शुल्क का प्रयोजन सिद्ध होने के बाद उसे अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- घ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उस सूचना के बाद ही गिरावट आनी शुरू हुई जब पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए एटीएमए द्वारा दायर की गई याचिका का बाजार में पता चला। घरेलू उद्योग ने जान बूझकर अपनी बिक्री की मात्रा और कीमत कम रखी ताकि वह समीक्षा के बाद की अवधि में क्षति दर्शा सके।
- ड. कैबोट इंडिया की कार्बन ब्लैक की सुविधा पाटित आयातों के किसी प्रतिकूल प्रभाव के कारण बंद नहीं की गई थी अपितु बेहतर लागत संरचना, विस्तार की क्षमता और अन्य कारकों के लिए सर्वथा प्रबंधन के निर्णय की वजह से बंद हुई थी।
- घ. मूल जांच की जांच अवधि और 2010-11 के बीच घरेलू उद्योग के निर्यातों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
- छ. डीजीएडी ने अपने प्रारंभिक जांच में यह नोट किया है कि आयात की इकाई कीमत में भी वृद्धि हुई है और कीमत क्षति का कारक नहीं है इससे स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति नहीं हो रही है।
- ज. क्षति रहित कीमत की गणना हेतु पुनः मूल्यांकित परिसंपत्तियों, कार्यशील पूंजी आदि के मूल्यहास के संदर्भ में घरेलू उद्योग के दावे को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रस्तावित कार्यप्रणाली से प्राधिकारी की स्थापित और सुसंगत परंपरा का पालन नहीं होगा।
- झ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस दावे को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि सुसंगत परंपरा के अनुसार उसे लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय प्रदान की जाएगी। प्राधिकारी उतनी आय प्रदान कर सकते हैं जिसे घरेलू उद्योग क्षति न होने पर अर्जित कर सकता है।
- ऋ. क्षति रहित कीमत का निर्धारण और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री की प्राप्ति के साथ उसकी तुलना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग बनाने और बेचने की लागत तथा लगाई गई पूंजी पर आय से काफी अधिक लाभ कमा रहा है। भारी निवेश पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग अत्यधिक लाभ कमा रहा है और इसलिए उसने गलत ढंग से यह अनुरोध किया है कि उसे अभी भी क्षति हो रही है।
- ट. घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु घरेलू उद्योग के तर्क – बेहतर वित्तीय परिणाम, क्षमता वृद्धि, आयातों से कोई क्षति नहीं, के विरोधाभासी हैं। पूर्ववर्ती जांच के समय विद्यमान

परिस्थितियों में भारी अंतर आया है और घरेलू उद्योग को क्षति होने की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

- ठ. आयातों में वृद्धि पर कार्वाई रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा की जा रही है और डीजीएडी को इस समस्या में उलझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा की जा रही रक्षोपाय जांच केवल चीन के बारे में है और यह अन्य संबद्ध देशों के लिए संगत नहीं है।
- ड. घरेलू उद्योग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि से यह पता चलता है कि उसे पूँजी जुटाने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जहां तक क्षमता का संबंध है घरेलू उद्योग की स्थिति संबद्ध देशों के निर्यातकों और अन्य देशों में वस्तु के पाटन की स्थिति के समान है।
- ढ. मूल जांच की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कुल स्थापित क्षमता 500,000 मी.ट. थी। संभावित मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में लगातार वृद्धि की गई है। वर्तमान समीक्षा जांच की जांच अवधि के दौरान याचिककर्ता द्वारा क्षमता में 175,000 मी.ट. की वृद्धि की गई है जिससे कुल क्षमता बढ़कर 675,000 मी.ट. हो गई है। इसी प्रकार, बाजार में कुछ नए प्रवेशकर्ता आए हैं जबकि दूसरे बाहर चले गए हैं। भारत में कार्बन ब्लैक के घरेलू उद्योग की गतिशीलता में यह परिवर्तन परिवर्तित का द्योतक है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा अपेक्षित हो गई है।
- ण. घरेलू उद्योग का यह तर्क सही नहीं है कि नियमों के अनुबंध III की व्याख्या करते समय पाठ की व्याख्या करने में पिछली कोई परंपरा आड़े नहीं आनी चाहिए। अनुबंध III प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परंपरा की मात्र संहिताबद्धता है और प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध III में दिए गए कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।
- त. किसी रक्षोपाय जांच परिणाम पर विचार करने के लिए डीजीएडी अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। डीजीएडी के लिए रक्षोपाय जांच, जिसमें विशिष्ट जांच अवधि नहीं होती है, के विपरीत जांच अवधि से पूर्व परिभाषित क्षति अवधि के साथ परिभाषित जांच अवधि के दौरान निष्पादन की जांच करना अपेक्षित होता है।
- थ. यद्यपि रक्षोपाय महानिदेशक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश की थी तथापि वित्त मंत्रालय ने यह माना कि चीन जन.गण. से आयातों से क्षतिकारी प्रभावों को दूर करने के लिए 15 माह की अवधि हेतु रक्षोपाय शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त है। अतः केंद्र सरकार के अनुसार भी 31 दिसम्बर 2013 से आगे चीन जन.गण. से आयातों के कारण क्षति की संभावना नहीं है।
- द. चीन से आयातों में नियमित आधार पर कमी आ रही है और इस प्रकार उनका घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू उद्योग को क्षति स्वजनित है न कि आयातों के कारण।
- ध. रूस/यारोसलावर्स्की के पास उपलब्ध कोई बेशी क्षमता नहीं है।

- न. मध्यावधि समीक्षा जांच वर्तमान जांच की समीक्षा अवधि तक सीमित की जानी चाहिए और समीक्षा जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे हर बार नए आंकड़ों पर विचार किया जाएगा जिससे जांच पूरी होने में विलंब होगा।
- प. चीन के उत्पाद और घरेलू उत्पाद की कीमत में अंतर के मुख्य कारण घरेलू उद्योग और चीन में उसके समकक्ष द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री में अंतर है। मात्र इस वजह से कि चीन के उत्पादक सस्ती कीमत पर संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने में समर्थ है, यह अर्थ नहीं निकलता है कि वे वस्तु का पाठन कर रहे हैं। प्रयुक्त विभिन्न कच्ची सामग्रियों से हुई किसी क्षति का कारण पाठन को नहीं माना जा सकता।
- फ. पूर्ववर्ती जांच के दौरान मौजूद परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है और खासकर यारोसलावस्की, रूस से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

76. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:-

- क. आटोमोबाइल उद्योग में मंदी के परिणामस्वरूप वर्ष 2008–09 में विचाराधीन उत्पाद की मांग में अत्यधिक गिरावट आई और 2009–10 तथा जांच अवधि में भारी वृद्धि हुई। वर्तमान/चालू अवधि में मांग में आगे और वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि की आशा करते हुए और उपभोक्ता उद्योग की उत्पादन योजनाओं पर विचार करते हुए अपनी क्षमता में 2009–10 तथा 2010–11 में वृद्धि की है।
- ख. आयातों में भारत में उत्पाद के उत्पादन की तुलना में और भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम रही थी। अतः आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हो रहा है।
- ग. उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि हो रही है। तथापि 2010–11 के बाद जब क्षमता में आगे और वृद्धि हुई है, घरेलू बिक्री में नाटकीय ढंग से गिरावट आई है और परिणामिक उत्पादन एवं क्षमता उपयोग कम हुआ है।
- घ. क्षमता का उपयोग इष्टतम स्तर तक नहीं किया जा सका क्योंकि पाठित आयातों की मात्रा में एक बार फिर भारी वृद्धि हुई। इससे क्षमता का कम उपयोग होने के बावजूद माल सूची इकट्ठी हो गई।

इसके अलावा, उत्पादन में भारी कमी के बावजूद माल सूची में अप्रैल – दिसम्बर 2011 में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

- ड. उत्पादन लागत में 2008–09 में वृद्धि हुई 2009–10 में गिरावट आई और 2010–11 में पुनः वृद्धि हुई। बिक्री कीमत में भी यही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। तथापि बिक्री कीमत में वर्ष 2010–11 में बिक्री लागत में वृद्धि की समान बढ़ोत्तरी नहीं हुई। परिणामतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जिसमें 2008–09 में घाटे के बाद 2009–10 में सुधार हुआ था, 2010–11 में तुलनात्मक रूप से कम रही।
- घ. इस प्रकार वर्तमान मामले की जांच अवधि से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पहले से ही गिरावट शुरू हो गई। उसके बाद स्थिति में भारी गिरावट आई।
- छ. यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई तथापि भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में कुल मिलाकर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। बहरहाल, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में अत्यधिक सुधार होना चाहिए था और पाटन से पूर्व घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी सुधार होना चाहिए था। तथापि घरेलू उद्योग पूर्व में प्राप्त बाजार हिस्से को वापस हासिल नहीं कर सका।
- ज. कैबोट इंडिया घरेलू उद्योग का भाग नहीं है और उसने पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की मांग नहीं की है।
- झ. सीबीएफएस में गिरावट से भी पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की जरूरत की पुष्टि नहीं होती है। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है। जैसा कि लिखित अनुरोधों में सिद्ध किया गया है कि यदि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक कीमत में कमी करेगा तो उसे भारी वित्तीय घाटा होगा।
- ञ. निर्यात मात्रा में वृद्धि से ऐसी निर्यात मात्रा की प्रतिस्पर्धात्मकता का पता नहीं चलता है इससे केवल घरेलू बाजार में बिक्री करने या निर्यात बाजार में बेहतर लाभप्रदता के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता का पता चलता है।
- ट. वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचना इस वजह से संगत नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है और उसमें अन्य उत्पाद भी शामिल है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट में सूचना निर्यात तथा घरेलू प्रचालनों दोनों के लिए है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग को पाटन से क्षति जारी है। घरेलू उद्योग को अभी आय की उचित दर हासिल करनी है। घरेलू उद्योग देश में मौजूद मांग की सीमा तक अपनी क्षमताओं के उपयोग की आशा कर रहा है। आशा की गई थी कि घरेलू उद्योग की स्थिति में

पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण सुधार होगा। तथापि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

- ड. टायर खंड के अधिकांश उपभोक्ता विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक कीमतों के आधार पर अपनी खरीद का निर्णय लेते हैं। यद्यपि विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतें कम होती हैं तो उपभोक्ता विदेशी उत्पादकों से खरीद बढ़ा देते हैं। इस बात की स्पष्ट पुष्टि हाल की अवधि में चीन से आयातों में अत्यधिक वृद्धि द्वारा होती है।
- ढ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की सिफारिश करने के लिए वर्तमान में कोई पाटन या कोई क्षति न होना पर्याप्त नहीं है। निर्यातक को पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कोई क्षति न होने की पुष्टि करनी चाहिए।
- ड. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों की विषय-वस्तु घरेलू उद्योग के तर्क की विरोधाभासी है, अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचना इस वजह से संगत नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है और उसमें अन्य उत्पाद भी शामिल हैं। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट में सूचना निर्यात तथा घरेलू प्रचालनों दोनों के लिए है।
- त. रूस से सम्बद्ध वस्तु की आयातों में गिरावट संगत नहीं है, क्योंकि अलग-अलग देशों से निर्यातों में आई गिरावट में मध्यावधि समीक्षा में कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। जो बात संगत है वह यह है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की शुरूआत भारी मात्रा में किए जाने की संभावना नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है। रूस से विश्व के कई स्थानों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात किए जाते हैं। क्षति की संभावना दर्शाने के लिए वैश्विक निर्यातों की वर्तमान मात्रा ही पर्याप्त है।
- थ. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, तथापि उत्पादन और घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी मांग में वृद्धि के कारण हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2010–11 तक वृद्धि होने के बाद 2011–12 की तिमाही 2 में तेजी से गिरावट आई। लाभप्रदता में 2009–10 तक सुधार हुआ और उसके बाद वर्तमान जांच अवधि में गिरावट आई। वर्तमान जांच अवधि में लाभप्रदता 2007–08 की लाभप्रदता से कम रही थी। इसके अलावा, लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई और वह 2011–12 की तिमाही 3 में सबसे कम स्तर पर थी।
- द. लगाए गए रक्षोपाय शुल्क में चीन के संबंध में ही पाटन के कारण हुई क्षति शामिल होती है और वह भी उस स्थिति में जहां रक्षोपाय शुल्क की मात्रा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से अधिक होती है। यदि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा रक्षोपाय शुल्क की मात्रा से अधिक है तो इसका तात्पर्य यह है कि राशि में भिन्नता की सीमा तक रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क, दोनों का भुगतान करना है। इसका तात्पर्य यह भी है कि रक्षोपाय शुल्क द्वारा इन मामलों में संपूर्ण क्षति का निवारण नहीं हुआ है।

- ध. रक्षोपाय शुल्क की अवधि 31.12.2013 तक इस वजह से सीमित नहीं की गई है कि केंद्र सरकार ने यह माना है कि घरेलू उदयोग को उसके बाद “कोई क्षति” नहीं होगी। शुल्क को इस वजह से सीमित नहीं किया गया है कि सरकार का यह मानना है कि डब्ल्यू टी ओ दायित्वों के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क 31.12.2013 के बाद वसूल नहीं किया जा सकता।
- न. घरेलू उदयोग की क्षमता में वृद्धि और निर्यात निष्पादन से यह सिद्ध नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उदयोग को क्षति नहीं होगी। क्षमता में वृद्धि से कम से कम उचित बाजारी स्थिति हेतु जरूरत में वृद्धि की पुष्टि होती है। निर्यातों में वृद्धि केवल उपलब्ध क्षमताओं में से हुई है न कि घरेलू बाजार की लागत पर।
- प. समीक्षा जांच में निवल बिक्री प्राप्ति के साथ क्षति रहित कीमत की कोई तुलना यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जा सकता है। यदि अंतर सकारात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि घरेलू उदयोग क्षति रहित कीमत प्राप्त करने में असमर्थ है। यदि अंतर नकारात्मक है तो इसका तात्पर्य भी “किसी प्रतिकूल कीमत प्रभाव” से नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकारी ने क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा आगे किए गए क्षति विश्लेषण से स्वतः हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों का समाधान हो जाता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोधों पर प्राधिकारी ने निम्नानुसार विचार किया है:

78. जहां तक कैबोट इंडिया की कार्बन ब्लैक की सुविधा को बंद किए जाने के बारे में याचिकार्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कैबोट इंडिया घरेलू उदयोग का भाग नहीं है और इसलिए आवेदक द्वारा इस संबंध में उठाया गया मुद्दा प्रासंगिक नहीं है।

79. आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय महानिदेशालय “डीजीएसजीडी” ने प्रारंभिक जांच परिणाम में यह नोट किया है कि आयातों की इकाई की कीमत में भी वृद्धि हुई है और यह कीमत क्षति का कारक नहीं है, अतः पाटन के कारण घरेलू उदयोग को क्षति न होने की पुष्टि होती है। कार्यकारी नोट करते हैं कि डीजीएसजीडी ने इस संबंध में 31 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या जीएसआरडी-220011/12/2011 के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए हैं। डीजीएसजीडी के अंतिम जांच परिणाम के संगत पैरा नीचे उद्धृत हैं:

“98 घरेलू उदयोग के निष्पादन से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान कार्बन ब्लैक की मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उदयोग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और चीन से आयातों में वृद्धि हुई। यह भी देखा जाता है कि 2009–10 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन से वे आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित, दोनों रूप में कीमत कटौती में वृद्धि हुई है।

99. यह देखा जाता है कि यद्यपि हाल की अवधि में आयात कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, यह घरेलू उदयोग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे घरेलू उदयोग की बिक्री कीमत और आयात की पहुंच कीमत के बीच कीमत अंतर में बढ़ोतरी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप उभोक्ताओं में चीन जन–गण से आयात शुरू कर दिए हैं तथा बाजार में अत्यधिक विकृति हुई है और घरेलू उदयोग को परिणामी क्षति हुई है जिससे सर्वाधित आयात और आई विकृति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है।”

“111 उपर्युक्त जांच परिणाम के आधार पर यह देखा जाता है कि

क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्षति अवधि के दौरान हल्की अवधि में आयातों में तेजी से वृद्धि के साथ समग्र रूप में वृद्धि हुई है,

ख. चीन जनवादी गणराज्य से कार्बन ब्लैक के सर्वाधित आयातों से कार्बन ब्लैक के घरेलू उदयोग/उत्पादकों के लिए बाजार विकृति उत्पन्न हुई है और उसका खतरा पैरा हो गया है, तथा

ग. इस बात की पुष्टि की गई है कि घरेलू उदयोग को क्षति चीन जनवादी गणराज्य से सर्वाधित आयातों के कारण हुई है:— और

घ. चीन जन–गण से कार्बन ब्लैक के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू करना सार्वजनिक हित में होगा।”

80. जहां तक क्षति रहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उदयोग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ उसकी तुलना के बारे में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत के बीच अंतर पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण के मापदण्डों में से एक है परन्तु यह एकमात्र मापदण्ड नहीं है। ऐसे विश्लेषण को एकमात्र आधार के रूप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती कि क्या घरेलू उदयोग को पाटन के कारण क्षति हुई है या नहीं। इसके अलावा, समीक्षा जांच में विश्लेषण का केंद्र बिन्दु शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उदयोग को क्षति होने की संभावना और वर्तमान क्षति न होने पर निहित होता है।

81. जहां तक क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की कार्यप्रणाली के बारे में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संगत दिशानिर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में सुनिर्धारित हैं।

82. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2010 में चीन के उत्पादकों के पास आज की स्थिति के अनुसार काफी अधिक अतिरिक्त क्षमता थी और इससे भविष्य में भी भारतीय बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी सम्बद्ध देश में बेशी क्षमता का होना पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की क्षमता में पाटन की संभावना का एक प्रमुख संकेतक है। चूंकि याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि चीन के उत्पादकों के पास बेशी क्षमता है। इसलिए वर्तमान जांच समीक्षा जांच होने के कारण चीन में ऐसी बेशी उत्पादन क्षमता की अनुदेखी नहीं की जा सकती।

83. जहां तक याचिकाकर्ता और हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी को 22 प्रतिशत के रूप में लगाई गई पूँजी पर आय के दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि लगाई गई पूँजी पर 22 प्रतिशत की आय की अनुमति देने की प्राधिकारी की सुसंगत परम्परा रही है।

ट. संचयी निर्धारण

84. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संयची रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है तथा

ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

85. प्राधिकारी ने पाया है कि:

- संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
- संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा ईरान को छोड़कर निर्धारित सीमाओं से अधिक है; जैसा कि इन जांच परिणामों के संगत खंड में दर्ज किया गया है।

- आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से प्रतिसंपर्क कर रहे हैं। यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है :

क. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन किया जाता है। संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा इसी प्रकार के ग्रेडों का उत्पादन किया जा रहा है और भारत को उनकी आपूर्ति की जा रही है। संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु से आपस में और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की तुलना में तुलनीय गुणधर्म है। दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों से आपूर्ति और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु आपस में समान वस्तु है।।

ख. ऐसी सामान्य पार्टियां हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रही हैं। अतः आयातित एवं घरेलू सामग्री का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच प्रत्यक्ष प्रतिसंपर्क है।।

ग. संबद्ध देशों के निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने उन्हीं ग्राहकों को समान अवधि में समान उत्पाद की बिक्री की है। बिक्री के माध्यम तुलनीय हैं।।

घ. प्रत्येक देश से आयात की मात्रा काफी अधिक है।।

ड. ग्राहक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कीमतों के आधार पर खरीद संबंधी निर्णय लेते हैं।।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आस्ट्रेलिया चीन, जन.गण., रूस और थाइलैंड से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण उचित होगा।

86. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है।

अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

87. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिकी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभावित और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन माजिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।”
88. प्राधिकारी ने तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है। क्षति मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के तुलन पत्र सहित समस्त संगत दस्तावेजों की जांच की और उनका सत्यापन किया। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के हित में और मुददों पर कार्रवाई भी उचित शीर्ष में की गई है।

मांग और बाजार हिस्सा

89. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में (2008-09 को छोड़कर) और जांचोत्तर अवधि में भी उत्पाद की मांग में अत्यधिक और लगातार वृद्धि हुई है।

अवधि	घरेलू उद्योग की घरेलू बिकी	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिकी	संबद्ध देशों से आयात	अन्य देशों से आयात	मांग/खपत	प्रवृत्ति
	मी.ट.	मी.ट.	मी.ट.	मी.ट.	मी.ट.	सूचीबद्ध
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि						
2007-08	345641	111,826	48,209	14,858	520,534	100
2008-09	340067	98,052	43,825	7,506	489,449	94
2009-10	404649	119,391	57,605	8,082	589,727	113

2010-11	462280	109,537	46,273	16,312	634,403	122
जांचोत्तर अवधि						
ति.1(11-12) वार्षिकीकृत	471,602	104,292	40,880	17,936	634,710	122
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	390,488	132,000	116,333	27,757	666,578	128

आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

बजार हिस्सा	इकाई	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12- ति.1	11-12- ति.2
घरेलू उद्योग	%	66	69	69	73	74	59
अन्य भारतीय उत्पादक	%	21	20	20	17	16	20
संबद्ध देश	%	9	9	10	7	6	17
अन्य देश	%	3	2	1	3	3	4
मांग/ खपत	%	100	100	100	100	100	100
उत्पादन के संबंध में आयात	%	10	11	12	8	6	19
घरेलू बिकी के संबंध में आयात	%	14	13	14	10	9	30

90. यह देखा जाता है कि:-

- तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, जांचोत्तर अवधि के दौरान ति.2 में जांच अवधि सहित समूची क्षति अवधि की तुलना में आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

- ii. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में मामूली गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि ति.2 में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष के दौरान 66 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 73 प्रतिशत हो गया है। तथापि, समूची क्षति अवधि की तुलना में जांचोत्तर अवधि अवधि की ति.2 के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में भारी गिरावट आई है। अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा, जो जांच अवधि सहित समूची क्षति अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रहा है, उसमें जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों के बाजार हिस्से, जिसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है? उसमें जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

91. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अविवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिकी, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। उत्पादन लागत के इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिकी प्राप्ति और क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है।

पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी और कीमत न्यनकारी प्रभाव:

92. पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी और कीमत न्यूनकारी प्रभाव की जांच भी जांच अवधि तथा जांचोत्तर अवधि सहित क्षति अवधि के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, निवल बिकी प्राप्ति और पहुंच मूल्य के संदर्भ में की गई है।

अवधि	बिकी की लागत	अवधि	आधार वर्ष में वृद्धि/कमी	बिकी कीमत	प्रवृत्ति	आधार वर्ष में वृद्धि/कमी
	रु./मी.ट.		%	रु./मी.ट.		%
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि						
2007-08	***	100	-	***	100	-

2008-09	***	150	***	***	126	***
2009-10	***	124	***	***	122	***
2010-11(जांच अवधि)	***	153	***	***	149	***
जांचोत्तर अवधि						
ति.1(11-12) वार्षिकीकृत	***	169	***	***	156	***
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	***	186	***	***	168	***

93. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिकी लागत और बिकी कीमत, दोनों में भारी वृद्धि हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिकी कीमत में वृद्धि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिकी लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है। इससे कीमत ह्वासकारी प्रभाव का पता चलता है जिससे घरेलू उद्योग बिकी लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप बिकी कीमत प्राप्त नहीं कर सका है। इसके अलावा, जांच अवधि की तुलना में जांचोत्तर अवधि के दौरान बिकी लागत और बिकी कीमत दोनों में भारी वृद्धि हुई थी। परंतु बिकी कीमत में वृद्धि बिकी लागत में वृद्धि से काफी कम रही है। इससे पता चलता है कि जांचोत्तर अवधि के दौरान पाटित आयातों के कीमत ह्वासकारी प्रभाव गंभीर हो गया है।

कीमत कटौती और कम कीमत पर बिकी संबंधी प्रभाव

कीमत कटौती

94. घरेलू उद्योग की निवल बिकी प्राप्ति की गणना करते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित रिवेट, छूट और कमीशन तथा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कटौती की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना 1 प्रतिशत उत्तराई प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर को संबद्ध देशों से निर्यात/सीआईएफ कीमत में जोड़कर की गई है जैसी कि प्रत्येक प्रतिवादी

निर्यातक ने सूचना दी है। अन्य श्रेणी के लिए पहुंच कीमत की गणना डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार निर्धारण योग्य मूल्य में लागू मूल सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर की गई है।

देश	पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	निवल बिकी प्राप्ति	पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती	पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती रेज	पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती रेज	
	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	
जांच अवधि								
आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-10
चीन	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-10
थाइलैंड	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-10
रूस	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-(10)
संबद्ध देश	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-10
जांचोत्तर अवधि								
आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-10
चीन	***	***	***	***	** *	***	*** 5-15	0-4

थाइलैंड	***	***	***	***	**	***	***	0-10	0-(10)
रूस	***	***	***	***	**	***	***	5-15	0-10
संबद्ध देश	***	***	***	***	**	***	***	5-15	0-10

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित और पाटन शुल्क रहित घरेलू कीमत पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत कटौती सकारात्मक है। तथापि, पाटनरोधी सहित रूस और थाइलैंड के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है।

कम कीमत पर बिकी

96. कम कीमत पर बिकी के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है। इससे यह पता चलता है कि जहाँ जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिकी नकारात्मक थी वहीं यह जांचोत्तर अवधि के दौरान सकारात्मक बन गई है।

क्र. सं.	देश	पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत	एनआईपी	कम कीमत पर बिकी		
				रु./मी.ट.	रु./मी.ट.	% Range %
जांचोत्तर अवधि						
1	आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	0-(10)
2	चीन	***	***	***	***	0-(10)
3	थाइलैंड	***	***	***	***	(5)-(15)
4	रूस	***	***	***	***	0 - (10)

जांचोत्तर अवधि						
1	आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	5 - 15
2	चीन	***	***	***	***	5 - 15
3	थाइलैंड	***	***	***	***	0 - 10
4	रूस	***	***	***	***	5 - 15

ड. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जांच

बिकी मात्रा

97. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिकी मात्रा का विश्लेषण किया गया है। स्थिति निम्नानुसार है:

अवधि	घरेलू बिकी मात्रा
	मी.ट.
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि	
2007-08	345641
2008-09	340067
2009-10	404649
2010-11	462280
जांचोत्तर अवधि	
ति.1(11-12) वार्षिकीकृत	471,602
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	390,488

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बिकी मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच अवधि की तुलना में जांचोत्तर अवधि की ति.1 के दौरान घरेलू बिकी में भी मामूली वृद्धि हुई है, परंतु जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिकी में भारी गिरावट आई है।

उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

98. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग
	मी.ट.	मी.ट.	%
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि			
2007-08	485,000	465,586	96%
2008-09	500,000	414,226	83%
2009-10	590,000	491,743	83%
2010-11	674,000	581,508	86%
जांचोत्तर अवधि			
ति.1(11-12) वार्षिकीकृत	724,000	654,113	90%
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	724,004	598,025	83%

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान दोनों प्रकार की क्षमता में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2008-09 को छोड़कर जब उत्पादन में गिरावट आई है, क्षति अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। जांचोत्तर अवधि की ति.1 के दौरान भी वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। परंतु, जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है। आगे यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान इसमें आगे और गिरावट आई है।

मालसूची:

99. मालसूची से संबंधित आंकड़ों से निम्नानुसार पता चलता है :

अवधि	प्रारंभिक स्टॉक	आंतिम स्टॉक	औसत स्टॉक
	मी.ट.	मी.ट.	मी.ट.
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि			
2007-08	8,494	10,025	9,259
2008-09	10,025	9,870	9,948
2009-10	9,870	15,616	12,743
2010-11	15,616	17,554	16,585
जांचोत्तर अवधि			
ति.1(11-12) वार्षिकीकृत	17,554	16,386	16,970
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	16,386	20,876	18,631

	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	ति.1(11-12)	ति.2(11-12)

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि में औसत मालसूची में लगातार वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी के बावजूद जांचोत्तर अवधि की दूसरी तिमाही में मालसूची काफी अधिक थी।

लाभ, और नकद प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

100. लाभ एवं नकद प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव का व्यौरा निम्नानुसार है :

जहां तक लाभ/हानि और नकद प्रवाह का संबंध है, यह पाया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कर और ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है परंतु जांचोत्तर अवधि की ति.1 और ति.2 अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई है।

बिकी की लागत	रु०/मी० ट०	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	124	159	169	186	
बिकी कीमत	रु०/मी० ट०	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	122	149	156	168	
लाभ/हानि	रु०/मी० ट०	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(56)	111	135	54	26	
कर पूर्व लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(55)	130	181	18	7	
पी बी आई टी	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(11.82)	134	185	27	19	
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(42)	127	176	25	13	

101. लगाई गई पूंजी पर आयः

निम्नलिखित तालिका से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई है। तत्पश्चात् जांचोत्तर अवधि की ति.1 और ति.2 अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई है।

	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	जांचोत्तर अवधि (वार्षिकी कृत)	2011-12- ति 1	2011-12- ति.2
पीबीआईटी-घरेलू	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
एन एफ ए	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
नियोजित पूंजी	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
नियोजित पूंजी	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	-12	97	87	45	54	37

रोजगार, मजदूरी और लाभप्रदता

102. रोजगार, मजदूरी और लाभप्रदता से संबंधित आंकड़ों से निम्नानुसार पता चलता है:

अवधि	कर्मचारियों की संख्या	मजदूरी	उत्पादन की प्रति इकाई के अनुसार मजदूरी	प्रति कर्मचारी उत्पादकता
	सं०	रु०/लाख	रु०/लाख	मी०ट०
जांच अवधि के साथ क्षति अवधि				
2007-08	***	***	***	***
2008-09	***	***	***	***
2009-10	***	***	***	***

2010-11	***	***	***	***
जांचोत्तर अवधि				
ति1(11-12) वार्षिकीकृत	***	***	***	***
ति.2(11-12) वार्षिकीकृत	***	***	***	***

यह देखा जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान मुख्यतः नए संयंत्रों में उत्पादन शुरू किए जाने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त प्रवृत्ति के अनुरूप भुगतान की गई मजदूरी और उत्पादकता में भी सुधार प्रदर्शित होता है।

पाटन की मात्रा

103. उपर्युक्त पाटन मार्जिन से संबंधित खंड से यह देखा जाता है कि जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि, दोनों के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है।

वृद्धि

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी परंतु जांचोत्तर अवधि, खासकर जांचोत्तर अवधि की ति.2 के दौरान उसमें गिरावट आई है।

निधियां जुटाने की क्षमता:

105. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि (अर्थात् ति.1.) के दौरान घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की क्षमता में वृद्धि की है। इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की पूँजी जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

द. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

देश	उत्पादक/निर्यातक	पाटन मार्जिन की एनआईपी (रु०/ मी०ट०)	पहुंच कीमत (रु०/ मी०ट०)	क्षति मार्जिन (रु०/ मी०ट०)	% के रूप में क्षति मार्जिन	% के रूप में क्षति मार्जिन रेंज

106. जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

देश	उत्पादक / निर्यातक	पाटन मार्जिन की एनआईपी (रु०/ मी०ट०)	पहुंच कीमत (रु०/ मी०ट०)	क्षति मार्जिन (रु०/ मी०ट०)	% के रूप में क्षति मार्जिन	% के रूप में क्षति मार्जिन रेंज
जांच अवधि						
चीन जन.गण.	मै० जिनेंग साईंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लि. चीन. जन.गण.	***	***	***	***	0-10
	अन्य कोई उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	0-10
रूस	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	0-(10)
आस्ट्रेलिया	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	0-(10)
थाइलैंड	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	(5)-(15)
जांचोत्तर अवधि						
चीन जन.गण.	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	5-15
रूस	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	5-15
आस्ट्रेलिया	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	5-15
थाइलैंड	समस्त उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	0-10

वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष

107. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्से, क्षमता, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है परंतु क्षमता उपयोग और मालसूची के संबंध में इसमें गिरावट आई है। तथापि, जांचोत्तर अवधि, खासकर ति.2 अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता, क्षमता उपयोग, मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इसके अलावा, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी अधिक है।

ण. अन्य ज्ञातकारक और कारणात्मक संबंध

108. कीमत हरासकारी और न्यूनकारी प्रभाव तथा कम कीमत पर बिक्री के संबंध में वास्तविक क्षति की मौजूदगी, मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव जांच करने के बाद प्राधिकारी द्वारा भारतीय नियमावली एवं पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदण्डों की निम्नानुसार जांच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:-

(क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से इतर देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात की मात्रा न्यूनतम रही है, जबकि दक्षिण कोरिया से आयात की कीमत सम्बद्ध देशों की कीमत से अधिक रही है। अतः अन्य देशों से हुए आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले आयातों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

(ख) मांग में कमी और खपत की पद्धति में परिवर्तन:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु की समग्र मांग में अत्यधिक सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है। तथापि, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उपलब्ध मांग की सीमा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसा पर्याप्त परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयातयोग्य है। घरेलू उदयोग सम्बद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है और उसका हिस्सा उत्पादन और बिक्री में पर्याप्त है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादकों के बीच बाजार अर्थव्यवस्था को छोड़कर कोई स्पष्ट प्रतिस्पर्धा नहीं है।

घरेलू उदयोग का निर्यात निष्पादन

निम्नलिखित तालिका में घरेलू उदयोग द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में उसके निष्पादन का संक्षेप में उल्लेख है।

	इकाई	2007–08	2008–09	2009–10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि वार्षिक
मात्रा	मी.ट.	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	63	69	101	157

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उदयोग की निर्यात मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः निर्यात निष्पादन को किसी क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, वर्तमान क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत तथा लाभप्रदता को अलग-अलग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से घरेलू उदयोग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है तथापि, निम्नलिखित मापदण्डों से यह पता चलता है कि घरेलू उदयोग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्से, क्षमता, लाभ, नकद लाभ और लगाई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उदयोग के निष्पादन में सुधार हुआ है, परन्तु क्षमता उपयोग और मार्गसूची के संबंध में उसमें गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि के दौरान और खासकर तिमाही 2 की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता, क्षमता उपयोग, माल सूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उदयोग की समग्र आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इस प्रकार जांचोत्तर अवधि और खासकर तिमाही 2 की अवधि के दौरान लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय, नकद प्रवाह आदि में गिरावट सीधे पाटित आयातों के कारण आई है। बाजार हिस्से में गिरावट से घरेलू उदयोग अपना उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाने से बंधित हुआ है।

त. क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

110. प्राधिकारी को यह निर्धारण करना होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों से पाटित कीमत पर सम्बद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में प्रवेश जारी है अथवा उसका निर्यात किए जाने की संभावना है। इसकी बात की जांच करना ग्रासांगिक है कि शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें अंतर किए जाने की स्थिति में इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उदयोग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से भारत में हुए आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उदयोग की बिकी कीमत से कम था और वह जांचोत्तर अवधि में घरेलू उदयोग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम था। प्राधिकारी ने जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और साक्ष्य के आधार पर घरेलू उदयोग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच भी की है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदण्डों पर विचार करते हुए पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की। नियम में निम्नानुसार उल्लेख है:

“वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

घरेलू उदयोग के अनुरोध

111. घरेलू उदयोग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- (क) समीक्षा अवधि में निरंतर पाटन और क्षति के अभाव का तात्पर्य पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना से नहीं है।
- (क) सम्बद्ध देशों के निर्यातक तीसरे देशों में में पाटन कर रहे हैं जिससे भारत में पाटन की संभावना का पता चलता है।
- (ग) निम्नलिखित कारकों से पाटन एवं क्षति जारी रहने की संभावना की पुष्टि होती है।

- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद सम्बद्ध देशों से आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
- सम्बद्ध देशों के उत्पादकों के पास कार्बन ब्लैक का उत्पादन करने के लिए विशाल क्षमताएं हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात मात्रा में आगे वृद्धि होना लाजमी है।
- पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित आयातों के पहुंच मूल्यों की तुलना, घरेलू उदयोग की बिक्री कीमत के साथ किए जाने पर यह देखा जाएगा कि कीमत में अत्यधिक कटौती मौजूद है।
- सम्बद्ध देश का भारतीय बाजार में काफी अधिक बाजार हिस्सा है। वस्तुतः पाटित आयातों के बाजार हिस्से में ही वृद्धि हुई है। यह स्थिति वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद बनी हुई है।
- सम्बद्ध देशों के निर्यातिक विश्व भर में अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।
- पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी के कारण घरेलू उदयोग पाटन के पिछले प्रभावों से उबरने से वंचित हुआ है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उदयोग को या तो पाटनरोधी शुल्क की राशि तक बिक्री कीमत घटानी होगी या फिर वर्तमान बिक्री कीमत बनाए रखनी होगी। किसी भी स्थिति में उसे क्षति होगी।

याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

112. याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. घरेलू उदयोग का निष्पादन स्थिर है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के बाद भी घरेलू उदयोग को क्षति नहीं होगी। पूर्वर्ती अनुरोधों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना

जांचोत्तर अवधि में भी घरेलू उदयोग का निष्पादन पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रहा है।

- ख. सम्बद्ध देशों द्वारा तीसरे देशों में पाटन से संबंधित घरेलू उदयोग का आरोप अप्रमाणिक है। यदि यह स्थिति वास्तव में रही होती तो पाटनरोधी शुल्क की कार्रवाई शुरू नहीं की गई होती और उन देशों में भी पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया होता।
- ग. घरेलू उदयोग अपने इस दावे की पुष्टि करने में समर्थ नहीं रहा है कि सम्बद्ध देशों में बेशी क्षमता है।
- घ. इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि घरेलू उदयोग को 2010 में, जब चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी क्षमता थी, क्षति नहीं हुई थी। चीन में बेशी क्षमता का भारतीय बाजार पर भविष्य में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

113. भारत के पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में प्राधिकारी के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समय—समय पर जांच करनी अपेक्षित होती है। याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा जांच में निर्णायक समीक्षा के मामले की तरह संभावना के पहलुओं की जांच अपेक्षित नहीं होती है। तथापि, प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसी किसी जांच में परिवर्तित परिस्थितियों के स्थायी स्वरूप और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावना के परिदृश्य की जांच भी शामिल होगी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटन की परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी स्वरूप की हैं और क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उदयोग को भविष्य में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की है। प्राधिकारी ने जांच अवधि और जांच अवधि के तत्काल परवर्ती अवधि के लिए सहयोगी निर्यातकों से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

जांचोत्तर अवधि में निर्यातों की मात्रा:

114. सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उदयोग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने जांचोत्तर अवधि के दौरान भी सम्बद्ध देशों से भारत तथा अन्य देशों को किए गए सम्बद्ध वस्तु के निर्यात की मात्रा का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से भारत को किए गए निर्यात की मात्रा क्रमशः 46114 मी.ट. और 78606 मी.

ट. “वार्षिक” रही थी जिसमें 70 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। इस प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि भारत में पाटित आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे अत्यधिक आयात किए जाने की संभावना का पता चलता है।

भारतीय बाजार में सम्बद्ध देशों का बाजार हिस्सा

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद सम्बद्ध देशों का बाजार हिस्सा, जिसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है उसमें जांचोत्तर अवधि की तिमाही 2 की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। इसके विपरीत जांचोत्तर अवधि के दौरान जहां अन्य घरेलू उत्पादों के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है वहीं तदनुरूपी अवधि के दौरान घरेलू उदयोग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उदयोग के बाजार हिस्से पर सम्बद्ध देशों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा समग्र घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में भी भारी गिरावट आई है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

116. सम्बद्ध देशों द्वारा भारत को सम्बद्ध वस्तु का जिस कीमत पर निर्यात किया जा रहा है वह पाटन जारी रहने की संभावना का एक संकेतक है। भारत में पहुंच कीमत पर जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान शुल्क सहित और रहित, दोनों रूप में कीमत में भारी कटौती हुई है। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में विदेशी उत्पादकों के लिए भारतीय कीमतें और अधिक आकर्षक बन जाएंगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई मांग के कारण भारी मात्रा में आयात करना होगा।

विदेशी उत्पादों का निर्यात अभियुक्तीकरण

117. उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट होती है कि सम्बद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के पास विशाल उत्पादन क्षमता है और वे अत्यधिक निर्यातोनुखी भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि और उसकी लाभकारी कीमत पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में समूची मांग की पूर्ति सम्बद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा की जा सकती है।

वेशी क्षमता

	मात्रा : '000 मीट.						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012एफ	2015एफ
चीन							
क्षमता	1100	2310	4349	5100	5490	5900	6400

खपत	764	1620	2758	2860	2920	3060	3750
अधिकता	336	690	1591	2240	2570	2840	2650
रूस							
क्षमता	638	703	683	683	718	858	945
खपत	287	345	234	297	343	380	425
अधिकता	351	358	449	386	375	478	520
थाइलैण्ड							
क्षमता	220	370	385	465	465	515	515
खपत	132	200	240	314	350	367	400
अधिकता	88	170	145	151	115	148	115
स्रोत :							
कार्बन ब्लैक वर्ल्ड द्वारा बुल 2012							
नोच कंसलटिंग ग्रुप							
[प्रकाशित जन..2012]							

118. उपर्युक्त तालिका में दिए गए अनुसार घरेलू उदयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि 4 सम्बद्ध देशों में से 3 चीन जन-गण, रूस और थाइलैण्ड के पास सम्बद्ध वस्तु की अत्यधिक बेशी क्षमता है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि तथा अनुकूल कीमतों पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातयोग्य बेशी वस्तु पाटित कीमत पर भारतीय बाजार में आ सकती है।

वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

119. प्राधिकारी द्वारा पूर्वकी जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और अब निर्धारित पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि निर्यातों को पाटित कीमतों पर किया जाना जारी है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उनके जारी रहने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान जांच अवधि में आयातों की मात्रा मूल्य जांच अवधि से भी अधिक है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिकी को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात मात्रा में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।
120. इससे यह सिद्ध होता है कि सम्बद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी सम्बद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं। अतः भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों के निर्यातकों के लिए पाटित कीमतों पर भारत को सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करने में कठिनाई नहीं होगी। यह भी नोट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद सम्बद्ध देश से भारत में पाटन जारी है।
121. जहां तक घरेलू उदयोग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का संबंध है। जिस कीमत स्तर पर लागू शुल्क के बावजूद सम्बद्ध देश से भारतीय बाजार में वस्तु प्रवेश कर रही है, वह एक प्रमुख संकेतक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कई क्षति मापदण्डों में घरेलू उदयोग की स्थिति में सुधार होने के बावजूद जांचोत्तर अवधि, खासकर तिमाही 2 की अवधि के दौरान उत्पादन, बिकी मात्रा, क्षमता, क्षमता उपयोग, माल सूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उदयोग की समग्र आर्थिक स्थिति खराब हुई है। अतः जांचोत्तर अवधि, खासकर तिमाही 2 की अवधि के दौरान लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय, नकद प्रवाह आदि में गिरावट पाटित आयातों के कारण आई है।
122. इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार जांच के आवश्यक तथ्यों से पूर्णतः यह सिद्ध होता है कि जिन परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर आटोमोबाइल टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने मध्यावधि समीक्षा की जांच की है, वे स्थायी स्वरूप की नहीं है और सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने/उसमें तेजी आने तथा पाटनरोधी शुल्क में कमी/उसकी समाप्ति की स्थिति में घरेलू उदयोग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

थ. घरेलू उदयोग का हित और अन्य मुद्दे

123. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उदयोग का हराश रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए सम्बद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कार्यकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से सम्बद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के 2 या अधिक स्रोत रख सकते हैं।
124. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उददेश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उदयोग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

द. प्रकटन विवरण के बाद टिप्पणियां

125. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्द वक्षकारों की प्रकटन विवरण प्रश्चात टिप्पणियां निम्ननुसार हैं—
- i. प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण प्रश्चात टिप्पणियों के लिए अपर्याप्त समय दिया गया है।
 - ii. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षति रहित कीमत आदि की गणना के बारे में अत्यधिक गोपनीयता।
 - iii. विशिष्ट कारणों का उल्लेख किए बिना लगाए गए पूँजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति औचित्यपूर्ण नहीं है।
 - iv. यदपि रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, तथापि डीजीएडी ने क्षति तथा क्षति की संभावना का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया है।
 - v. प्रकटन विवरण इस दृष्टि से स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने घरेलू उदयोग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत घटाने पर विचार किया है।
 - vi. थाइलैण्ड में सम्बद्ध वक्षकार द्वारा सम्बद्ध वस्तु के भारी निर्यातों के मददेनजर हाईटैक कार्बन को घरेलू उदयोग के दायरे में लाना न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा, प्रकटन विवरण में हाईटैक कार्बन को घरेलू उदयोग के दायरे में लाने को न्यायोचित ठहराने के

समय घरेलू उदयोग द्वारा विचारित प्रत्येक कारक के संबंध में विशिष्ट जांच परिणाम निहित नहीं है।

- vii. यद्यपि डीजीएडी ने यह माना है कि सम्बद्ध निर्यातिक के जरिए किए गए शुल्क मुक्त आयातों का घरेलू उदयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि, साथ ही साथ डीजीएडी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ ऐसे आयातों को अलग नहीं किया है।
- viii. क्षति विश्लेषण करते समय प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आवश्यक है।
- ix. पिछले चार वर्षों और जांच अवधि की पहली तिमाही के दौरान घरेलू बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में लगातार सुधार हुआ है। केवल जांचोत्तर अवधि की दूसरी तिमाही के दौरान मात्रात्मक मापदण्डों में गिरावट प्रदर्शित हुई है। ऐसा मामला होने के कारण यह मानना गलत होगा कि घरेलू उदयोग को क्षति होने की संभावना है।
- x. घरेलू उदयोग को समीक्षा अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है और वस्तुतः लाभ, बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
- xi. घरेलू उदयोग को इस समय कोई क्षति मौजूद नहीं है और न ही घरेलू उदयोग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना है।
- xii. डीजीएडी ने यह माना है कि चीन में बेशी क्षमता की मौजूदगी के परिणामस्वरूप भारत में पाटन हो सकता है। अनुरोध है कि चीन जन-गण में काफी पहले से बेशी क्षमता है और उससे भारतीय बाजार पर किसी भी रूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xiii. प्रकटन विवरण के पैरा 105 से यह पता चलता है कि डीजीएडी ने रूप, आस्ट्रेलिया और थाइलैण्ड के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन निकाला है। चूंकि धारा 9क (1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन से कम रखा जाना है तथापि, डीजीएडी इन दोनों मार्जिनों में से कम तर आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए अधिदेशित हैं।
- xiv. चूंकि डीजीएडी ने मूल जांच के दौरान जिंगडेझैन की एम जैड से उत्तर दायर करने के लिए नहीं कहा, इसलिए अब ब्लैक कैट को असहयोगी मानना औचित्यपूर्ण नहीं है।
- xv. यारोसलावस्की और द्वायगन के संबंध में निर्यात दस्तावेजों में परेषिती देश के रूप में कोलम्बो का उल्लेख एक तकनीकी चूंक है जिसका जांच परिणामों पर कोई वित्तीय या अन्य प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए प्राधिकारी इसकी अनदेखी कर सकते हैं।

- xvi. द्रायगन द्वारा ओ एम एस के – रूस के उत्पाद के निर्यात की मात्रा अत्यंत कम है और इसीलिए प्रश्नावली का उत्तर दायर करना न्यायोचित नहीं है।
- xvii. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 6क के अनुसार डीजीएडी के पास किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा प्रदत्त सूचना को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है।
- xviii. निर्यात प्राप्ति में से अप्रत्यादेय वैट की कटौती करने का कोई आर्थिक तर्काधार या कोई विधिक आधार नहीं है।

126. घरेलू उदयोग की प्रकटन विवरण प्रश्नात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

- i. वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है इसलिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु लागू कार्य प्रणाली वही रहनी चाहिए जिसे मूल जांच में लागू किया गया था।
- ii. वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि शुल्क को पाटन और परिणामी क्षति के आधार पर लागू किया गया है।
- iii. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों से हाई टैक कार्बन ब्लैक को घरेलू उदयोग के दायरे से अलग रखना न्यायोचित नहीं है।
- iv. शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों को घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव न डालने वाला नहीं माना जा सकता।
- v. क्षति रहित कीमत और निवल बिकी प्राप्ति के बीच अंतर पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण के मापदण्डों में से एक मापदण्ड होता है, परन्तु यह एकमात्र मापदण्ड नहीं है।
- vi. यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उदयोग ने उत्पादन, घरेलू बिकी, उत्पादकता, लाभ, नकद लाभ, लगाई गई पूँजी पर आय आदि जैसे आर्थिक मापदण्डों में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है तथापि, जांचोत्तर अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस चरण पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उदयोग को भारी क्षति होगी।
- vii. मध्यावधि समीक्षा में जांच में परिवर्तित परिस्थितियों की स्थायी प्रकृति और शुल्क समाप्ति की स्थिति में संभावना की जांच शामिल होगी।

viii. घरेलू उदयोग द्वारा कार्बन ब्लैक की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादित लीन गैस को दिए गए व्यवहार के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण सही नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात की गई टिप्पणियां उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का अधिकांशतः अपुष्टिकृत दोहराव हैं। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्रकटन विवरण पश्चात टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:-

- i. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पश्चात टिप्पणियों के लिए अपर्याप्त समय दिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
- ii. जहां तक सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षति रहित कीमत आदि की गणना के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार अगोपनीय तथ्यों/आंकड़ों को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया गया था और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, क्षति रहित कीमत आदि की गणना की कार्यप्रणाली का इस जांच परिणाम में स्पष्ट प्रकटन किया गया है। इसके अलावा, सम्बद्ध पक्षकारों और घरेलू उदयोग को निर्यात कीमत तथा क्षति रहित कीमत के ब्यौरे प्रदान किए गए थे।
- iii. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट कारण बताए बिना लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय की अनुमति देना प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया है।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यद्यपि रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई थी तथापि, डीजीएडी ने क्षति और क्षति की पुनरावृत्ति का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार के व्यवहारों से उत्पन्न दो अलग स्थितियों से निपटने के लिए दोनों उपाय अलग—अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि इस जांच परिणाम में सिद्ध किया गया है, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उदयोग को परिणामी क्षति की पुनरावृत्ति होने/इसमें तेजी आने की संभावना है।
- v. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने घरेलू उदयोग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्रमुख कच्ची

सामग्री की कीमत में कटौती पर विचार किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण सत्यापित आंकड़ों के आधार पर नियमानुसार किया गया है।

- vi. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि हाईटैक कार्बन के थालैण्ड स्थित सम्बद्ध पक्षकार द्वारा सम्बद्ध वस्तु के भारी मात्रा में निर्यातों को ध्यान में रखते हुए उसे घरेलू उदयोग के दायरे में शामिल करना न्यायोचित नहीं है और प्रकटन विवरण में हाईटैक कार्बन को घरेलू उदयोग के दायरे में लाने को न्यायोचित ठहराते समय घरेलू उदयोग द्वारा विचारित प्रत्येक तथ्य के संबंध में विशिष्ट जांच परिणाम निहित नहीं हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उदयोग के रूप में हाईटैक कार्बन पर विचार करते समय नियमानुसार समस्त संगत मापदण्डों पर विचार किया गया है।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 6क के अनुसार डीजीएडी को निर्यातक या उत्पादक द्वारा प्रदत्त सूचना को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने मैसर्स यारोसलावर्स्की टैक्नीकैस्की अगलेरॉड (उत्पादक) और मैसर्स द्रायगन गल्फ, एफ जैड सी यू दुबई, यू ऐ ई द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं क्योंकि इन्हें इस जांच परिणाम में पहले से दर्ज कारणों से भरोसेमंद और समुचित संदेह रहित नहीं पाया गया था।
- viii. जहां तक जिनेना द्वारा किए गए इस अनुरोध का संबंध है कि निर्यात आय में से अप्रत्यादेय वैट की कटौती करने का कोई आर्थिक तर्काधार या कोई कानूनी आधार नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत का निर्धारण सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत और नियमों पर विचार करते हुए किया गया है।
- ix. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने यह अनुरोध किया है कि केवल 3 माह के निष्पादन के आधार पर प्राधिकारी द्वारा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का निष्कर्ष गलत और अनुचित है। इस संबंध में प्राधिकारी वर्ष 2011–12 के लिए घरेलू उद्योग के लेखापरीक्षित लेखों से यह नोट करते हैं कि जांच अवधि की तुलना में ब्याज एवं कर पूर्व लाभ तथा निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में भारी गिरावट आई है।
- x. जहां तक क्षति रहित कीमत के निर्धारण में विद्युत की बिक्री पर प्राप्त लाभ पर विचार न किए जाने के बारे में घरेलू उदयोग की टिप्पणी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्बन ब्लैक के विनिर्माण में उत्पन्न लीन गैस का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है और ऐसी लीन गैस के लिए कोई मूल्य नहीं रखा गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उदयोग ने उसके द्वारा उत्पादित विद्युत के एक भाग की बिक्री बाहरी

पक्षकारों को की है और लाभ कमाया है। इस संबंध में घरेलू उदयोग द्वारा किए गए अनुरोधों के गोपनीय रूपांतरण की जांच की गई है और उनमें कोई गुण नहीं पाया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने कार्बन ब्लैक का उत्पादन करते समय उत्पन्न लीन गैस से उत्पादित विद्युत की बिकी पर लाभ को समायोजित करने के बाद क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है।

घ. निष्कर्ष

128. एटीएमए द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार समीक्षा शुरू कर उसे सम्पन्न करने के बाद और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों द्वारा प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों एवं हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों अथवा इस जांच परिणाम में अन्यथा दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति की वर्तमान तथा संभावित स्थिति और पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद सम्बद्ध देशों का भारतीय बाजार में एक बड़ा हिस्सा है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क के साथ भी सम्बद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू बिकी कीमत से कम है।
- iii. सम्बद्ध देशों से निर्यातों के कारण जांच अवधि और जांचोत्तर अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क के बिना भी कीमत में सकारात्मक कटौती हो रही है और जांचोत्तर अवधि में कम कीमत पर बिकी सकारात्मक है।
- iv. जांच अवधि, जांचोत्तर अवधि, खासकर तिमाही 2 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षति मापदण्डों में घरेलू उदयोग की स्थिति में सुधार होने के बावजूद उत्पादन, बिकी मात्रा, क्षमता, क्षमता उपयोग, मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूँजी पर आय आदि के संबंध में घरेलू उदयोग की समग्र आर्थिक स्थिति खराब हुई है। इस प्रकार जांचोत्तर अवधि, खासतौर पर तिमाही 2 की अवधि के दौरान लाभ, लगाई गई पूँजी पर आय, नकद प्रवाह आदि में गिरावट सीधे पाटित आयातों के कारण आई है।
- v. पाटन एवं क्षति की परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी स्वरूप की नहीं हैं और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति होने या इसमें तेजी आने की संभावना है।

न. सिफारिश

129. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि घरेलू उदयोग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण पाटन एवं क्षति

जारी रहने/पुनः शुरूआत होने/उसमें तेजी आने की संभावना है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में उपाय की अवधि बढ़ाने की जरूरत है।

130. प्राधिकारी ने मैसर्स जियांगसी ब्लैक कैट कार्बन इंक लिंग, जिंगडेझैन, चीन जन-गण और मैसर्स यारोसलावस्की टैक्नीकैस्की अगलेराड, रूस और उसके सम्बद्ध निर्यातक मैसर्स द्वायगन गल्फ एफ जैड सी ओ, यू ए ई द्वारा दायर उत्तरों को इस जांच परिणाम में पहले से दर्ज कारणों से स्वीकार नहीं किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इन पक्षकारों के लिए किसी विशिष्ट शुल्क की सिफारिश नहीं करते हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के ऐसे किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक, जिसे मूल जांच में विशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया था, ने इस मध्यावधि समीक्षा जांच में सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी चीन जन-गण के अन्य प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मैंग जिनेंग साईंस एंड टैक्नोलॉजी कंपनी लिंग को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपित परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी स्वरूप की नहीं पाई गई हैं और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने या उनमें तेजी आने की संभावना है, के लिए विशिष्ट शुल्क की सिफारिश नहीं करते हैं।

131. प्राधिकारी द्वारा 24 दिसम्बर, 2009 के अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डीजीएडी के तहत संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की पूर्व में सिफारिश की थी और केन्द्र सरकार ने 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संग्रह 6/2010-सी.शु. के तहत शुल्क लगाया था। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित तालिका में यथा विर्निदिष्ट पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु विवरण*	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	0.330	कि.ग्रा.	अम.डा.
2.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	कोई	0.330	कि.ग्रा.	अम.डा.

3.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	कोई	आस्ट्रेलिया	कोई	कोई	0.330	कि.ग्रा.	अम.डा.
4.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	चीन जन:गण	चीन जन:गण	कोई	कोई	0.423	कि.ग्रा.	अम.डा.
5.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	चीन जन:गण	कोई	कोई	कोई	0.423	कि.ग्रा.	अम.डा.
6.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	कोई	चीन जन:गण	कोई	कोई	0.423	कि.ग्रा.	अम.डा.
7.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	रूस	रूस	कोई	कोई	0.391	कि.ग्रा.	अम.डा.
8.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	रूस	कोई	कोई	कोई	0.391	कि.ग्रा.	अम.डा.
9.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	कोई	रूस	कोई	कोई	0.391	कि.ग्रा.	अम.डा.
10.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	थाइलैण्ड	थाइलैण्ड	कोई	कोई	0.186	कि.ग्रा.	अम.डा.
11.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	थाइलैण्ड	कोई	कोई	कोई	0.186	कि.ग्रा.	अम.डा.
12.	28030010	‘रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाला कार्बन ब्लैक’ *	कोई	थाइलैण्ड	कोई	कोई	0.186	कि.ग्रा.	अम.डा.

*टिप्पणी: अद्व्यालक योगिक अनुप्रयोगों के लिए नित थर्मल ब्लैक और कार्बन ब्लैक को विचारधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाता है।

प. आर्ग की प्रक्रिया

132. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमा शुल्क शामिल होंगे।

133. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

FINAL FINDING

Subject : Mid-term Review (MTR) anti-Dumping investigation concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications', originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand.

No. 15/41/2010-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time, (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules);

A. Background of the case:

- Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had notified its final findings vide Notification No.14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009, recommending imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of "Carbon Black used in rubber applications" (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries). The definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 6/2010-Customs dated 28th January, 2010.
- Whereas M/s Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), hereinafter referred to as the applicant, submitted an application for mid-term review (MTR) on behalf of the importers and users of the subject goods. The applicant requested for conducting a mid-term review (MTR) of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, claiming that the circumstances that were prevalent during the original investigation have changed significantly during the POI proposed by them, leading to a situation where the existing antidumping duties are no longer warranted.

B. Initiation

3. And whereas Rule 23 of the Rules read with Section 9A of the Act require that the Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
4. Having regard to the information provided by the applicant substantiating the need for such review and indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority, vide Notification No. 15/41/2010-DGAD dated 30th August, 2011, initiated the subject Mid-term Review (MTR) investigation of the final findings notified vide Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No.6/2010-Customs dated 28th January, 2010, to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties.

C. Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i) The Authority sent copies of the initiation notification dated 30th August, 2011 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
- ii) Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters, domestic producers and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iii) The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the MTR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:

834 90/13-23

Carbon Black Producers/Exporters in Australia

- | |
|---|
| 1. MIs Continental Carbon Australia Pty Ltd.
Sir Joseph Banks Drive
Kurnell NSW 2231, Australia
Phone: 9668 9177 |
| 2. Cabot Australia Pty. Ltd
P.O. Box 829, Torquay,
Victoria 3228,
Australia |

Carbon Black Producers/Exporters in China PR

- | |
|---|
| 1. Hebeijing Country Xinyuan Rubber Chemical Co Ltd., Shengli Road
Guangsha District 31-1-101, Hengshui City, Hebei Province, P.R.China |
| 2. Hebei Yonghui Chemical Industries Import And Export Co., Ltd., No.199,
Xinhua Road, Shijiazhuang, Hebei, P. R. China-311101 |
| 3. Laiwu Taishan Carbon Black Co., Ltd., Gaozhuang Industrial Zone,
Laicheng, Laiwu, P.R.China -271122 |
| 4. Qichang Chemical Co., Ltd., Beichenwang, Tangyin County, Anyang
City, Henan Province, P. R. China |
| 5. Tianjin Dolphin Carbon Black Ltd., East Of Railway, North Of
YinheqiaoBeichein District, Tianjin, P.R.China 300400 |
| 6. MIs Hebei Daguangming Juwuba Carbon Black Co., Ltd.
South of Donghuan Road,
Shahe City, Hebei Province, China – 054100
Ph: 86-319-8707022 |
| 7. MIs Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd ("Black Cat")
Liyaojingdnezen City
Jiangxi Province, PR China – 333000
Ph: 86-798 839 9126 |
| 8. Suzhou Boahua Carbon,
Xushuguan Suzhou, China-215151
Ph: 0086-512-653 |
| 9. MIs Ningbo Detai Chemical Co. Ltd.
No. 699, Fengxiang Road,
Ningbo Chemical Industry Zone (Xiepu, Zhenhai)
Ningbo City, Zhejiang Province, China |
| 10. MIs Longxing Chemical Stock Co., Ltd.
No.1, Longxing Street, Donghuan Road,
Shahe City, Hebei, China
Ph: 86- 3198869003 |
| 11. MIs Ningbo Sheen - All Chemical Co., Ltd.
R.M. 6C2-6D2, Xinjingjiang Building,
No. 419 Lingqiao Road, Ningbo City, PRC- 315000
Ph: 86-574-87255359 |
| 12. China Rubber Industry Association |

North Yinhe Bridge
 Beichengdu, Tianjin-300400
 China
 Ph: 86-22-27276558

13. M/s Jinneng Science & Technology Co. Ltd.,
 No.1 Jinneng Street, Qihe, Shandong, China
14. China Rubber Group Carbon Black Research and Design Institute
 No.568, Huixing Road, Huidong Dist., Zigong City
 Sichuan, PR China

Carbon Black Producers/Exporters in Russia

1. Omsktechuglerod OJSC
 644049, barabinskaya Street, 20,
 Omsk, Russia
 Ph: (3812) 42-02-63
2. MIs. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod
 Yaroslavl, 150000,
 Russia
3. MIs Trigon Gulf FZCO
 No. MO 0743, Jafza
 PO Box 61468, Dubai, UAE
 Ph: 971 48819337
4. Amtel Holding Company, Amtel House 45 Kutuzovsk,
 Prospekt, 121170 Moscow, Russia.
5. Severgazprom,
 39/2 Lenin Street UkhtaKomi, Republic of Russian Federation
6. Nizhnekamsk Carbon Black Plant
 423570 Nizhniekamsk , Prombaza Republic of Tartarstan

Carbon Black Producers/Exporters in Thailand

1. Thai carbon Black, 44 Mool, Ayuthaya -Angthong Highway,
 TambolPasa, AmphurMuang, Angthang 14000
2. Thai Tokai Carbon Product Co., Ltd. 9th Floor, Harindhorn Tower,
 54 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
3. Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd., Rojana Industrial
 Park, Ban Khai District, Rayong Province, Thailand

- iv) In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:

Sl.No.	Name of producer/exporter	Country
1.	M/s Jiangxi Black Cat Carbon Inc. Ltd., Jingdezhen, China PR	China PR
2.	M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd. China PR	China PR
3.	M/s. Shanghai Hyun Tong Industry International Co. Ltd. China PR	China PR
4.	M/s. Suzhou Baohua Carbon Black Co. Ltd. China PR	China PR
5.	M/s. YaroslavskiyTekhnicheskiyUglerod, Russia	Russia
6.	M/s Trigon Gulf FZCO, UAE	UAE

- v) Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

1	M/s Apollo Tyres Ltd, Apollo House 7, intuitional Area, Sector-32, Gurgaon - 122001 (Haryana)
2	M/s J. K. Tyre& Industries Ltd. Link House, 3 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
5	M/s Goodyear South Asia Tyres Pvt. Ltd. H-18 MIDC Industrial Area WalujAurangbad.
4	M/s Goodyear India Ltd. Matura Road Ballabgrah, Faridabad, Haryana 121004
5	M/sCabot India Ltd. NKM International House, 178, Backbay Reclamation, BabhubhaiChinai Marg,, Mumbai 400020
6	M/SGeneral Rubbers P. John Zachariah Buildings Kottayam – 686001, Kerala

7	Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), PHD House (4th Floor), Opp. Asian Games Village, Siri Institutional Area, New Delhi-110016
8	All India Rubber Industries Association 1009, Padma Tower , 15 Rajindra Place, New Delhi-L10008
9	M/S Gem Poly Tech Industries Pvt. Ltd Garden Lane, Beliaghata, Kolkata - 700010, West Bengal

vi) In response to the above notification, following importers/ users have filed importer questionnaire response.

- a) M/s Ceat Limited
- b) M/s. JK Tyre & Industries Ltd
- c) M/s. Apollo Tyres Ltd.

vii) Questionnaires were also sent to the known domestic producers of the subject goods in India for necessary information and response.

1. Association of Carbon Black Manufacturers 5A, Raba Kailash, 55/4 Ballygunge Circular Road, Calcutta 700019
2. Phillips Carbon Black Ltd 31, NetajiSubhas Road, Kolkata 700001
3. Hi-tech Carbon Murdhwa Industrial Area P.O. Renukoot DisttSonebhadra (UP) 231217
4. Continental Carbon India Ltd A-14 Industrial Area No 1 South Side of GT Road, Ghaziabad-201001
5. M/s Cabot India Ltd. NKM International House, 178, Backbay Reclamation, BabhubhaiChinai Marg., Mumbai 400020

viii) M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s. Hi-Tech Carbon, the domestic producers of the subject goods constituting domestic industry in the subject investigation, have filed response/submissions along with injury related information/data.

ix) Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

x) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations, which was

received by the Authority. The domestic industry provided information with regard to imports based on IBIS data (secondary source). The Authority has, however, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.

- xii) Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules.
- xiii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2010 to 31st March, 2011 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI. The Authority also called relevant information/data from the interested parties for post POI (1st April 2011 to 30th Sep. 2011) for conducting likelihood analysis.
- xiv) In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 20th April, 2012 and 30th October, 2012. The parties, which presented their views in both the oral hearings, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xv) The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this disclosure. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the co-operating producers/exporters.
- xvi) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties vide a disclosure statement issued on 22nd February, 2013 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been considered in this finding.

- xvii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
- xviii) The competent Authority has extended the time period for completing the subject investigation up to 28.02.2013.
- xix) *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx) The average exchange rate of 1US\$ = Rs 46.18 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

6. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation was 'Carbon Black used in rubber application'. In the original investigation the product was defined as under:

"5. The product under consideration is 'Carbon Black used in rubber applications'. It is an inorganic chemical used in production/ processing of rubber (including tyres), as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, lampblack, thermal black, and noir de carbone. Carbon black can be divided into two categories – rubber and non-rubber applications Carbon black. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation.

6 The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under Subheading No. 28030010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."

7. None of the importers, consumers, exporters, domestic industry and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles. The applicant submitted that they have no issues regarding the product under consideration and like article. In view of the above, the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as that in the original investigation.

E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**Submissions made by the Petitioner (ATMA), Exporters, Importers and Other Interested Parties**

8. Following submissions have been made by the applicant (ATMA), Exporters, Importers and other interested parties with regard to standing and scope of the domestic industry:
- i. M/s Hi-Tech Carbon, one of the constituents of the domestic industry in the original investigation, is related to a producer and exporter of the subject goods from Thailand, namely M/s Thai Carbon Black Co Ltd. The said related producer/exporter had made substantial exports to India during the period of investigation and also not filed questionnaire response. In view of the above Hi-Tech Carbon is ineligible to become the domestic industry and therefore the level of injury if any suffered by the domestic industry should be determined based on the performance of Phillips Carbon Black alone.
 - ii. The Designated Authority has no discretionary power to permit Hi-Tech Carbon having a related producer/exporter in the subject country as domestic industry under the Rules.
 - iii. The argument of domestic industry that ATMA filed an application for mid-term review already considering Hi-Tech as domestic industry is devoid of any merit. Filing a petition giving details of Hi-Tech does not mean that ATMA concedes that Hi-Tech is a part of domestic industry.
 - iv. Domestic industry has made another baseless submission that ATMA has suppressed the fact that it did not disclose information about duty-free imports made by its members. It is submitted that some of the members filed their importers questionnaire response in response to the initiation of investigation. Furthermore, upon receiving a letter from DGAD, majority of members provided the information sought by DGAD. Thus, there is no suppression of facts as has been claimed by domestic industry.
 - v. Domestic industry has claimed that since imports from related exporter are under duty free scheme, domestic industry should not be excluded as such imports are not affecting domestic industry. The DGAD should therefore exclude all the imports made under advance license scheme from all the subject countries, and only thereafter should conduct injury and threat of injury analysis.
 - vi. From the websites of Phillips Carbon Black Ltd (PCBL) and Ceat Ltd, it is evident that one of the Directors of PCBL is the Managing Director of CEAT Ltd, an importer of subject goods from subject

countries. Hence PCBL also needs to be excluded from the scope of domestic industry.

- vii. As per Rule 25 of the AD Rules, Hi tech Carbon and M/s. Phillips Carbon Black Limited cannot be treated as domestic producers of the subject goods as they are only making a value addition of just 15% to the raw material that is predominantly imported into India from third country.

Submissions made by Domestic Industry

9. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing of the domestic industry:

- a) The common director in PCBL and CEAT has not attended any board meeting in the relevant period and therefore cannot be termed as having impacted through their relationship in term of Rule 2(b).
- b) Hi-Tech Carbon should be considered as an eligible domestic producer despite exports by their affiliated companies in subject countries in view of (i) past decision of the Designated Authority in this regard at the time of original investigations, (ii) low volume of exports by the related producers, (iii) production of the company in India being quite significant, (iv) focus of the company being on domestic production instead of imports.
- c) Production by the respondent domestic producers constitutes a major proportion in Indian production; domestic producers expressly supporting the extension of Anti-dumping duty account for more than 50 percent of total production of the like product produced by the domestic industry.
- d) The mere fact that one or more domestic producers of the product have themselves imported the product does not imply that such domestic producers should not form part of the domestic industry.
- e) The petitioner has withheld vital fact from the authority that imports from Thailand from TCB were under duty exemption scheme. Out of total exports of Carbon Black by TCB to India during period of investigation, only ***% of the total exports are duty paid and rest all the exports made by TCB are under advance license. Since these imports are under duty exemption scheme, in any case, this do not disentitle Hi-Tech from being considered as part of domestic industry
- f) The Hon'ble Chennai High Court in the matter of Nirma Ltd. vs. Saint Gobain Glass India Ltd., has held that the Designated Authority has discretion under Rule 2(b) and the amendment dated 27th Feb., 2010 has not taken away the discretionary power of the Designated Authority.
- g) In the original investigation the Designated Authority exercised its discretion and came to the conclusion that that Hi-Tech Carbon is eligible

8344713-25

domestic industry. The opposing interested parties have not challenged the same at the time of original investigation or thereafter.

- h) The applicants have filed the application for initiation of Mid-term review considering Hi-tech Carbon as domestic industry. The applicant seems to have now taken a U-turn and now stating that Hi-Tech is not an eligible domestic industry. If the argument of the applicant is considered, then the whole basis of their application along with their claim of good performance by the domestic industry (which includes Hi-Tech) does not hold good and therefore the whole investigation is bad and without any factual basis.
- i) The volume of exports from the related party accounts for mere ***% and ***% in the total Indian production and demand respectively. It cannot therefore be said that the exports made by the related exporter is significant.
- j) Hi-Tech Carbon is the second largest producer of carbon black in India, covering approximately ***percent of the domestic market share. The focus of the company is on domestic production.
- k) The responding companies have not imported the product under consideration during the period of investigation from subject countries.
- l) There is no automatic exclusion of the related domestic producer from the ambit of domestic industry. Various WTO members have determined the eligibility of the related domestic producers based on facts and circumstances of the case.
- m) Petitioner has compared the exports made by Thai Carbon with total exports from Thailand or production of Hi-Tech Carbon. Either of the two parameters is not adopted either by the Designated Authority or other investigating authorities. On the contrary, the established practice in this regard clearly is that the Designated Authority and the investigating authorities consider such imports in relation to production and consumption in India.
- n) Despite repeated arguments of the domestic industry, the petitioner has not disputed that these imports have been made by its members under advance licenses. Thus, such imports only supplement the production effort and not substitute the production efforts of Hi-Tech Carbon. It is established practice of the Designated Authority and investigating authorities that imports made to supplement the production efforts should not be considered as sufficient reason to treat such company as ineligible.
- o) Imports from Thailand in the post-POI period have significantly declined as evident in the table below.

Year	Imports from Thailand (MT)
2008-09	***
2009-10	***
2010-11	***
Q1 2011-12	***
Q2 2011-12	***
Q3 2011-12	***

- p) It is the consumers, being represented by ATMA in the present case, who are resorting to duty free imports from various sources. They are unwilling to give domestic industry a price equivalent to its selling price minus duty benefit (the maximum that the domestic industry can do in such situations). Thus, this segment of market, in any case, was not available to the domestic industry even after imposition of anti-dumping duty. The Govt. of India has exempted such imports from payment of ADD. Had ADD been applied on such imports, the domestic industry would have catered to this market and the consumers would not have imported the product.
- q) No Statutory or organizational restriction by the shareholders in relation to operations of the related companies: if the two related companies are acting autonomously when defining and pursuing their business plans and if the relationship did not influence the behavior, nor distort the analysis of the economic situation of the domestic producer in question as regards the product concerned, then the producer may not be excluded under Rule 2(b).
- r) Related producers operating are in competition and have conflicting interest: if the two companies concerned, although related, have conflicting interests regarding the imposition of anti-dumping measures, then such related domestic producers should be included within the ambit of domestic industry.
- s) Is the behavior of the related parties distinct and different as compared to unrelated parties: The investigating authorities consider the behavior of the related parties and ascertain whether the same shows distinct and different behavior as compared to unrelated parties? Followings are relevant in this regard:
- Status of the company among the different manufacturers of the product in the domestic country;
 - Whether focus of the company is on domestic production;

- c. Effect of non imposition of Anti-dumping duty on the company concerned;
 - d. Trend of injury information of the concerned producer with the other domestic producers.
- t) Whether exports of the product in question by the related producers allow the domestic producer to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping. If a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to exports by the related party, the company must be excluded or if a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, it may be excluded.
- u) Effect on injury analysis – Where exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry, it must be included or if inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
- v) Exports Made by the Related Parties: Apart from being a related party, it is also pertinent to evaluate the impact of the exports, if any, made by the related party in a given case. Whether such related party had exported the product to India during the period, if so, what is the impact thereof on the claims of injury? If not, whether there is any other ground still justifying its exclusion. In case the related party has also exported the subject goods, then the following also need to be evaluated:
- i. The volume of exports made by such related party;
 - ii. The purpose of such exports made by the related party;
 - iii. Whether there is any evidence to show that injury to the domestic industry was attributable to such exports by the related party;
 - iv. Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
 - v. Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the proceedings.
- w) In the instant case, Hi-tech Carbon and TCB can be loosely said to be related party, but for the purposes of Anti dumping Rules they are not related parties because (a) none of them directly or indirectly control the other; (b) none of them are directly or indirectly controlled by any third person; and (c) they does not directly or indirectly controlled by any third person. Assuming though not admitting that the two companies are related, the domestic industry submits that the rules provide for discretion, as

elaborated above and the discretion should be in favour of inclusion of the company as a domestic industry for the reasons given below:

- i. Hi-tech Carbon has not imported the subject goods from any related exporter from subject countries.
- ii. Hi-Tech Carbon is one of the business verticals of the Aditya Birla Nuvo Limited (ABNL) and is engaged in carbon black business.
- iii. Aditya Birla Nuvo Limited and Thai Carbon (TCB) are two separate listed corporate entities and neither holds any share in the other. They are controlled by their respective shareholders and the board of directors.
- iv. There are two directors who are common on board of both the companies, namely Mr. Kumar Managalam Birla and Mrs. Rajashree Birla. However, both are non-executive directors and have joined the board in their individual capacity. It is also pertinent to note that the board of directors of ABNL and TCB constitutes of 11 and 12 directors respectively and none of these two directors have any casting vote or any veto right.
- v. Both the companies act autonomously while taking business decisions in pursuing their own business plans.
- vi. Both the companies are working in competition with each other in the Indian market as one is the domestic producer of the subject goods and the other is the exporter.
- vii. There is no statutory or organizational restriction by the shareholders in relation to operations of the two companies.
- viii. Both the companies have conflicting interest regarding the imposition of Anti-dumping duty. Imposition of Anti-dumping duty would help the domestic company i.e. ABNL to recover from the injurious effect of dumping caused by the exporters from subject countries, whereas the goods exported by TCB will be subject to Anti-dumping duty.
- ix. The behaviour of the Hi-tech Carbon is not distinct and different as compared to Phillips Carbon Black Limited who is the unrelated domestic producers in India. Both the domestic producers are injured from the effect of dumping practices by the exporter of subject countries including Thailand. The trends of various economic factors of both domestic producers are similar therefore it cannot be said that Hi-Tech Carbon is benefitting out of dumping by TCB.

834 51/13 -26

- x. With manufacturing plants at Renukoot in Uttar Pradesh, Patalganga in Maharashtra and Gummidipoondi in Tamilnadu, Hi-Tech Carbon is the second largest producer of carbon black in India, covering approximately ***percent of the domestic market share. The focus of the company is on domestic production.
- xi. Revocation of anti-dumping duty would severely affect the performance of Hi-tech Carbon. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, lower import prices prevented the company from increasing their prices. Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash profits. Thus, deterioration in profits, return on capital employed and cash flow is directly due to dumped imports.

Examination by the Authority

10. The Authority notes that at the time of the initiation of the subject investigation, Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules read as follows:-

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producer only".

11. However, post initiation, the Rule 2(b) has been amended vide Notification No. 86/2011-Cutoms (N.T.) dated 1st December 2011 and presently reads as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

12. Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations. The Authority is of the considered view that the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. On the contrary, it has been the consistent practice of the investigating authorities that the exclusion of such

producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.

13. As regards the contention of the applicant and other interested parties that the Authority has no discretionary power to consider or not to consider a domestic producer as domestic industry under Rule 2(b) of the Rules in view of their relationship with the exporters of the subject goods from subject countries and imports of subject goods from subject countries by themselves or through related companies, the Authority notes that similar issue had been raised by some interested parties in the anti-dumping investigation concerning imports of soda ash from China PR, Pakistan, Kenya, etc before the Hon'ble Madras High Court. The Hon'ble division bench of Madras High Court in Writ Appeal Nos. 193 / 2012, 194 / 2012, 189 / 2012 and 195 / 2012 in their judgment dated 27.04.2012 held inter alia held as follows:

“ 62.....(ii) the term ‘domestic industry’, as it was amended on 27.02.2010, has not taken away the discretionary power of the Designated Authority.....”

14. Further, the Hon'ble Division Bench of Madras High Court vide their order dated 18.06.2012, while disposing of the M. P. 1 of 2012 in W.A. No. 195 of 2012, reiterated their earlier judgment that the Designated Authority is endowed with the discretionary power in this regard. In view of the above, the Authority notes that there should not be any further dispute as regards discretionary power of the Authority under the Rules.

15. The Authority has taken cognizance of the jurisprudence available on the subject and relied upon by it in some of its earlier findings in respect of investigations concerning imports of Soda Ash, Viscose Staple Fibre, etc. These jurisprudence suggests the following as the circumstances in which a related domestic producer may be included or excluded:-

- (a) One of the important factors in this regard is the balance of business of the domestic producer between manufacturing and importing. If the company predominantly manufactures the product in India, it should be included. However, if the domestic producer closes or reduces its production and instead imports the product or the general emphasis of its business shifts from production to imports, it should be excluded.
- (b) If a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to imports or exports to a related party, the company must be excluded.

- (c) If a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, it must be excluded.
 - (d) If inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
 - (e) If a domestic producer does not co-operate with the Authority, the Authority tends to consider such domestic producer as ineligible.
16. The Authority also notes that the text book written by M/s. Czako, Human and Miranda; *inter alia*, mentions the criteria applied by the other WTO members in such situations as follows:-
- (a) The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers.
 - (b) Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping.
 - (c) Whether exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry.
 - (d) The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production, as opposed to importing activities.
 - (e) The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.
17. The Authority considers that the purpose of the discretion to include or exclude certain domestic producers is to enable the Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped import on the domestic industry in India by excluding those domestic producers from the relevant domestic industry which have participated in injurious dumping. The Investigating authorities may exclude a related producer, where the related parties either:
- (a) provoked or contributed to a fall in prices on the market,
 - (b) are shielded from their effects, or
 - (c) where they benefited unduly from them.
18. With regard to the first category, i.e. the participation in dumping practices, the Authority considers that several typical situations may be distinguished. On the one hand, the exclusion is indeed appropriate where the injury of a domestic producer is

self-inflicted because imports from dumped producers reduced the use of domestic producers' own capacity, or resulted in the abdication of domestic producers' projects designed to increase their own production. The Authority is of the view that exclusion of a domestic producer is *prima facie* not appropriate, if its participation in the dumping was an act of self-defence. Such a domestic producer should, therefore, be taken into account when defining the relevant domestic industry.

19. The Authority further considers that the domestic producers who import the dumped products or whose related party exports the dumped products or whose related party imports the dumped products do not unduly benefit from dumping practices, if these exports/imports do not represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage would occur to such domestic producers in such an event because of the competition from other suppliers in the market. Another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? If the focus has shifted from domestic production to imports, then such a domestic producer should be excluded from the scope of domestic industry. Thus an important element that needs to be considered on the subject is: whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.
20. The Authority notes that the relevant provisions and legal position as on date, defining the domestic industry, grants discretion to the Authority to either include or exclude a related domestic producer from its consideration as a part of the domestic industry. The Authority further notes that in case the applicant is related to a producer in the exporting country, the mere fact of such relationship does not lead to automatic exclusion of such producer from the ambit and scope of the domestic industry. Indeed, discretion granted has to be judiciously exercised by the Authority in such cases, to examine further on case by case basis and consider whether such a related producer should be considered as eligible or ineligible to be considered as a part of the domestic industry. Axiomatically, the impact of relationship on the facts of the case needs to be appreciated for this purpose. Considering the facts available on record, the Authority has, *inter alia*, considered the following:-

- (a) Whether the behaviour of the related parties is distinct and different as compared to unrelated parties;
- (b) Whether there is some evidence to show that such related producer triggered or intensified dumping in the Indian market;
- (c) Whether the related domestic producer has been shielded from the effects of dumping or has unduly benefited from it;
- (d) Whether the related domestic producer has sought to stifle the competition in the Indian market;

(e) Whether there is a case of self-inflicted injury?

21. The Authority considers that apart from being a related party, it is also pertinent to evaluate the impact of the exports/imports, if any, made by the related party in a given case. Whether such related party had exported/imported the product to India during the period, if so, what is the impact thereof on the claims of injury? If not, whether there is any other ground still justifying its exclusion. In case the related party has also exported/imported the subject goods, then the following also need to be evaluated:
- The volume of exports/imports made by such related party;
 - The purpose of such exports/imports made by the related party;
 - Whether there is any evidence to show that injury to the domestic industry was attributable to such exports/imports by the related party;
 - Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
 - Whether the volume of exports/imports by such related parties were such that the related exporter is gradually or steadily substituting the unrelated domestic producers' market;
 - Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the investigation.
22. The imports were not made by Hi-Tech during POI. The imports were rather made directly by unrelated importers. The domestic industry claimed that during POI the exports made by M/s Thai Carbon Black (TCB) to Indian importers were mostly under duty free advance licenses. They claimed that out of total *** MT exports of Carbon Black made by TCB to India during the period of investigation, only *** MT (***% of total exports) were exported under duty paid mode and the rest *** MT were exported against duty free advance licenses. In this context the Authority requested the applicant to provide information regarding imports made by their member importers under advance license during the POI. The applicant informed that out of their 10 members, five of their members namely M/s CEAT Ltd, Apollo Tyres Ltd, J K Tyres & Industries Ltd, Bridgestone India Pvt Ltd and MRF Ltd together have imported during POI total *** MT of the subject goods from M/s TCB, out of which *** MT was under duty free advance licenses. On the basis of the above information, the Authority notes that only *** MT (***% of the total imports) of the subject goods were imported by the members of the applicant association on payment of duty and the balance *** MT was imported under duty free advance licenses, during the POI, from M/s TCB Thailand. This reinforces the claim made by the domestic industry that the concerned exporter has exported mostly under advance licenses to India during POI.

23. Although M/s HiTechCarbon and M/s ThaiCarbonBlack Public Company (TCB) are related, both the companies are independent companies under the legal framework of the respective countries, one operating under the Company Law of India and the other operating under the Company Law of Thailand. The Thai Carbon is a producer and exporter of the subject goods from Thailand, one of the subject countries, during POI, but did not file response. The subject exporter being non-cooperative will be subjected to residual duty in case the anti-dumping duty is continued to be imposed. In such a situation it does not seem to be benefiting M/s Hi-Tec in any manner. Imposition of Anti-dumping duty against Thailand itself proves the intent of the domestic industry. If the Hi-tech carbon was benefitted by the related party exports, it would not have filed the petition against Thailand at the very first instance. It is pertinent to note that the exports made by the related party are also subject to anti-dumping duty and therefore there is no evidence to prove that Hi-tech carbon is unduly benefitted. Focus of Hi-Tech continues to be on production. The company have not turned trader. The Authority further notes that there is no evidence whatsoever provided by opposing interested parties establishing that the two parties have colluded.
24. The domestic industry in the original as well present review investigation is constituted by two leading unrelated domestic producers of Carbon Black in the country namely M/s Philips Carbon and M/s Hi-Tech Carbon. Had the exports of subject goods made by the related exporter of Hi-Tech Carbon i.e. TCB would have injured the domestic industry, M/s Philips Carbon would have been injured equally. In that event, being an unrelated party, by no stretch of imagination M/s Philips Carbon, would have joined hands with Hi-Tech., in the anti-dumping investigation. Moreover, the behaviour of the Hi-tech Carbon is not distinct and different as compared to Phillips Carbon Black Limited who is the unrelated domestic producer in India. Both the domestic producers are injured from the effect of dumping practices by the exporter of subject countries including Thailand. The trends of various economic factors of both domestic producers are more or less similar, therefore it cannot be said that Hi-Tech Carbon is benefitting out of dumping by TCB.
25. Moreover during the original investigation, the issue regarding non-eligibility of M/s Hi-Tech Carbon as domestic industry due to their relationship with M/s ThaiCarbonBlackPublic Company Ltd (TCB) had come up. The Authority in its Final Findings notification No.14/21/2008-DGAD dated 24th December 2009 had observed as follows:

"20. The Authority notes that M/s Hi Tech Carbon is related to M/s Thai Carbon Black Public Company and M/s Liaoning Birla Co. Ltd. M/s Hi Tech Carbon has claimed that M/s Liaoning Birla Co. has not exported carbon

black in Indian market. Even though M/s Thai Carbon Black Public Company Ltd. has exported the subject goods to India, the entire volume of exports is only 2178 MT, out of total of 515350 MT in POI. Some interested parties have reiterated their argument regarding inclusion of M/s Hi Tech in view of exports by their related entity. The Authority, however, notes that the exports made by the Thai related company are not so significant and not under such condition to take a view that M/s Hi Tech should be considered ineligible to be considered as a part of the domestic industry. The Authority notes that the Hi Tech Carbon has not turned to importing and trading. The focus of the company remains substantially on production. Further, there is no evidence on record to show that M/s Phillips Carbon Black Ltd. and M/s Ceat Ltd. are related companies. Even though ATMA has participated in the present investigations as an interested party and M/s Ceat Ltd. is their member, there is no evidence on record to show that M/s Ceat Ltd. has imported significant volumes of the product under consideration from the subject countries after payment of customs duties.

21. *The Authority notes that the volume of exports made by M/s Thai Carbon Black is too insignificant in relation to production and consumption in India. Besides, it has not been established that M/s Hi Tech Carbon should be excluded from the purview of domestic industry because of exports made by the related company. The Authority considers it appropriate to include M/s Hi Tech Carbon within the scope of the domestic industry. With regard to eligibility of M/s Phillips Carbon, the Authority notes that the interested parties have not provided sufficient evidence to justify its exclusion.*

22. *As per the evidence available on record, production of M/s Phillips Carbon Black Ltd. and Hi-Tech Carbon account for a major proportion of the domestic production of like article, being significantly more than 50% of Indian production. Further, the petition is supported by M/s Continental Carbon. The application thus satisfied the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Further, M/s Phillips Carbon Black Ltd. and M/s Hi-Tech Carbon are being treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) read along with Rule 2(d) of the AD Rules for the present purpose."*

26. It is relevant to note that applicant in the present review investigation, who were also interested party in the original investigation and had taken similar ground for exclusion of Hi-Tech from the purview of domestic industry due to their relationship with Thai Carbon, have not impugned the decision of the Authority in considering Hi-Tech as domestic industry under the Rules. Moreover the Authority notes that the applicant for present MTR did not show any prejudice with regard to the standing and scope of M/s Hi-tech as constituting domestic industry in the event of

relationship with TCB. Rather the ground on which the present MTR was sought by the applicant was that:

- the import prices of Carbon Black have increased significantly;
- domestic selling prices have also increased significantly;
- the cost of raw material – Carbon Black Feed Stock (CBFS) has come down significantly and that with the fall in cost of major raw materials, the Non-injurious price (NIP) for the domestic industry has come down drastically;
- coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.”

27. As regards the contention of ATMA that Phillips Carbon Black Ltd (PCBL) and Ceat Ltd are related in the context of having a common director, the Authority notes that CEAT Ltd has opposed the domestic industry in the present investigation by filing importer questionnaire response. Moreover the concerned importer had also opposed the domestic industry in the original investigation. This signifies that relationship has no determining effect on the decision making process of both the companies. Had the relationship been of any significance in the decision making process of these companies, then the concerned domestic industry would not have sought imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries and the concerned importer would not have opposed the move of the domestic industry.
28. After careful examination of the submissions made by the interested parties on the subject and considering the legal provisions and facts of the case and Authority's consistent position in such circumstances, the Authority notes that the facts on record do not justify exclusion of M/s Hi-tech and PCBL from being considered as domestic industry under the Rules. M/s Philips Carbon and M/s Hi-Tech Carbon account for a major proportion of the domestic production of the subject goods in India and therefore constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.
29. As regards the contention of the petitioner that imports made under duty exemption scheme should be excluded while conducting injury analysis, it is noted that it is a consistent practice with Authority not to exclude such imports while conducting injury analysis. The Authority in the past has examined similar issues pertaining to the anti-dumping investigations involving imports of Aceton, originating in or exported from European Union, Chinese Taipei, Singapore, South Africa & USA and held as under:

“56. It has been stated that imports made under duty exemption scheme should be excluded for the purpose of injury analysis. The Authority notes that the imports made under duty exemption scheme create competition and change

834 9/13-28

the price line as the importers would procure the goods from exporters or producers whosoever gives him the competitive price, therefore, the imports made under duty exemption scheme cannot be considered to have not affected the price in the market. The Authority, therefore, has not found it reasonable to exclude all duty free imports for the purpose of injury analysis."

30. Therefore, the imports made under duty exemption scheme cannot be considered to have not affected the price in the domestic market. An Advance license/authorisation holder has a choice either to import the inputs on a duty free basis or procure the same from indigenous sources by using the mechanism of Advance Release Order. The purpose of injury analysis is to examine and capture the effect of dumped imports on the domestic industry. Therefore, it would not be reasonable to exclude all duty free imports for the purpose of injury analysis.
31. As regards the submission of petitioner and other interested parties that as per Rule 25 of the Anti-dumping Rules, Hi tech Carbon and M/s. Phillips Carbon Black Limited cannot be treated as domestic producers of the subject goods as they are only making a value addition of just 15% to the raw material that is predominantly imported into India from third country. In this context the provisions of Rule 25 of AD Rules is extracted below:

"25. Circumvention of anti dumping duty. - (1) Where an article subject to anti dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in such country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if,-

- (a) *the operation started or increased after, or just prior to, the anti dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty; and*
- (b) *the value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty-five percent of the cost of assembled, finished or complete article.*

Explanation I. — 'Value' means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components

Explanation II. - For the purposes of calculating the 'value', expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know- how fees and consultancy charges, shall not be taken

into account.

(2) *Where an article subject to anti dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti-dumping duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to anti dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any.*

(3) *Where an article subject to anti dumping duty is imported into India through exporters or producers or country not subject to anti dumping duty, such exports shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti-dumping duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through exporters or producers or country not subject to anti dumping duty.*

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it shall be established that there has been a change in trade practice, pattern of trade or channels of sales if the following conditions are satisfied, namely:-

- (a) *absence of a justification, economic or otherwise, other than imposition of anti- dumping duty;*
- (b) *evidence that the remedial effects of the anti-dumping duties are undermined in terms of the price and or the quality of like products.*

32. The Authority notes that provisions of Rule 25 of Anti-dumping Rules have been formulated to address a completely different situation caused by circumvention by the exporters/producers who are subjected to anti-dumping duty. Criteria given in the said Rule is not applicable in the matter concerning standing and scope of domestic industry in an anti-dumping investigation.

F. Confidentiality

33. The applicant and other interested parties have submitted that the information can either be kept confidential or non-confidential; there is no regulation which provides for the treatment of information as confidential for few interested parties alone and be regarded as non- confidential for all others. On the contrary the domestic industry has alleged that applicant has claimed information pertaining to domestic industry confidential from the domestic industry itself.

Examination by the Authority

34. The Authority notes that none of the interested parties have raised any major issue concerning confidentiality. However it is noted that the Authority has granted confidentiality wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

G. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**Submissions made by the Petitioner (ATMA), Exporters, Importers and Other Interested Parties**

35. Following miscellaneous submissions have been made by Petitioner (ATMA), Exporters, Importers and Other Interested Parties:

- a. The scope of mid-term review is different from the scope of sunset review. In a mid-term review DGAD is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty before completion of five years, whereas in sunset review DGAD is required to determine whether anti-dumping duty is required to be extended further or not after expiry of five years.
- b. Petitioner has sought review of existing measures providing 'positive information substantiates the need for review'. Therefore, the argument by the domestic industry that the onus of proving that revocation of duty would not cause injury to the domestic industry does not hold any water.
- c. POI should not be extended as argued by the domestic industry, If the contention of the domestic industry that 'the performance during POR is irrelevant' is accepted and the performance as of today is to be examined, the concept of examining the performance over a period would lose its legal sanctity and there would be no end to an AD Investigation as the new data would keep flowing in with passage of time.
- d. Post initiation data should not be considered, the producers will stage manage their business in such a way so as to show losses in the period post initiation and claim injury as a sign of recurrence.
- e. Safeguard investigation is China specific and not relevant for other subject countries.
- f. DGAD is not an appellate authority to consider the findings of a safeguard finding. DGAD is required to examine the performance during the defined Period of Investigation (POI) with the defined injury period prior to the POI, unlike safeguard investigation, which does not have a specified investigation period.
- g. There exists large variation in the data presented in the submissions made by domestic industry in the present investigation and findings recorded by DG Safeguards.

- h. Although DG Safeguards recommended imposition of safeguard duty for a period of three years, Ministry of Finance considered that imposition of safeguard duties for a period of 15 months is sufficient for domestic industry to overcome the effects of injurious effects of imports from China PR. Thus, even according to Central Government, injury due to imports from China PR beyond 31st December 2013 is unlikely.
- i. The amended rule requires interested party to provide positive information substantiating a need for review. There is no need to provide information substantiating need for withdrawal of anti-dumping duties as argued by domestic industry.
- j. The contention of the domestic industry that its performance during the POR is totally insufficient for examining the need for withdrawal of anti-dumping duty is without any legal basis. The purpose of specifying a particular period as the POR is to examine the performance of the domestic industry during that period and thereafter review the need for withdrawal of the Duty.
- k. The POR fixed for the present case is April 2010 to March 2011. The investigation was initiated on 30 August 2011, that is, 5 months after the end of POR. Therefore the POR fixed by the Authority cannot be termed as historic as argued by the domestic industry.
- l. The findings of DG Safeguards shall not be considered by DGAD while arriving at the final determinations, since the information contained therein is totally different from information provided by domestic industry in the present MTR investigation.
- m. The information regarding the procurement prices of a few members cannot be disclosed since it would adversely affect the purchasing power of the members who had provided the information.
- n. The contention of the domestic industry that imports should have stopped after the imposition of AD Duty is highly incorrect. The object of AD Duty is only to cure the injurious effect of dumping and not to stop imports.
- o. The MTR investigation should be restricted to the POR of the present investigation and not consider post POR data as it would result in consideration of new data every now and then and thereby result in delay in completion of investigation.

Submissions made By Domestic Industry

36. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. The scope of Mid Term Review Investigation is substantially different from scope of original or sunset review investigation in the sense that while in a Mid Term Review, the Designated Authority is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty at premature stage, in a Sunset Review, the Designated Authority is required to consider and determine whether anti-dumping duty is required to be extended further. However, in both the

8344/13-29

type of review, likelihood analysis in respect of dumping and injury is an essential consideration.

- .b. The period of investigation fixed by the Authority is historical and the performance of the domestic industry has undergone a significant change thereafter. Therefore any determination without consideration of the present period will be against the intention of the Rule 23 (1A).
- c. Designated Authority has to examine whether changed circumstances could be said to be of lasting nature. Mere change in circumstance is insufficient. The performance of the domestic industry and the levels of imports from subject countries in the current period is the most reliable evidence in order to determine the lasting nature of the changed circumstances.
- d. There is no basis for the argument that the safeguard findings should not be considered merely because there are some differences in the figures. The basis adopted by the Director General Safeguards for assessment of production, domestic & export sales volumes, inventories volume is different from the basis adopted by the Designated Authority. While Designated Authority adopts financial records and financial statement forming part of annual accounts; the Director General Safeguards adopts excise records. This has been clearly stated by Director General (Safeguards) in its final finding. The relevant extracts are as follows:
 - a. *Production: - The production has been determined on the basis of production reported by the domestic industry in its excise records*
 - b. *Sales: The sale has been determined on the basis of goods cleared by the domestic industry, as reported in their excise records.*
 - c. *Inventory: The level of inventories was considered as per excise records maintained by the domestic industry.*
- e. Thus, minor variation between the two data is inevitable. As stated in the written submissions, even more important parameter such as profit/loss as per Income Tax Act and profit/loss in the Annual Report may not be the same, as Annual Report is prepared as per directions under Companies Act. These differences are, however, not relevant to the Designated Authority. The domestic Industry has not requested Designated Authority to consider the figures adopted by the Director General Safeguards. The domestic industry has requested the Designated Authority to consider the conclusions drawn by the Director General Safeguards. It is not established that the decision in two bases have led to two different conclusions. In fact, information presented by domestic industry on both the basis leads to the very same conclusions i.e.
 - i. Performance of the domestic industry improved on account of parameters such as production, domestic sales, capacity utilization, market share till 2010-11 and deteriorated thereafter.

- ii. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash profits improved till 2010-11 and deteriorated thereafter.

- f. These conclusions are clearly established from both set of information, i.e. the information relied upon by the Director General Safeguards and the information provided to the Designated Authority based on financial records.

- g. The difference in imports is due to the fact that whereas the Designated Authority considers product description and includes imports of the product under consideration regardless of the classification where it has been imported, the Director General has considered imports falling under HS code 28030010 only. Domestic industry refers to the final findings notified by the DG (Safeguards), which is relevant to the present issue. The relevant extracts finding of DG (Safeguards), are as follows –

30. The product under investigation is imported into India under chapter heading 28030010 of the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of DGCI&S import data from 2008-09 to 2010-11 and data provided by the domestic industry from secondary data compiling agency (IBIS) for rest of the period. In the Preliminary Findings, the import data for the entire period has been considered on the basis of data provided by the domestic industry from secondary data compiling agency (IBIS). The information provided by the petitioners and other interested parties were examined and it was found that it included some imports of the products which are beyond the scope of the product under consideration. Therefore, even though the petitioners had reported imports as per IBIS which included imports under HS code 28030020 and 28030090 also; after scrutiny the imports falling under HS code 28030010 only has been considered. The analysis for increasing imports was carried out for the relevant period by considering imports of Carbon Black under chapter heading 28030010 of the Customs Tariff Act, 1975 for 'rubber applications' only.

- h. Without prejudice, domestic industry submits that the difference in the two data is insignificant. Both data leads to eventually same conclusion. Under the Rules, ultimately, DA is concerned with the trends in the economic indices. Whether the data contained in the safeguard findings or data now presented by the domestic industry before the DA is considered, eventual conclusion drawn shall remain the same. For example, the DA is concerned with whether the production increased or declined materially. Whether the production is considered as per excise records or as per financial records, the same conclusion shall be reached. Thus, there is no material impact of considering two different basis for assessment of economic parameters.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

- 37. Rule 23 of Anti-dumping Rules states as follows:

(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

(1B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or (1A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.

(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9/10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.

38. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authority shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

39. The applicant and the other interested parties have contended that the scope of mid-term review is different from the scope of sunset review. The applicant has contended that in a mid-term review DGAD is required to consider and determine whether there is sufficient justification for withdrawal of anti-dumping duty before completion of five years, whereas in sunset review DGAD is required to determine whether anti-dumping duty is required to be extended further or not after expiry of five year. On

the other hand, domestic industry contended that in a mid-term review, current performance alone is insufficient to conclude whether the anti-dumping duty can be withdrawn at this stage and that the Authority is required to consider the likely situation when anti dumping duty is withdrawn.

40. The Authority has examined the issues raised by the interested parties and domestic industry and notes that Rule 23 of the Anti-dumping Rules obligates the Authority to review the need for the continued imposition of an anti-dumping duty, *inter alia*, upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review after a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to the conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.
41. As regards analysis of post POI data, the Authority notes that post POI developments are required to be addressed through the review mechanism as envisaged under the Anti-dumping Rules and the Customs Tariff Act, which is necessary to determine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry and necessity for withdrawal or continued imposition of anti-dumping measures. The Authority has examined and evaluated the information/data not only with reference to the period of investigation but has also analysed the post POI information/data for assessing likelihood of recurrence of dumping and injury to arrive at the conclusions. Therefore for the purpose of the present investigation, the Authority has considered the injury period till March 2011. However, the period of April-September, 2011 has also been considered for assessing likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
42. As regards difference in data between safeguard and anti dumping, it is claimed by the domestic industry that the basis adopted by the Director General Safeguards for assessment of production, domestic & export sales volumes, inventories volume is different from the basis adopted by the Designated Authority. While Designated Authority adopts financial records and financial statement forming part of annual accounts; the Director General Safeguards adopts excise records. In this regard the Authority notes that the present findings are based on verified data as furnished by the cooperating interested parties.

H. Determination of Dumping Margin

Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the domestic industry during the course of investigation

43. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

834 46/13-20

- i. China should be treated as non-market economy countries for following reasons:
 - Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
 - Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values
 - Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards.
 - Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.
 - It is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
 - Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
 - In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- ii. Normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 Annexure-I to the Rules.

Submissions made by the Petitioner (ATMA), Exporters, Importers and Other Interested Parties

- The domestic industry has claimed that there is huge excess capacity with Chinese producers which threatens dumping into India. It is submitted that China PR has been holding excess capacity for quite a long time, however mere availability of excess capacity is not sufficient in itself to conclude that there will be recurrence of dumping into India.
- The main reason for difference in prices of Chinese product and domestic product is due to difference in raw material used by Domestic industry and its Chinese counterpart. Merely because Chinese producers are able to produce the subject goods at cheaper price does not imply they are dumping the goods. Any injury arising out of different raw materials used cannot be attributed to dumping.

Examination of Market Economy Claims

China PR

44. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of

China to advise producers/exporters in their country to provide the required information.

45. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporter/producer of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labor, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

46. In the present investigation, the following producers/exporters of subject goods from China PR, except M/s Jiangxi Black Cat Carbon Inc. Ltd., Jingdezhen, China PR (producer/exporter), claimed market economy treatment by filing MET questionnaire response;

1. M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd. China PR.
2. M/s. Shanghai Hyun Tong Industry International Co. Ltd. China PR.
3. M/s. Suzhou Baohua Carbon Black Co. Ltd. China PR.

47. The Authority notes that M/s Shanghai Hyun Tong Industry International Co. Ltd. China PR and M/s. Suzhou Baohua Carbon Black Co. Ltd. China PR did not cooperate by offering themselves for verification of their data/information, and therefore, are considered as non-cooperative in the present investigation.

48. The data/information furnished by M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd. China PR who claimed market economy treatment and M/s Jiangxi Black Cat

Carbon Inc. Ltd., Jingdezhen, China PR (producer/exporter) who did not claim market economy treatment, were verified by the Authority.

M/s Jinneng Science & Technology Co., China PR

49. M/s Jinneng Science & Technology Co., Ltd filed MET Questionnaire and claimed market economy treatment in the present investigation. The data/information furnished by M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd was verified by the Authority. Following observations weremade by the Authority during the course of on the spot verification:

- i. During the on the spot verification, it was informed that the subject company and its controlling parent companies as well as the related companies are entirely family held business. It was further informed that prior to establishment of the subject company, the family owning the subject company was involved in kitchen implement business. However the subject company could not substantiate with documentary evidence how the family could manage so much of fund from the kitchen implement business to make such a huge investment within a period of ten years or so.
- ii. On being questioned about the relationship between M/s Shandong Reipu and M/s Shandong Chenming Chemical Co Ltd, it was informed that Mr. Qin Ping, the Chairman of the subject company had set up M/s Shandong Chenming Chemical Co Ltd in 1998 with ***% share for producing food additives. It was further informed that this company was closed in 2002 and the land and the assets of the company were sold off. But the company could not substantiate the transaction with documentary evidence. However, when being informed about the web based information that the old name of M/s Shandong Reipu is M/s Shandong Chenming Chemical Co Ltd, the subject company stated that the business of M/s Chenming Chemicals Ltd was taken over by M/s Reipu, the controlling parent company of the subject company. But the subject company could not substantiate with documents to prove that the transaction was as per market process.
- iii. It was informed by the company that the entire group including the subject company is family held and all the investments and monetary transactions are made in cash. When questioned about the source of fund of the investors, no satisfactory answer supported by documents could be provided. The company could not provide any document to prove that the sales and purchases of the assets of the subject company and the related companies were done as per the open market price. The company also could not produce the details of the purchase of the raw materials at the prevailing market prices.
- iv. Further, one of the web based information states that the subject company was listed as the State Ministry of Coal Chemical key schedule contact companies. On being questioned about the relevance of such statement, the company could not provide any satisfactory answer substantiating with documents.

- v. In the balance sheet, the company claims to have assets worth of *** Million RMB in the very first year of establishment of the company and the company claimed depreciation for the same. But the company could not provide the assets register along with relevant documents supporting the procurement of such assets by the company. The company could not also produce the detailed land related documents and documents in support of procurement of land and buildings at market prices.
- vi. The company did not provide the audited annual accounts for the year 2011 stating that the same is not ready. But, it was observed that while the audited annual accounts of the company are generally ready by the month of February of the year, no satisfactory reason could be provided by the company for not keeping the annual accounts for the year 2011 ready even by the end of month of June when company is verified. The company was asked to provide an undertaking to this effect, but they did not do so.
- vii. The company informed that the Board of Supervisors of the company is manned by three members. While two members were claimed to be employees of the company, the chairman of the BOS was stated to be the Chairman of the Labour Union as well. But the company could not provide details about the engagement of the members of the BOS nor the documents in support of their employment and payment of monthly salary to them.
50. The verification report was sent to the subject company for comments through their representatives. In their response to the verification report M/s Jinneng did not rebut the observations of the Authority as regards their non-market status, thereby acknowledging their non-market economy status. In view of the above position, the Authority does not grant market economy treatment to M/s Jinneng Science & Technology Co., Ltd, China PR.
51. In view of the fact that none of the responding producers/exporters have been accorded MET status and none of the interested parties, including the domestic industry, have made available any material fact to the Authority to select an appropriate market economy third country, the Authority has determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
52. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provides that:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a

834 46/13-31

reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

53. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all exporters from China PR has been constructed based on facts available and the Authority has determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Methodology adopted for constructing Normal Value in case of China PR

54. The Authority has constructed the Normal value for the Chinese producers on the following basis –

- a. International prices of major input, carbon black feed stock has been considered on the basis of the price published by Platts magazine for Heavy Stock GC3%.
- b. Consumption of raw materials and Conversion costs have been adopted on the basis of information/data of efficient producer of the domestic industry.
- d. Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of information/data of efficient producer of the domestic industry.
- e. Profit has been taken @ 5% of ex-factory cost excluding interest.

55. For the purposes of conducting a fair comparison, separate Normal value has been calculated for each grade of subject goods produced and sold and separate Normal value has been calculated for each quarter of the period of investigation. However, the dumping margins so arrived have been weighted averaged for the entire ‘period of investigation’ and for the ‘product under consideration’ as a whole thereafter.

56. Accordingly Constructed normal value is determined by the Authority in respect of China PR as US \$ ***per MT.

Normal value in case of Russia, Australia and Thailand

57. While no questionnaire response has been filed by any producer/exporter from Australia and Thailand, the questionnaire response has been filed by M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod, Russia.

**M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod(producer) and M/s Trigon Gulf, FZCO
Dubai, UAE**

58. The data/information furnished by M/s Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod was verified by the Authority. During the POI, while the company exported the subject goods to other countries directly, they exported to India only through their distributor M/s Trigon Gulf, a trading company at Dubai, in the UAE. It was stated that M/s Trigon Gulf purchased the subject goods ex-factory from M/s Yaroslavskiy and then exported to India by preparing all the required documents and bearing all required expenses. The goods are shipped directly from the factory to Indian consumers. The payment is however made by Trigon. The entire transaction was stated to be governed by a contract signed between Yaroslavskiy and Trigon Gulf.
59. During the verification it was found that all the randomly selected invoices in respect of the subject goods claimed to have been exported to India during the POI and post-POI showed the consignee's name as ***, Colombo, Sri Lanka. On being questioned, it was informed by the company that all the other export consignments were also consigned to the same company in Colombo and they have been following this practice of showing the Colombo party as the consignee in respect of all their exports to India via Trigon Gulf, Dubai. But, the company could not provide any satisfactory reason/justification, with documentary support, for showing the name of ***, Colombo, Sri Lanka as the consignee in their invoices etc when the subject goods are actually meant for export to India and that was very much within their knowledge. From the copy of the addendum to the contract it is evident that it was very much within the knowledge of Yaroslavskiy that the subject goods shipped by them are actually meant for the Indian buyers and it was very much within the knowledge of Trigon Gulf that Yaroslavskiy is showing ***, Colombo as the consignee in respect of the goods purchased by them for export to Indian buyers. Despite this knowledge, Yaroslavskiy continued to show the name of ***, Colombo in their export documents and Trigon did not object to the same practice and continued to show the same consignments in the name of Indian buyers in their export documents.
60. Further, M/s Trigon Gulf also exported the subject goods produced by other Russian and Chinese producers to India during the POI. But in respect of such transactions no response has been filed by the concerned producers from Russia and China PR. Therefore, a portion of Trigon's export of the subject goods to India during the POI of the present investigation has gone un-responded by the concerned producers.
61. During the verification M/s Trigon was also requested to clarify why the name of the party has been shown in the documents prepared by Yaroslavskiy as ***, Colombo, when the goods were actually meant for sale to Indian customers as per the contract signed by them. No satisfactory reasons/justification with documentary support for following such practice was provided to the investigation team by Trigon as well.
62. M/s Yaroslavskiy Technicheskiy Uglerod, Russia was requested much in advance to keep the required documents/records ready duly translated into English language for

verification purpose. In spite of clear and prior instructions, most of the required documents/records were not translated in to English language and kept ready for verification. As a result, the team was handicapped in verifying the data/information furnished by the company.

63. The verification report was sent by the Authority for comments by concerned producer and exporter. But, as regard issue of showing consignee name as ***, Colombo in the invoices of the producer in respect of shipment meant for Indian buyers, no satisfactory reasons/justification for following such practice could be provided by either the producer or the exporter concerned with documentary support.
64. The above observations, along with a few others, were noted in the verification report and were sent to the concerned parties for comments. In response, M/s Open Joint Stock Company "Yaroslavsky Technichesky Uglerod" Russia (producer) has submitted inter alia as follows:

*"Trigon gulf is authorized to sell CB in any other country/market with prior approval of Yaroslav and can divert the goods to any other location along with India. The Consignee mentioned as " *** - Srilanka" in final invoice received from Yaroslavl, therefore does not matter. It is Yaroslav's own export matter (how they want to document it) and hence irrespective of consignee mentioned as ***, Srilanka, Trigon is authorised to sell goods in India to customers of their choice. Each MT of goods supplied to Trigon Gulf is properly documented by them and BL copies/invoices can prove final destination as India. It is Yaroslav's internal matter as to how to create export documentation. It has no financial bearing."*

65. In their response, M/s Trigon Gulf replied inter alia as follows:

*"Point 3: Tigon gulf also supplies to India, Carbon Black produced by M/S *** - Russia and M/S ***-China. Volume of both these companies however is very small to justify filing questionnaire response. Trigon represents Yaroslav in India. Yaroslav and Trigon have submitted their response regarding MTR and cooperated with whole investigation to avoid Anti Dumping*

*Point 5: Kindly also refer to m/s Yaroslavsky's response (point 7) on same subject. Trigon gulf has provided all documentary proofs of each MT procured from Yaroslav and shipped to India to various customers. It was Yaroslav's export documentation which shows consignee as *** Shrilanka, which is irrelevant to current investigations."*

66. In view of the above the Authority does not find the questionnaire response of M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod (producer) and M/s Trigon Gulf, FZCO Dubai, UAE as reliable and beyond reasonable doubt. The Authority therefore does not consider their responses and not to grant individual dumping margin to the concerned producer - exporter combination.

Determination of Normal value in respect of Russia, Thailand and Australia

67. Since, the response filed by M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod (producer) and M/s Trigon Gulf, FZCO Dubai, UAE has not been accepted by the Authority and no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from Russia, Thailand and Australia, the Authority has determined the Normal Value in respect of Russia, Thailand and Australia as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Accordingly Normal value at Ex-factory level in respect of Russia, Thailand and Australia is determined on the basis of methodology explained in para 54 and 55 of this finding. The weighted average Normal value for the grades exported to India so determined is US\$ ***per MT, US\$ ***per MT and US\$ ***per MT respectively.

I. **EXPORT PRICE**

Export price for the responding exporters

68. The Authority examined whether the export prices in respect of responding exporters could be determined on the basis of questionnaire responses filed by these interested parties.

M/s Jinneng Science & Technology Co., Ltd, Jinan, China PR (producer/exporter)

69. Separate weighted average export price to India has been determined for each grade/type of the subject goods, as explained above. The adjustments have been made on account of inland transportation, overseas transportation, overseas insurance, credit, bank charges and export packing as claimed by the exporter. During the verification Jinneng claimed that there is no VAT refund for the exports of the subject goods. In the exporters verification report it was noted that no adjustment has been claimed by M/s Jinneng for the difference between VAT paid/payable and the VAT refund. In their reply to the verification report Jinneng claimed that the prices shown in the Appendix 2 were net of VAT and therefore no adjustments have been claimed by them. On the basis of the verified data, the Authority notes that Jinneng exported the subject goods to India ***MT during the POI for the gross value of US\$ ***and ***MT during the post-POI (April, 2011 – September, 2011) for the gross value of US\$ **. After making the acceptable adjustments, the Authority determines the export price of Jinneng as US\$***per MT during the POI.

834 40/13-32

M/s Jiangxi Black Cat Carbon Inc. Ltd., Jingdezhen, China PR (producer/exporter)

70. It was claimed by M/s Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc., Ltd, China PR that during the POI of the subject MTR i.e. April 2010 – March 2011, they have made part of their export sales to India, through their related company M/s Jingdezhen KMZ Group Imp & Exp Co., Ltd. (“KMZ”). During on the spot verification, Black Cat was requested to clarify why their related party M/s KMZ did not file the exporters’ questionnaire response since they have also exported the product concerned to India during POI. It was explained by Black Cat that KMZ is only acting as an agent of Black Cat. They are not acting as exporter/trader of the product concerned as they are not earning any profit in any transaction. The comments furnished by the party in the above regard pursuant to the verification report were also found to be unsatisfactory.
71. The Authority notes that without any response filed by M/s KMZ, the related party of M/s Black Cat, the export price of Black Cat cannot be considered as representative export price of the entire group company’s exports to India. In view of the above position the Authority does not grant individual dumping margin to M/s Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc., Ltd, China PR.

Determination of Export Price in respect of Non-Co-operative Exporters/Producers from China PR

72. The Authority has decided to determine the Export Price in respect of non-cooperative exporters as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, the export price at ex-factory level in respect of all non-co-operative exporters from China PR is determined as US\$ *** per MT.

Determination of Export Price in respect of Exporters/Producers from Russia, Australia and Thailand

73. As mentioned in earlier para, the Authority has decided not to accept the response filed by M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod (producer) and M/s Trigon Gulf, FZCO Dubai, UAE (exporter) and since no other response has been received from any of the producers/exporters of the subject goods from Russia as well as Thailand and Australia, the Authority has decided to determine their Export Price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. The data has been collated as per the information provided by the applicant and the information provided by the co-operative exporter. The Authority has considered DGCI & S import data during POI for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from these countries. Adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges, as claimed by the domestic industry, have been considered to arrive at the net export price in respect of these countries. Accordingly, the export price at ex-factory level is determined as US\$ *** per MT from Russia, US\$ *** per MT from Australia and US \$ *** per MT from Thailand.

J. DUMPING MARGIN

74. Considering the Normal values and Export prices as determined above, the dumping margins are determined as follows:

Exporter	Country	Dumping Margin US\$ per MT	Dumping Margin as %	Dumping Margin Range %
M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd.	China PR	***	***	35 - 45
Non-Co-operative producers/ exporters	China PR	***	***	55 - 65
Non-Co-operative producers/ exporters	Russia	***	***	10 - 20
Non- Co-operative producers/ exporters	Australia	***	***	10 - 20
Non-Co-operative producers/ exporters	Thailand	***	***	5 - 15

K. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Applicant (ATMA), Exporters, Importers and Other Interested Parties

75. Following are the submissions made by the applicant and other interested parties in this regard:

- a) Import prices have significantly improved, by 24% from all subject countries between POI of original investigation and 2010-11. The existing measures need to be reviewed for the sole reason that the import prices have changed considerably and significantly during 2008-09, 2009-10 and 2010-11 when compared with 2007-08 as well as the POI of the original investigation.
 - a. Purchase price of CBFS, the major raw material has declined substantially – a decline of 7% in crude prices between POI of original investigation and 2010-11. The cost of another raw material, Tar Oil, has also declined. Therefore, non-injurious price should have come down drastically.
 - b. There has been an increase in the capacity of the domestic industry for the subject product. There has been significant changes in the selling prices of the Indian domestic industry and improvement in all parameters. The performance of the domestic industry has improved significantly for which the duty was imposed; the duty should now be withdrawn as having served its purpose.

- c. The performance of the domestic industry started deteriorating only after the information that the petition has been filed by ATMA for withdrawal of AD Duty was known in the market. The domestic industry intentionally kept its sales volume and prices lower so as to show injury in the post POR period.
 - d. Closure of Cabot India's carbon black facility was not because of any adverse impact of alleged imports but was purely a management decision for better cost structuring, ability to expand and other factors
 - e. There has been an increase of 60% in the exports of the domestic industry between POI of original investigation and 2010-11. This indicates that the domestic industry can compete internationally.
 - f. The DGSGD has noted in its preliminary findings that unit price of imports have also risen and the price is not the factor of injury. This also clearly establishes that the domestic industry is not suffering injury due to dumping.
 - g. The claims of the domestic industry in the context of depreciation of re-valued assets, working capital etc., for calculating NIP should be outrightly rejected as the proposed methodology will be a deviation from established and consistent practice of Authority.
 - h. The Authority should not blindly accept the claim of the domestic industry that the return on capital employed of 22% shall be granted to it as per the consistent practice. The Authority can utmost grant so much returns that the domestic industry earned when it was not suffering injury.
-
- b) Determination of NIP and its comparison with domestic industry's NSR is necessary to determine whether the domestic industry is earning well over its cost to make and sell and ROCE. Domestic industry is earning high return considering huge investments and therefore they have wrongly submitted that they are still suffering injury.
 - c) Contents of financial statements of the domestic industry are in contradiction with the contention of the domestic industry – robust financial results, increasing capacity, no injury from imports. Circumstances that existed in the previous investigation have materially changed and there is no likelihood of recurrence of injury to domestic industry.
 - d) The surge in imports is being taken care of by the DG Safeguards and DGAD is not required to dwell into this problem. Moreover, the safeguards investigation being conducted by the DG Safeguards is China specific and not relevant to other subject countries.
 - e) The robust increase in the capacity of the domestic industry shows that they are not facing any problem in raising capital. As far as capacity is concerned, the domestic industry is in the same position as exporter from subject countries and is dumping the goods in other countries.

- f) During the POI of the original investigation, total installed capacity of the domestic industry was 500,000 MT. Capacity additions have been consistently added to meet the expected demand. During the POI of present review investigation, capacity addition of 175,000 MT has been made by the petitioner taking the total capacity to 675,000 MT. Similarly, some new entrants have come into the market, while others have exited. This change in dynamics of domestic industry of Carbon Black in India constitutes a changed circumstance, which warrants review of existing anti-dumping duties.
- g) The contention of the domestic industry that while interpreting Annexure III to the rules, no past practice should cloud the way in which text is to be interpreted is not correct. Annexure III is only a codification of the practice that is followed by the Authority and NIP should be determined by the Authority as per the law laid down in Annexure III.
- h) DGAD is not an appellate authority to consider the findings of a safeguard finding. DGAD is required to examine the performance during the defined Period of Investigation (POI) with the defined injury period prior to the POI, unlike safeguard investigation, which does not have a specified investigation period.
- i) Although DG Safeguards recommended imposition of safeguard duty for a period of three years, Ministry of Finance considered that imposition of safeguard duties for a period of 15 months is sufficient for domestic industry to overcome the effects of injurious effects of imports from China PR. Thus, even according to Central Government, injury due to imports from China PR beyond 31st December 2013 is unlikely.
- j) Imports from Russia are coming down on regular basis and as such have no impact on the injury to the domestic industry. Injury to the domestic industry is self-inflicted and not on account of imports.
- k) Russia/Yaroslavaskiye has no surplus capacities available with them.
- l) The MTR investigation should be restricted to the POR of the present investigation and not consider post POR data as it would result in consideration of new data every now and then and thereby result in delay in completion of investigation.
- m) The main reason for difference in prices of Chinese product and domestic product is due to difference in raw material used by Domestic industry and its Chinese counterpart. Merely because Chinese producers are able to produce the subject goods at cheaper price does not imply they are dumping the goods. Any injury arising out of different raw materials used cannot be attributed to dumping.
- n) The circumstances that existed during the previous investigation have seen a material change and there is no likelihood of recurrence of injury to domestic industry, specifically from Yarosalaskiy Russia.

SUMBISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

76. The domestic industry has submitted as under:-

834 46/13 - 33

- a. Demand for the product under consideration declined in 2008-09 as a result of recession in the automobile industry and then increased significantly in 2009-10 and POI. The demand has further increased in the present/current period. The domestic industry has increased its capacity in 2009-10 and 2010-11 in anticipation of increase in demand and considering the production plans of the consumer industry.
- b. Imports have increased in absolute terms, in relation to production of the product in India and in relation to demand of the subject goods in India. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and increase in the selling price was less than the increase in the cost of production. The imports are thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.
- c. The production and sales volumes have increased. However, post 2010-11, even when capacity has further increased, the domestic sales have dramatically fallen and consequently production & capacity utilization have declined.
- d. The capacity could not be utilized to the optimum level in view of the fact that the volume of dumped imports once again increased significantly. This has led to piling of inventories despite underutilized capacities. Further, inventories have significantly increased in April-Dec., 2011 period despite significant reduction in production
- e. Cost of production increased in 2008-09, declined in 2009-10 and then again increased in 2010-11. The selling price shows a similar trend. However, the selling price did not increase at the same rate as cost of sales in 2010-11. Resultantly, profitability of the domestic industry, which improved in 2009-10, after a loss in 2008-09; was comparatively low in 2010-11.
- f. Thus, profitability of the domestic industry had already started deteriorating from the investigation period of the present case. The situation deteriorated dramatically thereafter.
- g. Although the market share of the domestic industry increased, there is no significant change in the market share of Indian producers at large. In any case, post imposition of anti-dumping duty, the market share of the Indian producers should have improved substantially back to the market share of domestic industry prior to dumping. Yet, the domestic industry has not reached back the market share gained earlier.
- h. Cabot India is not part of domestic industry and has not sought continued imposition of Anti-dumping duties.
- i. The decline in CBFS *per se* does not establish the need for withdrawal of anti-dumping duty. The interested parties must establish that the injury to the domestic industry is unlikely in the event of withdrawal of anti dumping duty. As established in the written submissions, should the domestic industry reduce the prices to the extent of anti dumping duty, it would suffer significant financial losses.
- j. Increase in exports volumes does not show competitiveness of such export volumes. It only shows the inability of the domestic industry to sell in the domestic market or better profitability in the export market.
- k. Information contained in the Annual Report is not relevant for the reason that the same is not restricted to the product under consideration and extends to other products

as well. Also the information in the annual report is for both for exports and domestic operations.

- l. Domestic Industry suffered continued injury from dumping even after the imposition of anti-dumping duty. The Domestic Industry is yet to earn reasonable rate of return. The domestic industry is looking for utilization of its capacities to the extent demand exists in the Country. It was expected that the condition of the Domestic Industry would improve under the discipline of the anti-dumping duty. However, the condition of the domestic industry remained fragile.
- m. Majority consumers in tyre segment decide their procurement on the basis of relative prices offered by the foreign producers and domestic industry. If the prices offered by the foreign producers are lower, the consumers increase their off take from foreign producers. This gets clearly established by the significant increase in imports from China in the most recent period.
- n. No current dumping or no current injury is insufficient to recommend withdrawal of anti-dumping duty. The exporter must establish no injury in the event of withdrawal of Anti-Dumping Duty.
- o. As regards the submission that contents of financial statements of the domestic industry are in contradiction with the contention of the domestic industry, it is submitted that the information contained in the Annual Report is not relevant for the reason that the same is not restricted to the product under consideration and extends to other products as well. Also the information in the annual report is for both for exports and domestic operations.
- p. The decline in imports of the subject goods from Russia is not relevant as the fact of decline in exports from individual countries is of no relevance in a Mid Term Review. What is relevant is whether dumping is unlikely to resume in larger proportion and the domestic industry is unlikely to suffer injury in the event of withdrawal of duties. There are significant exports from Russia to various global destinations. The current volume of global exports itself is sufficient to show likelihood of injury.
- q. Although the capacity utilization of the domestic industry declined, the increase in production and domestic sales is because of increase in demand. The market share of the domestic industry after increasing till 2010-11 fell sharply in Q2, 2011-12. Profitability improved till 2009-10 and then declined in current period of investigation. The profitability in the current period of investigation was worse than the profitability in 2007-08. Further, profitability deteriorated steeply and was at a very low level in Q3 2011-12.
- r. Safeguard duty imposed covers injury caused by dumping only in respect of China and that too in a situation where the quantum of safeguard duty is higher than the quantum of anti-dumping duty. If quantum of anti-dumping duty is higher than quantum of safeguard duty, it follows that both safeguard duty and anti-dumping duty to the extent of differential amounts are payable. It also follows that full injury in those cases has not been addressed by safeguard duty.

- s. The safeguard duty has been restricted upto 31.12.2013 not because the Government considered that the domestic industry would suffer “no injury” thereafter. The duty has been restricted because the Government considers that safeguard duty cannot be charged under WTO obligations after 31.12.2013.
- t. The increase in capacity of Domestic Industry and export performance do not establish that withdrawal of ADD shall not cause injury to the domestic industry. Increase in capacity at the least establishes enhanced need for fair market situation. Increased exports are only out of available capacities and not at the cost of domestic market.
- u. Any comparison of NIP with NSR in a review investigation would be insufficient to conclude whether ADD can be revoked. If the difference is positive, it implies that the industry is unable to realize NIP. If the difference is negative, it does not even mean “no adverse price effect”.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

77. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below:
78. As regards submission of the petitioner and other interested parties concerning closure of Cabot India's carbon black facility, Authority notes that Cabot India is not a part of domestic industry and therefore issue raised by the applicant in this regard is not relevant.
79. The applicant and other interested parties have contended that in the preliminary finding the Directorate General of Safeguard Duties (DGSGD) has noted that unit price of imports have also risen and the price is not the factor of injury, thus establishing absence of injury to the domestic industry due to dumping. The Authority notes that the DGSGD has already issued the final findings in this respect vide their notification no. G S R D- 22011/12/2011 dated 31st July, 2012. The relevant paras of the final finding of DGSGD are extracted below:

“98. The performance of domestic industry shows that despite increase in demand of Carbon Black over the POI, the market share of domestic industry has decreased and that of Chinese imports has increased. It is also seen that after imposition of Anti-Dumping duty (ADD) in year 2009-10, the price undercutting, both with and without ADD for imports from China has increased.

99. It is observed that even though there is a rise in import price in recent period, the same is far lower than the selling price of the domestic industry which has led to increase in price difference between domestic industry's Selling Price and landed price of import. This has resulted in consumers

switching over to the imports from China PR and has caused grave market disruption and consequential injury to the domestic industry which establish the causal link between increased import and disruption caused."

"111. On the basis of the above findings it is seen that

- a. *Imports of the product under consideration have increased over the injury period in absolute terms with a sharp increase in imports in the recent period,*
- b. *Increased imports of Carbon Black from People's Republic of China have caused and threatened to cause market disruption to the domestic industry/producers of Carbon Black and*
- c. *It has been established that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports from People's Republic of China; and*
- d. *It will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of Carbon Black from China PR."*

80. As regards submission of the applicant and other interested parties concerning determination of NIP and its comparison with domestic industry's NSR, the Authority notes that the difference between NIP and NSR is one of the parameters of injury analysis in an anti-dumping investigation, but not the sole parameter. Such analysis cannot be treated as the sole basis for concluding whether or not there is injury to domestic industry on account of dumping. Moreover, in a review investigation the focus of analysis is likelihood of injury to the domestic industry in the event of revocation of duty and not current injury as such.
81. As regards submission of the applicant and other interested parties concerning methodology of determination of NIP, the Authority notes that relevant guidelines in this regard is well laid down under Annexure III of Anti-dumping Rules.
82. The applicant and other interested parties have contended that in 2010 Chinese producers were holding as much of additional capacity as of now and the same will not impact the Indian market in the future also. The Authority notes that excess capacity in a subject country is an important indicator of likelihood of dumping in the event of revocation of Anti-dumping duty. Since it has been acknowledged by the petitioner that Chinese producers have excess capacity, present investigation being review investigation, such excess production capacity in China cannot be ignored.

834 4/13-34

83. As regards submission of the petitioner and other interested parties that the Authority should not accept the claim of return on capital employed as 22%, it is noted that it is the consistent practice of the Authority to allow a return of 22% on capital employed.

L. Cumulative assessment

84. Attention is invited to Annexure II para (iii) of the AD Rules which provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

- a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

85. In this regard the Authority notes that:

- The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
- The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed except from Iran as already recorded in relevant section of these findings);
- Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the following:
 - a) The domestic industry produces various grades of the subject goods. Similar grades are being produced by producers from the subject countries and supplied to India. The subject goods manufactured by the producers from the subject countries inter-se and in comparison to the product manufactured by the domestic industry has comparable properties. In other words, the subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are inter-se like articles.
 - b) There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material. Imported and domestic materials are, therefore, being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product and inter-se imported product.

- c) The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the same product in the same periods to the same set of customers. The sales channels are comparable.
- d) Volume of imports from each of the subject countries is significant.
- e) Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers.

In view of the above, the Authority considers, it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from Australia, China PR, Russia and Thailand.

86. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. Annexure II of the Anti-dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.
87. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as follows: "*The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*"
88. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties. For analyzing the injury parameters, all relevant documents including the balance sheet of the Domestic Industry have been examined and verified by the Authority. The issues relating to the interest of the Indian industry and other issues have also been dealt by the Authority under appropriate headings.

Demand and market share

89. It is noted that demand for the product has shown significant and consistent increase over the injury period (except 2008-09) and even post POI.

Periods	Domestic Sales of Domestic Industry	Sales of Other Indian Producers	Imports Subject Countries	Imports Other Countries	Demand/consumption	Trend
	MT	MT	MT	MT	MT	Indexed
Injury period with POI						
2007-08	345641	111,826	48,209	14,858	520,534	100
2008-09	340067	98,052	43,825	7,506	489,449	94
2009-10	404649	119,391	57,605	8,082	589,727	113
2010-11	462280	109,537	46,273	16,312	634,403	122
Post POI						
Q1(11-12)annualized	471,602	104,292	40,880	17,936	634,710	122
Q2(11-12)annualized	390,488	132,000	116,333	27,757	666,578	128

Import volumes and market share

Market Share	Units	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12-Q1	11-12-Q2
Domestic Industry	%	66	69	69	73	74	59
Other Indian Producers	%	21	20	20	17	16	20
Subject Countries	%	9	9	10	7	6	17
Other Countries	%	3	2	1	3	3	4
Demand/consumption	%	100	100	100	100	100	100
Imports in relation to Production	%	10	11	12	8	6	19
Imports in relation to Domestic Sales	%	14	13	14	10	9	30

90. It is seen that: -

- i. The imports during POI have increased as compared to the immediate preceding year as well as the base year. However, during Post POI, in Q2, the imports have significantly increased vis-a-vis the entire injury period including the POI.
- ii. Imports from subject countries have slightly declined in relation to production and consumption in India during POI as compared to the base year. It is also noted that the imports in relation to production and consumption have increased significantly in Q2, the imports have significantly increased vis-a-vis the entire injury period including the POI.
- iii. The Authority notes that the market share of the domestic industry has increased from the level of 66% during the base year to 73% during the POI. But the share of the domestic industry has drastically declined during Q2 period of Post POI as compared to the entire injury period. The market share of other Indian producers, which has remained more or less stagnant throughout the injury period including the POI, has increased during Q2 of post POI. On the contrary, the market share of the subject countries, which has declined during POI as compared to the base year, has registered a significant increase during Q2 of Post POI.

Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

91. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

92. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject countries in relation to injury period including POI and Post POI.

८३४ ९/१३-३५

Period	Cost of Sales	Trend	Increase/decrease over base year	Selling Price	Trend	Increase/decrease over base year
	Rs/MT	%		Rs/MT		%
Injury period with POI						
2007-08	***	100	-	***	100	-
2008-09	***	150	***	***	126	***
2009-10	***	124	***	***	122	***
2010-11(POI)	***	153	***	***	149	***
Post POI						
Q1(11-12) annualized	***	169	***	***	156	***
Q2(11-12) annualized	***	186	***	***	168	***

93. From the above, the Authority notes that there was significant increase in both costs of sales as well as selling price during POI, compared to the base year. The Authority notes that the increase is in selling price is not in proportion to the increase in cost price during POI as compared to immediate preceding year. This indicates price suppression effect whereby the domestic industry has not been able to realize the selling price commensurate with increase in the cost of sales. Further there was significant increase in both costs of sales as well as selling price during post POI as compared to POI, but increase in selling price has fallen much short of the increase in cost of sales. This indicates that the price suppression effect of the dumped imports has worsened during Post POI.

Price undercutting and Price underselling effects

Price Undercutting

94. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty and education cess to the export / CIF prices from the subject countries, as reported by each responding exporter. For others category, landed price has been computed by adding applicable basic customs duty and education cess to the Assessable value as per DGCI& S data.

Country	Landed Value without ADD	Landed Value with ADD	NSR	Price undercutting without ADD		Price undercutting with ADD		Price Undercutting Without ADD Range	Price Undercutting With ADD Range
	Rs./MT	Rs./MT	Rs./MT	Rs./MT	%	Rs./MT	%		
POI									
Australia	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
China	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
Thailand	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
Russia	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-(10)
Subject Countries	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
Post POI									
Australia	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
China	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-4
Thailand	***	***	***	***	***	***	***	0-10	0-(10)
Russia	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10
Subject Countries	***	***	***	***	***	***	***	5-15	0-10

95. The Authority notes that the price undercutting of dumped imports from the subject countries on the domestic price during POI as well as Post POI and with ADD and without ADD is positive. However, the price undercutting in respect of Russia and Thailand is negative with the anti-dumping duty.

Price Underselling

96. For the purpose of price underselling the landed prices of the imports from subject country have been compared with the Non-injurious price of the domestic industry determined for the POI as well as post POI. It shows that while the underselling was negative during the POI, the same is positive during post POI.

SN	Country	Landed Price without ADD	NIP	Underselling			
				Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%
Period of Investigation							
1	Australia	***	***	***	***	***	0 - (10)
2	China	***	***	***	***	***	0 - (10)

3	Thailand	***	***	***	***	(5) - (15)
4	Russia	***	***	***	***	0 - (10)
Post Period of Investigation						
1	Australia	***	***	***	***	5 - 15
2	China	***	***	***	***	5 - 15
3	Thailand	***	***	***	***	0 - 10
4	Russia	***	***	***	***	5 - 15

M. Examination of other Economic Parameters of Domestic Industry

Sales volumes

97. Sales volumes of the domestic industry are analyzed over the injury period. The position is as follows:

Period	Domestic Sales Volume
MT	
Injury period with POI	
2007-08	345641
2008-09	340067
2009-10	404649
2010-11	462280
Post POI	
Q1(11-12) Annualized	471,602
Q2(11-12) Annualized	390,488

It is noted that the domestic sales volume have increased during POI. The domestic sales have also marginally increased during Q1 of Post POI as compared to the POI, but during Q2 period of post POI the domestic sales of domestic industry has significantly declined.

Production, Capacity and Capacity Utilization

98. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Period	Capacity	Production	Capacity Utilization
MT	MT	MT	%
Injury period with POI			
2007-08	485,000	465,586	96%
2008-09	500,000	414,226	83%
2009-10	590,000	491,743	83%
2010-11	674,000	581,508	86%

Post POI			
Q1(11-12) Annualized	724,000	654,113	90%
Q2(11-12) Annualized	724,004	598,025	83%

It is noted that both the capacity has increased over the injury period including POI. However, the production has increased in the injury period with the exception of 2008-09, it has declined. The increasing trend is also reflected during Q1 of post POI period. But during Q2 of post POI period the volume of production has declined. It is further noted that the capacity utilization of the domestic industry has declined during POI as compared to base year and further declined during the Q2 of Post POI period.

Inventories:

99. Data relating to inventories shows as follows:

Period	Opening	Closing	Average stock
	MT	MT	MT
Injury period with POI			
2007-08	8,494	10,025	9,259
2008-09	10,025	9,870	9,948
2009-10	9,870	15,616	12,743
2010-11	15,616	17,554	16,585
Post POI			
Q1(11-12) Annualized	17,554	16,386	16,970
Q2(11-12) Annualized	16,386	20,876	18,631

It is noted that average inventories have increased consistently in the POI as well as in Post POI. The inventory in the second quarter of post POI was significant in spite of reduction in production.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

100. The Profits and actual and potential effects on the cash flow are as follows. With regard to Profit/Loss and cash flow, it is observed that the profitability of domestic industry in terms of profit before tax and interest and cash profit has increased in the POI as compared to base year, but declined thereafter significantly during Q1 and Q2 periods of Post POI.

834 4/13-36

	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Q1(11-12)	Q2(11-12)
Cost of sales	Rs./Mt	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	150	124	159	169	186
Selling Price	Rs./Mt	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	122	149	156	168
Profit/Loss	Rs./Mt	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(56)	111	135	54	26
Profit/Loss before Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(55)	130	181	18	7
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(11.82)	134	185	27	19
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(42)	127	176	25	13

Return on Capital Employed:

101. It is noted from the following Table that Return on capital employed has declined during the POI as compared to base year. Thereafter, it has declined significantly during Q1 and Q2 periods of Post POI.

	Units	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	Post POI (Annualized)	2011-12-Q1	2011-12-Q2
PBIT- Domestic	RsLacs	***	***	***	***	***	***	***
NFA	RsLacs	***	***	***	***	***	***	***
Working Capital	RsLacs	***	***	***	***	***	***	***
Capital Employed	RsLacs	***	***	***	***	***	***	***
Return on Capital employed	%	***	***	***	***	***	***	***
Index		100	-12	97	87	45	54	37

Employment, wages and productivity

102. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Period	No. of employees	Wages	Wages per unit of production	Productivity per employee
	Nos	Rs/Lacs	Rs/MT	MT
Injury period with POI				
2007-08	***	***	***	***
2008-09	***	***	***	***
2009-10	***	***	***	***
2010-11	***	***	***	***
Post POI				
Q1(11-12) Annualized	***	***	***	***
Q2(11-12) Annualized	***	***	***	***

It is seen that there was increase in the number of employees throughout the injury period mainly due to commencement of production in new plants. In line with the above trend, wages paid and productivity also show improvement.

Magnitude of dumping

103. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margins in respect of the imports of the subject goods from the subject countries are significantly positive in both in POI and Post POI.

Growth

104. The Authority notes that the growth of domestic industry was positive during injury period including POI, but the same has deteriorated in post POI, especially during Q2 period of Post POI.

Ability to raise funds:

105. It is noted that the domestic industry has enhanced the Capacity of the subject goods from the base year to POI and in Post POI (i.e. Q1). This signifies that their ability to raise capital industry has not been affected.

N. Magnitude of Injury and Injury Margin

106. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI and Post POI. The injury margin thus determined is as under:

Country	Producer/exporter	NIP of DI (Rs/MT)	Landed price (Rs/MT)	Injury margin	Injury margin %	Injury margin Range
POI						
China PR	M/s Jinneng Science and Technology. Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10
	Any other producer/exporter	***	***	***	***	0-10
Russia	All producer/exporter	***	***	***	***	0-(10)
Australia	All producer/exporter	***	***	***	***	0-(10)
Thailand	All producer/exporter	***	***	***	***	(5)-(15)
Post-POI						
China PR	All producer/exporter	***	***	***	***	5-15
Russia	All producer/exporter	***	***	***	***	5-15
Australia	All producer/exporter	***	***	***	***	5-15
Thailand	All producer/exporter	***	***	***	***	0-10

Conclusion on material injury

107. It is noted that during POI the performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, market share, capacity, profit , cash profit and return on capital employed, but deteriorated in terms of capacity utilization and inventory. However during post POI, especially during Q2 period the economic health of the domestic industry in terms of production, sales volumes, capacity, capacity utilization, inventory, market share, profit, cash profit and return

on capital employed deteriorated. Moreover price undercutting and underselling effects are positive and significant.

O. Other Known Factors & Causal Link

108. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:-

(a) Volume and prices of imports from third countries

The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries have been de-minimis in volume, except South Korea wherein the price is more than that of the subject countries. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant positive growth during the injury period. The Authority further notes that the domestic industry has expanded its capacity during the POI, however the domestic industry is unable to utilize its capacity to the extent of available demand due to dumped imports.

(c) Developments in technology:

The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

(e) Export performance of the domestic industry:

The table below summarises the performance of the domestic industry in respect of exports made by them.

834 9/13-37

	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI Annualised
Volume	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	63	69	101	157

The Authority notes that the export volumes of the domestic industry have increased during the POI vis-à-vis the base year as well as the immediate preceding year. Therefore, export performance cannot be considered as a reason for any injury. Moreover, the price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of present injury assessment.

109. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry, following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports. It is noted that during POI the performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, market share, capacity, profit , cash profit and return on capital employed, but deteriorated in terms of capacity utilization and inventory. However during post POI, especially during Q2 period the overall economic health of the domestic industry in terms of production, sales volumes, capacity, capacity utilization, inventory, market share, profit, cash profit and return on capital employed deteriorated. Thus, the deterioration during post POI, especially during Q2 period in profits, return on capital employed, cash flow, etc. is directly due to dumped imports. Decline in market share has prevented the domestic industry from raising their production and plant utilization.

P. Likelihood of continuation or recurrence of injury

110. The Authority has to determine as to whether the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices or are likely to be exported at dumped prices from the subject countries in the event of withdrawal of anti dumping duties. It is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. It has already been established that the landed value of imports from the subject countries to India was below the selling price of the domestic industry during POI and post POI and the non injurious price in post POI determined for the domestic industry. The Authority has also examined the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry on the basis of information and evidence presented by the various interested parties during the course of the investigations. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increase demand for further imports and,*
- d. Inventories of the article being investigated."*

Submissions made by the Domestic Industry

111. Following submissions are made by Domestic industry

- a) Absence of continued dumping and injury in review period does not imply any likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of withdrawal of anti-dumping duties.
- b) Exporters from subject countries are also dumping in third countries which indicate likelihood dumping in India.
- c) Following factors establish likelihood of continuation of dumping and injury
 - Volume of imports from the subject countries have significantly increased despite imposition of anti-dumping duty.
 - Producers in the subject countries maintain huge capacities to produce carbon black. In case of withdrawal of anti-dumping duty, the volume of imports is bound to increase further.
 - On comparison of the landed price of imports with and without anti-dumping duty with that of the selling price of the Domestic Industry, it would be seen that significant price undercutting exists.
 - The subject country holds a significant market share in the Indian Market. In fact, the market share of dumped imports has only increased. This situation exists in spite of the present anti-dumping duty

- Exporters from the subject countries have very high export orientation worldwide.
- Continued presence of dumped imports has prevented the domestic industry from recovering from past effects of dumping. In the event of withdrawal of current antidumping duty, the domestic industry will have to either decrease the selling price by the amount of ADD or will maintain the current selling price. In either case, it will suffer injury.

Submissions made by the petitioner and other interested parties

112. Following submission are made by petitioner and other interested parties
- a. The performance of the domestic industry is steady and even after withdrawal of Anti-dumping Duty; the domestic industry will not be injured. Without prejudice to earlier submissions, even in the post POR period, the performance of the domestic industry has been commendable compared to the earlier period.
 - b. The allegation of domestic industry regarding dumping by subject countries in third countries is unsubstantiated. If that had really been the case then ADD proceeding would have been initiated and ADD imposed in those countries as well.
 - c. The domestic industry has not been able to substantiate their claim that subject countries has excess capacity
 - d. It is not disputed that the domestic industry was not suffering injury in 2010 even when Chinese producers were holding as much of additional capacity. The excess capacity in China will not impact the Indian market in the future also.

Examination by the Authority

113. Rule 23 of Anti-dumping Rules of India requires the Authority to examine the need for continued imposition of the duty from time to time. The petitioner in its submission has argued that midterm review investigation does not require an examination of likelihood aspects as in the case of a sunset review. However, the Authority is of the view that such an examination would also involve an examination of the lasting nature of the changed circumstances and the likelihood scenario in the event of withdrawal of the duty. In order to determine whether the changed circumstances of dumping is of lasting nature and whether injury to the domestic industry would continue or recur in the future if the duties are removed, the Authority has examined the submissions made by the interested parties. The Authority had called for additional information from the co-operating exporters for the period of investigation, as well as subsequent period immediately following the period of investigation. In this regard, the Authority notes as under:

Volume of Exports Post- POI:

114. In order to examine, the likelihood of injury to the domestic industry due to dumping of the subject goods from the subject countries, the Authority has undertaken analysis of the volume of exports of the subject goods to India and other countries from the subject country during the post-POI period as well. The Authority notes that the volume of the exports from subject countries to India during the POI and post POI on the basis of DGCI& S data was 46174 MT and 78606 MT (Annualized) respectively, showing 70% growth. This trend indicates that there is significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

Market share of Subject Countries in the Indian market

115. The Authority notes that the market share of the subject countries, which has declined during POI as compared to the base year, has registered a significant increase during Q2 period of Post POI, despite the anti-dumping duty in place. On the contrary, while market share of other domestic producers has marginally increased during Post POI, the market share of the domestic industry has significantly declined during the corresponding period; thereby indicating that market share of the domestic industry has been captured by the subject countries. Further, the market share of domestic producers as a whole has also declined significantly. The volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duties

Price attractiveness of Indian market

116. The price at which the subject goods are being exported by subject countries to India is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. At the landed price in India, there is significant undercutting both with and without duty during POI and Post POI. Thus, in the event of the revocation of anti-dumping duties, the Indian prices would be too attractive to the foreign producers and there is strong likelihood that Indian consumers would import substantially due to increasing demand.

Export orientation of foreign producers

117. From the available information it is evident that the producers/exporters from subject countries have tremendous production capacity and are very much export oriented. Considering the increase in demand for the subject goods in Indian Market and its lucrative price, if the anti-dumping duties are revoked, the entire demand in India can be catered by the producers/exporter from subject countries.

834 4/13-38

Surplus capacity

	Qty : '000 MT						
	2000	2005	2009	2010	2011	2012f	2015f
CHINA							
Capacity	1100	2310	4349	5100	5490	5900	6400
Consumption	764	1620	2758	2860	2920	3060	3750
Excess	336	690	1591	2240	2570	2840	2650
RUSSIA							
Capacity	638	703	683	683	718	858	945
Consumption	287	345	234	297	343	380	425
Excess	351	358	449	386	375	478	520
THAILAND							
Capacity	220	370	385	465	465	515	515
Consumption	132	200	240	314	350	367	400
Excess	88	170	145	151	115	148	115
Source :							
Carbon Black World Data Book 2012 Notch consulting Group Published Jan 2012							

118. From the information furnished by the domestic industry as given in table above, the Authority notes that China PR, Russia and Thailand, three out of four subject countries, have substantial surplus capacity for the subject goods. This indicates that in the event of revocation of anti-dumping measures, considering the increase in demand and favourable prices in Indian market, the exportable surplus can find its way to Indian market at dumped price.

Level of current and past dumping margin

119. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigation and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports were continued to be made at dumped prices and is likely to continue with revocation of anti dumping duties. Volume of imports has significantly increased even after imposition of anti-dumping duties. The volume of imports in the current investigation period is higher than even the original investigation period. Further, the volume of imports is likely to increase further in the event of revocation of anti dumping duties, given the significant price undercutting and underselling during the injury period.

120. This proves that producer/exporter from subject countries are involved in dumping the subject goods not only in India but also in other countries. Thus, in the event of revocation of the anti-dumping duty by India, it would not be difficult for the exporters of subject countries to export to India the subject goods at dumped

prices. It is also noted that dumping is continuing from the subject country in India in spite of the antidumping duty in force.

121. As far as continuation or recurrence of injury to the domestic industry is concerned the price levels at which the goods are entering Indian market from the subject country, in spite of the duty in force, is an important indicator. The Authority also notes that in spite of improvement in the condition of the domestic industry in several injury parameters during POI, during post POI, especially during Q2 period the overall economic health of the domestic industry in terms of production, sales volumes, capacity, capacity utilization, inventory, market share, profit, cash profit and return on capital employed deteriorated. Thus, the deterioration during post POI, especially during Q2 period in profits, return on capital employed, cash flow etc. is due to dumped imports.
122. The essential facts of the investigation, as analysed by the Authority in this finding, sufficiently prove that the changed circumstances, on the basis of which Automobile Tyre Manufacturers Association (ATMA) has sought for the mid-term review, are not of lasting nature and there is a likelihood of continuation/recurrence/intensification of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry, in the event of reduction/revocation of the anti-dumping duty.

Q. Indian industry's interest and other issues

123. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.
124. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Further, imposition of anti-dumping duties, would not affect the availability of the product to the consumers.

R. Post Disclosure Comments

125. The following are the Post-disclosure comments by the producers/exporters/imports/other interested parties:

- i. Inadequate time granted by the Authority for post disclosure comments.
- ii. Excessive Confidentiality as regards computation of normal value, export price, NIP, etc.
- iii. Allowing 22% return on capital employed is not justified without stating specific reasons.
- iv. Even though safeguard duty was recommended for a period of 3 years, DGAD has not at all considered this fact while conducting injury and recurrence of injury analysis.
- v. The disclosure statement is not clear whether the Authority considered the reduction in prices of major raw material while determining NIP of the domestic industry.
- vi. The inclusion of Hi-Tech Carbon within the scope of domestic industry is not justified in view of significant exports of subject goods by their related party in Thailand. Further, the disclosure statement does not contain a specific finding with respect to each and every factor considered by the domestic industry while justifying inclusion of Hi-tech Carbon within the scope of domestic industry.
- vii. While DGAD has considered that duty free imports made through related exporter have not adversely affected the domestic industry, yet at the same time, DGAD has not segregated such imports for the purposes of injury analysis.
- viii. Comparison of NIP and NSR needs to be done by the Authority while conducting injury analysis.
- ix. Domestic sales, production and capacity utilization has consistently improved during the last 4 years as well as during first quarter of post POI period. Only during the second quarter post POI, the volume parameters have shown a decline. Such being the case, it will be incorrect to hold that injury to domestic industry is likely.
- x. The domestic industry was not at all injured during the review period and in fact recorded significant increase in profits, sales, production and capacity utilization.
- xi. There exists no injury to the domestic industry at present nor there any likelihood of recurrence of injury to domestic industry.
- xii. DGAD has held that presence of excess capacities in China may result in dumping into India. It is submitted that China PR has been holding excess capacity for quite a long time and have not adversely impacted the Indian market anyway.
- xiii. From para 105 of the disclosure statement, it is seen that DGAD has arrived at a negative injury margin for Russia, Australia and Thailand. Since in terms of Section 9A(1), anti-dumping duty has to be lesser of dumping margin or injury margin, DGAD is mandated to recommend anti-dumping duty based on lower of the two margins.

- xiv. Since DGAD during the original investigation did not ask Jingdezhen KMZ to file any response, treatment of Black Cat as non-cooperative now is unjustified.
 - xv. In respect of Yaroslavaskiy and Trigon, mentioning of country of consignee as Colombo in the export documents is merely a technical lapse having no financial or other bearing on the investigation results and therefore the same may be ignored by the Authority.
 - xvi. Volume of exports of OMSK - Russia produce by Trigon is very small and therefore this does not justify filing questionnaire response.
 - xvii. In terms of subsection 6A to section 9A of Customs Tariff Act, DGAD has no power to reject the information given by an exporter or producer.
 - xviii. There is neither any economic rationale nor any legal basis for deducting the non-refundable VAT from the export realization.
126. The following are the Post-disclosure comments by the domestic industry:
- i. The present investigations being a midterm review investigation, the methodology applied for determination of normal value, export price, dumping margin, non injurious price and injury margin should be the same as applied in the original investigation.
 - ii. The quantum of anti dumping duty is not required to be modified in the present case, as the extension of duty is on the grounds of likelihood of dumping and consequent injury.
 - iii. Facts on record do not justify exclusion of Hi-tech Carbon Black from the scope of Domestic Industry.
 - iv. The imports made under duty exemption scheme cannot be considered to have not affected the price in the domestic market
 - v. The difference between NIP and NSR is one of the parameters of injury analysis in an anti-dumping investigation, but not the sole parameter.
 - vi. Though domestic industry has shown positive growth in the economic parameters such as production, domestic sales, productivity, profit, cash profit, ROCE, etc in POI as compared to the base year, the, analysis of post-POI data shows that the domestic industry would suffer significant injury if anti dumping duties is discontinued at this stage.
 - vii. An examination in midterm review would involve an examination of the lasting nature of the changed circumstances and the likelihood scenario in the event of withdrawal of the duty.
 - viii. Determination of NIP by the Designated Authority is not correct in respect of treatment given to lean gas generated in the production process of carbon black by the domestic industry.

8349/13-39

Examination by the Authority

127. The Authority notes that the post-disclosure comments made by the parties are mostly unsubstantiated reiterations of their earlier submissions. The post-disclosure comments, considered relevant by the Authority, are addressed below:

- i. As regards the submission that the Authority granted inadequate time for post disclosure comments, the Authority notes that adequate opportunities were granted to the interested parties during the course of the investigation.
- ii. As regards excessive confidentiality adopted by the Authority in respect of computation of normal value, export price, NIP etc, the Authority notes that in terms of the anti-dumping rules, non-confidential facts/data made available in the form of a public file and the methodology of computing normal value, export price, dumping margin, injury margin, NIP etc are very much disclosed in this finding. Moreover, the details of the export price and NIP were provided to the concerned exporters and the domestic industry.
- iii. As regards the submission that the Authority allowed 22% return on capital employed without specific reasons, the Authority notes that it is the consistent practice of the Authority to allow a return of 22% on capital employed.
- iv. The interested parties have submitted that even though safeguard duty was recommended for a period of 3 years, DGAD has not at all considered this fact while conducting injury and recurrence of injury analysis. In this regard the Authority notes that both the measures are governed by different rules intended to address different set of situations arising out of unfair trade practices adopted by the exporters. Moreover, as established in this finding, there is a likelihood of recurrence/intensification of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of revocation of the anti-dumping duties.
- v. As regards the submission that the disclosure statement is not clear whether the Authority considered the reduction in prices of major raw material while determining NIP of the domestic industry, the Authority notes that the NIP has been determined as per the Rules based on verified data.

- vi. The interested parties have submitted that inclusion of Hi-Tech Carbon within the scope of domestic industry is not justified in view of significant exports of subject goods by their related party in Thailand and the disclosure statement does not contain a specific finding with respect to each and every factor considered by the domestic industry while justifying inclusion of Hi-tech Carbon within the scope of domestic industry. In this regard the Authority notes that all the relevant parameters have been considered while considering Hitech Carbon as domestic industry under the Rules.
- vii. As regards the contention that in terms of subsection 6A to section 9A of Customs Tariff Act DGAD has no power to reject the information given by an exporter or producer, the Authority notes that the responses filed by M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod (producer) and M/s Trigon Gulf, FZCO Dubai, UAE have not been accepted by the Authority as the same were not found to be reliable and beyond reasonable doubt, for the reasons already recorded in this finding.
- viii. As regards the submission made by Jinneng that there is neither any economic rationale nor any legal basis for deducting the non-refundable VAT from the export realization, the Authority notes that the export price has been determined considering the export price claimed by the concerned exporters and as per the Rules.
- ix. The Authority notes that one of the interested parties has submitted that conclusion of likelihood of recurrence of injury by the Authority based on the performance of 3 months alone are incorrect and improper. In this connection, the Authority notes from the audited accounts of the domestic industry for the year 2011-12 that the financial performance of domestic industry in terms of Profit Before Interest and Tax (PBIT) and Return on Investment (ROI) has declined significantly as compared to the POI.
- x. As regards the comment of domestic industry not to consider the profit on sale of power in determination of NIP, the Authority notes that the lean gas generated in the manufacture of carbon black is used in generation of power and no value has been assigned for such lean gas. The Authority further notes that the domestic industry has sold part of the power generated by them to outside parties and made profit. The confidential version of the submissions made by the domestic industry in this regard has been examined and no merit has been found in them. Accordingly, the Authority has determined the NIP after adjusting the profit on sale of power generated from the lean gas generated while producing carbon black.

834 96/13-40

S. Conclusions

128. Having initiated and conducted the review as requested by ATMA and having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submissions made by the interested parties or otherwise as recorded in this finding and on the basis of the analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
- i. In spite of the anti-dumping duty in force, the subject countries command a significant share in the Indian market.
 - ii. The landed price of imports from the subject countries, even with anti-dumping duty, is lower than the domestic selling price.
 - iii. The exports from subject countries are causing positive price undercutting with as well as without anti-dumping duty during the POI and post-POI and positive underselling in Post POI.
 - iv. In spite of improvement in the condition of the domestic industry in several injury parameters during POI, during post POI, especially during Q2 period, the overall economic health of the domestic industry in terms of production, sales volume, capacity, capacity utilization, inventory, market share, profit, cash profit and return on capital employed, etc, deteriorated. Thus, the deterioration during post POI, especially during Q2 period in profits, return on capital employed, cash flow etc. is directly due to dumped imports.
 - v. The changed circumstances of dumping and injury are not of lasting nature and are likely to recur or intensify if the duties are revoked.

T. Recommendation

129. Having concluded that the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation/resumption/intensification of dumping and injury on account of imports of the subject goods from the subject countries, if the duties are revoked, the Authority holds that the measure is required to be extended in respect of imports of the subject goods from the subject countries.
130. The responses filed by M/s Jiangxi Black Cat Carbon Inc. Ltd., Jingdezhen, China PR and M/s. Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod, Russia and its connected exporter M/s Trigon Gulf FZCO, UAE have not been accepted by the Authority due to the reasons already recorded in this finding. In view of the above the Authority does not recommend any specific duty to these parties. The Authority further notes that no other exporter/producer from the subject countries, which had been granted specific duties in the original investigation, has cooperated in this Mid-Term Review

investigation. In view of the above the Authority does not recommend any specific duty to such non-cooperative exporters/producers. Moreover, the Authority does not recommend specific duty to the other respondent producer/exporter from China PR namely M/s. Jinneng Science & Technology Co. Ltd., in view of the fact that the alleged changed circumstances are not found to be of lasting nature and dumping and injury are likely to recur or intensify if the anti-dumping duties are revoked.

131. The Authority had earlier recommended imposition of antidumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries vide Final Findings Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009 and duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 6/2010-Customs dated 28th January, 2010. In view of the above position, the Authority considers it necessary and recommends continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, as specified in the table below:

Duty Table

.No.	Heading/ Subheading	Description of goods *	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Australia	Australia	Any	Any	0.330	KG	US Dollar
2	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Australia	Any	Any	Any	0.330	KG	US Dollar
3	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Any	Australia	Any	Any	0.330	KG	US Dollar
4	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	China PR	China PR	Any	Any	0.423	KG	US Dollar
5	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	China PR	Any	Any	Any	0.423	KG	US Dollar
6	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Any	China PR	Any	Any	0.423	KG	US Dollar
7	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Russia	Russia	Any	Any	0.391	KG	US Dollar
8	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Russia	Any	Any	Any	0.391	KG	US Dollar
9	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Any	Russia	Any	Any	0.391	KG	US Dollar

10	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Thailand	Thailand	Any	Any	0.186	KG	US Dollar
11	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Thailand	Any	Any	Any	0.186	KG	US Dollar
12	28030010	'Carbon Black used in rubber applications'*	Any	Thailand	Any	Any	0.186	KG	US Dollar

* Note: Thermal Black and Carbon Black grade meant for semi conductive compound applications are excluded from the scope of the product under consideration

U. Further Procedures

132. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs Authority under the Customs Act, 1962 and all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

133. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. S. DEEPAK, Designated Authority